Machine Translated by Google

THE HINDU

असमंजस की भीड़ चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में मंथन को शांत कर सकते हैं 20

नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज होने के साथ ही राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों का मिश्रण

ए फोकस में है। राज्य में व्यक्तित्व संघर्ष और नेताओं और बाहरी लोगों के वर्गीय हित भी खेल में हैं, जिसने पांच साल पहले हुए पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से काफी राजनीतिक मंथन देखा है। प्रमुख राजनीतिक अभिनेता नए परिदृश्य को समझने और इसे अपने लाभ के लिए आकार देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मुंबई में द हिंदू के सम्मेलन में स्पष्ट था, जिसने इस सप्ताह उन्हें एक साथ इकट्ठा किया था। जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस राष्ट्रीय विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, वहीं क्षेत्रीय दल, विशेष रूप से शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो गुट, क्षेत्रीय मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

शुक्रवार को अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और कांग्रेस पर पाकिस्तान के विचारों को दोहराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, जिसकी मौजूदा राजनीति का केंद्रीय हिस्सा देशव्यापी जाति जनगणना की मांग है, जाति विभाजन पैदा कर रही है। सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के बीच प्रतिस्पर्धात्मक कल्याणवाद चल रहा है।

शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया है कि भाजपा विकास परियोजनाओं और निजी निवेश में राज्य के हितों को कमजोर कर रही है।

2024 के आम चुनाव में एमवीए की बढ़त काफी हद तक जाति-आधारित आरक्षण और संविधान की रक्षा जैसे राष्ट्रीय आख्यान पर आधारित थी। विधानसभा चुनाव में 288 सीटों पर चुनाव होने हैं और भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति को राष्ट्रीय आख्यान और जमीनी स्तर पर प्रचार करने की क्षमता का लाभ है। जातिगत गतिशीलता भी अलग-अलग तरीके से सामने आ सकती है। एमवीए को मराठा-प्रभुत्व वाले मंच के रूप में देखा जाता है, जबकि भाजपा के पास समुदायों के व्यापक गठबंधन को समायोजित करने की गुंजाइश है। सभी दल महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले और बाबासाहेब अंबेडकर का हवाला दे रहे हैं, लेकिन अपने-अपने तरीके से। भाजपा का अभियान मराठा वर्चस्व को चुनौती देकर और हिंदू एकता का जोरदार नारा देकर जातिगत न्याय को छूता है। पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में पेश कर रही है, जबकि उसके साथी अजित पवार ने धर्मनिरपेक्षता के प्रति निष्ठा को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में घोषित किया है।

क्षेत्रवाद की अपील एक दोधारी तलवार है क्योंकि महाराष्ट्र में कई राज्यों से प्रवासी आबादी रहती है। बदलती जनसांख्यिकी आने वाले दशकों में महाराष्ट्र की राजनीति को नया आकार दे सकती है। राजनीति दो विरोधी गठबंधनों में छह प्रमुख दलों में विभाजित है।

इसके अलावा, सभी दलों के कई बागी उम्मीदवार भी मैदान में हैं। चल रहा चुनाव प्रचार भ्रम और विरोधाभासों का प्रतिबिम्ब है; परिणाम इस उलझन को शांत कर सकते हैं।

मूसी की सफाई

'पुनरोद्धार योजना' गंभीर प्रदूषण के मुद्दे से दूर है

2023 विधानसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद, तेलंगाना के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने लंदन के टेम्स रिवरफ्रंट की नकल करने के प्रयास में, हैदराबाद के मूसी रिवरफ्रंट को बहुमंजिला इमारतों, प्रो-मेनेड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कई पुलों के साथ पुनर्विकास करने की महत्वाकांक्षी योजना का प्रस्ताव रखा था। लेकिन चेन्नई के कूम, कोलकाता के हुगली और दिल्ली की यमुना की तरह, मूसी उस जगह से होकर बहती है जो कभी हैदराबाद का दिल हुआ करता था; शहरी फैलाव का बदसूरत केंद्र। भारत के शहरी क्षेत्रों और वास्तव में वैश्विक स्तर की अधिकांश नदियों की तरह, मूसी लंबे समय से शहर का गंदा नाला रही है, जो प्रतिदिन करीब 2000 मिलियन लीटर सीवेज ले जाती है, जिसमें से 60 प्रतिशत से अधिक अनुपचारित है। मूसी में बड़ी मात्रा में औद्योगिक अपशिष्ट भी गिरते हैं, फिर भी, नदी के किनारे लगभग एक लाख लोग रहते हैं, उनमें से कुछ सूखी नदी के किनारे पर रहते हैं और कुछ अन्य मैदानों पर रहते हैं, जिन्हें ब्यूर ज़ोन कहा जाता है जो नदी के दोनों ओर लगभग 50 मीटर तक फैला हुआ है। वे पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं। और नीचे की ओर रहने वाले कई लोग खेती के लिए नदी पर निर्भर हैं।

इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब सरकार ने १ अक्टूबर को पुराने शहर कहे जाने वाले इलाके — हैदराबाद का वह हिस्सा जहाँ प्रतिष्ठित चारमीनार स्थित है — में १५,००० से अधिक संरचनाओं, जिनमें ज्यादातर घर थे, को ध्वस्त करना शुरू किया, तो श्री रेड्डी को बेदखल लोगों से किसी भी तरह के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यह इलाका शहर के कई ब्लू-कॉलर कर्मचारियों — कूड़ा बीनने वालों, संरक्षण और निर्माण श्रमिकों का घर है, जिनमें से कई के पास लंबे समय से जमीन के मालिकाना हक, बिजली कनेक्शन हैं और वे कर भी दे रहे हैं। सरकार ने बेदखल लोगों के लिए ऊंची इमारतों की पुनर्वास योजना का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ये दूरदराज के स्थानों पर थीं, जिससे आजीविका प्रभावित हो रही थी। भारत में यह कोई नई घटना नहीं है। २००४ में सुनामी के बाद चेन्नई में यह देखा गया था, जब सरकार लेकिन इससे पहले भी चेन्नई से होकर गुजरने वाली अड्यार नदी के किनारे रहने वालों को बेदखल करने की कोशिशें की गई हैं। हालांकि, मूसी सहित ऐसी सौंदर्यीकरण योजनाओं के साथ समस्या यह है कि उन्हें उन लोगों से परामर्श किए बिना क्रियान्वित किया जाता है जो सबसे अधिक प्रभावित होंगे। जबकि श्री रेड्डी की सरकार कहती है कि ऐसा किया गया था, बेदखल किए गए लोग इससे असहमत हैं। इसके अलावा, 'पुनरुद्धार योजना', जैसा कि सरकार इसे कहना पसंद करती है, एक दिखावटी बदलाव है - आंखों में चुभने वाली चीज इस उम्मीद में गायब हो जाती है कि इसे वाणिज्यिक गतिविधि से गुलजार एक रोमांटिक नदी के किनारे से बदल दिया जाएगा। लेकिन इसने कमरे में मौजूद हाथी को संबोधित नहीं किया है: रासायनिक पदार्थों और अनुपचारित सीवेज से मूसी के प्रदूषण के स्रोतों को स्थायी रूप से खत्म करना।

ब्रिक्स की यात्रा - परिवर्तन के दौरान बढ़ती ताकत

एक साल के भीतर चीजें कैसे बदल जाती हैं ?

राजीव भाटिया

एक प्रतिष्ठित गेटवे पर साथी हाउस, एक पूर्व हाई आयुक्त को दक्षिण अफ्रीका, तथा विदेश नीति पर तीन पुस्तकों के लेखक

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स 2023 शिखर सम्मेलन में केवल एक संक्षिप्त डिजिटल उपस्थिति दर्ज कराई।

जोहान्सबर्ग में, मेजबान दक्षिण अफ्रीका द्वारा यूक्रेन युद्ध से जुड़े आईसीसी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ उन्हें राजनयिक छूट प्रदान करने के निर्णय के बावजूद। इस वर्ष शिखर सम्मेलन के मेजबान और अध्यक्ष के रूप में, श्री पुतिन ने इस कार्यक्रम पर अपना दबदबा बनाए रखा। तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के बारे में खबरों को पीछे धकेल दिया।

अस्तित्व और कायाकल्प रूस के कज़ान में शिखर सम्मेलन (22-24 अक्टूबर, 2024) 2009 में शुरू हुई श्रृंखला का सोलहवां शिखर सम्मेलन था। पहले दो शिखर सम्मेलनों में केवल चार देशों - ब्राजील, रूस, भारत और चीन - ने भाग लिया था।

दक्षिण अफ्रीका 2011 में तीसरे शिखर सम्मेलन में समूह में शामिल हुआ, जिससे इसे अपना वर्तमान नाम, ब्रिक्स मिला। पहले दशक में कई उपलब्धियाँ दर्ज की गईं, लेकिन दूसरे दशक की शुरुआत मुश्किलों से हुई। कोविड-19 के प्रकोप ने चीन को रक्षात्मक बना दिया; फिर जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष ने दो सदस्य-राज्यों के बीच संबंधों को एक नए निम्न स्तर पर ला दिया; अंत में, फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने मॉस्को के उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के साथ टकराव को जन्म दिया। इन सभी ने समूह को कमज़ोर बना दिया।

फिर भी, यह बच गया और कायाकल्प के संकेत दिखाए। 15वें शिखर सम्मेलन के विस्तार पर निर्णय ने पांच नए सदस्यों को जन्म दिया: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, मिस्र और इथियोपिया। श्री पुतिन द्वारा यह खुलासा कि 34 और देश समूह में शामिल होने के इच्छुक हैं, यह दर्शाता है कि ब्रिक्स ऊपर की ओर बढ़ रहा है।

शिखर सम्मेलन के बाद, रूस का अनुमान था कि यह समूह 'वैश्विक बहुमत' का प्रतिनिधित्व करता है।

इस संक्रमण पथ को ध्यान में रखना होगा कज़ान शिखर सम्मेलन के परिणामों और दुनिया के लिए उनके व्यापक निहितार्थों का आकलन करते हुए। ब्रिक्स एक नई विश्व व्यवस्था बनाने का प्रयास नहीं करता है। यह केवल वर्तमान व्यवस्था में सुधार करना चाहता है ताकि यह सभी के लिए काम करे। समूह "ब्रिक्स भावना" से प्रेरित है, जो आठ विशिष्ट विशेषताओं से ओतप्रोत है: आपसी सम्मान और समझ; संप्रभु समानता; एकजुटता; लोकतंत्र; खुलापन; समावेशिता; सहयोग और आम सहमति। यह तीन कार्यक्षेत्रों के तहत अंतर-ब्रिक्स सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है: राजनीतिक और सुरक्षा; आर्थिक और वित्तीय, और सांस्कृतिक और लोगों से लोगों का सहयोग।

ब्रिक्स, जो शुरू में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह था, अब मुख्य रूप से उभरते बाजारों और विकासशील देशों (ईएमडीसी) के लिए एक मंच है। यह पूर्व और दक्षिण का संयुक्त समूह है, जो वैश्विक उत्तर के साथ जुड़ा हुआ है।

ब्रिक्स के भीतर पश्चिम विरोधी प्रवृत्तियाँ स्पष्ट हैं, लेकिन इसके उदारवादी सदस्य अपने गैर-पश्चिमी रुझान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार के लिए जोर देते हुए, समूह ने जोहान्सबर्ग में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों की आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए एक सावधानीपूर्वक सूत्र तैयार किया, जिसमें "ब्रिक्स देश" (अर्थात भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका) संयुक्त राष्ट्र में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आकांक्षाएं शामिल हैं, जिसमें इसकी सुरक्षा परिषद भी शामिल है। कज़ान में यह अपरिवर्तित रहा; तीनों आकांक्षियों के पक्ष में कोई और सुधार दर्ज नहीं किया गया। किसी भी तरह की उम्मीद नहीं थी क्योंकि इस सूत्र से आगे जाने के लिए चीन की अनिच्छा एक खुला रहस्य है।

समूह का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व था एकतरफा आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म करने का आह्वान किया गया है। यह उन्हें एकतरफा उपायों के रूप में दर्शाता है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत हैं और मानवाधिकारों के लिए दूरगामी परिणाम हैं।

शिखर सम्मेलन में शांति और सुरक्षा से संबंधित पहले शिखर सम्मेलन में पश्चिम एशिया में संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके लिए घोषणापत्र में कई पैराग्राफ समर्पित किए गए। पैराग्राफ 30 में हमास द्वारा 7 अक्टूबर को किए गए आतंकवादी हमले का कोई संदर्भ दिए बिना इजरायल की कार्रवाइयों की तीखी आलोचना की गई है। समूह ने तत्काल और व्यापक युद्धविराम, सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई और एक स्वतंत्र 'फिलिस्तीन राज्य' की स्थापना का आह्वान किया है। इजरायल, जिसका इस क्षेत्र पर सैन्य प्रभुत्व जारी है, प्रभावित नहीं हुआ। इसकी प्रतिक्रिया ब्रिक्स के सदस्य ईरान पर सीधे हवाई हमले के रूप में आई।

रूस ब्रिक्स का अध्यक्ष है, इस समूह में... यूक्रेन में जारी युद्ध के बारे में बहुत कम कहा गया। सदस्य अपनी राष्ट्रीय स्थिति को दोहराने और बातचीत और कूटनीति के माध्यम से युद्ध को समाप्त करने का आह्वान करने से संतुष्ट थे, जबकि संघर्षों के "मूल कारणों" को संबोधित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते थे।

आर्थिक और वित्तीय सहयोग के दूसरे चरण में, साझा मुद्रा मुद्दे पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। लिया गया निर्णय अपेक्षित दिशा में था। ब्रिक्स देशों और उनके व्यापारिक भागीदारों के बीच वित्तीय लेन-देन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को और अधिक सुगम बनाया जाएगा। हालांकि, गहन वित्तीय और बैंकिंग सहयोग के मुद्दे पर सदस्य-राज्यों के वित्त मंत्रालयों द्वारा अध्ययन जारी रहेगा।

> अब यह अहसास हो रहा है कि सदस्यता में वृद्धि से इस बहुपक्षीय समूह के प्रभाव को बढ़ाने की क्षमता है।

सऊदी अरब अभी भी इसमें शामिल होने को लेकर झिझक रहा है ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की शुरुआती उम्मीदों को पूरा नहीं किया है। इसलिए, नेताओं ने बैंक के कामकाज में और सुधार का सुझाव देने और इसे "21वीं सदी में एक नए प्रकार के एमडीबी" के रूप में विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने तक ही खुद को सीमित रखा।

तीसरे वर्टिकल का उद्देश्य मजबूत करना है सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लोगों के बीच आदान-प्रदान। खेल, संस्कृति, संसद, नागरिक समाज, व्यापार और थिंक टैंकों से जुड़े सहयोग से दीर्घकालिक लाभ हो सकता है।

अंत में, समूह के विस्तार से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अंतिम दिन आउटरीच सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 34 देशों ने भाग लिया। दिशा-निर्देशों और मानदंडों को मंजूरी देने के बाद, 'भागीदार राज्य' की एक नई श्रेणी बनाई गई। समूह में भागीदार राज्यों के रूप में शामिल होने के लिए तेरह देशों को आमंत्रित किया गया है। लैटिन अमेरिका: क्यूबा और बोलीविया; यूरेशिया: बेलारूस और तुर्किये; अफ्रीका: अल्जीरिया, नाइजीरिया और युगांडा; दक्षिण पूर्व एशिया: इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम; और मध्य एशिया: कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। स्पष्ट रूप से, तीसरा विस्तार दुनिया की आबादी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सकल घरेलू उत्पाद में ब्रिक्स परिवार की हिस्सेदारी को और बढ़ाएगा।

अभी से लेकर 2025 में ब्राज़ील में होने वाले अगले शिखर सम्मेलन तक, इनमें से ज़्यादातर देशों को भागीदार के तौर पर शामिल किया जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि वे जल्दी से जल्दी पूर्ण सदस्य बनने की मांग करेंगे। इसलिए, संक्रमण कुछ और समय तक जारी रह सकता है।

भारत के नजरिए से भारत के नजरिए से , ब्रिक्स आज शीर्ष छह बहुपक्षीय समूहों में शामिल है- जी-20, क्वाड, ब्रिक्स, बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल), जी-7 (जहां भारत को लगभग स्थायी अतिथि का दर्जा प्राप्त है) और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)। ब्रिक्स भारत को दुनिया में बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देने, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का प्रयोग करने, रूस के साथ अपने संबंधों को गहरा करने और वैश्विक दक्षिण के हितों और एजेंडे की प्रभावी ढंग से वकालत करने में मदद करता है। इसके अलावा, नवीनतम शिखर सम्मेलन ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लगभग पांच वर्षों में पहली बैठक के लिए एक उपयोगी मंच के रूप में कार्य किया। द्विपक्षीय वार्ता के परिणामस्वरूप सीमा पर गश्त व्यवस्था और विघटन पर एक समझौता हुआ। इसलिए, शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित इस बैठक ने नई दिल्ली और बीजिंग के बीच मेल-मिलाप की शुरुआत की।

भारत इस बात को बहुत महत्व देता है ब्रिक्स को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक प्रभावी साधन बनाना। इस राष्ट्र ने इस दिशा में एक ठोस योगदान दिया है और ऐसा करना जारी रखने के लिए उत्सुक है। विस्तार पर प्रारंभिक सावधानी अब एक शांत गणना द्वारा प्रतिस्थापित की गई है कि बढ़ी हुई सदस्यता, यदि ठीक से संभाली जाए, तो इस बहुपक्षीय समूह के प्रभाव को बढ़ाएगी। सबसे बढ़कर, ब्रिक्स भारत को पश्चिम और पूर्व के बीच और उत्तर और दक्षिण के बीच एक सेतु के रूप में काम करने की अनुमति देता है, इस प्रकार आज नई दिल्ली को एक भू-राजनीतिक मधुर स्थान में बदल देता है।

स्वच्छ तकनीक और वैश्विक सहयोग के साथ ठंडा रहना

मैं तेजी से गर्म हो रही दुनिया हूँ, ठंडी नहीं

ज़ेरिन ओशो

भारत के निदेशक कार्यक्रम में संस्थान के लिए शासन एवं टिकाऊ विकास (आईजीएसडी)

यह महज एक विलासिता नहीं बल्कि एक आवश्यकता है, खासकर कमजोर आबादी के लिए।

स्वच्छ ऊर्जा और शीतलन समाधानों पर सहयोग जलवायु संकट को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 21 सितंबर, 2024 को, क्वाड राष्ट्रों (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका) ने विलमिंगटन घोषणा जारी की, जो विशेष रूप से उच्च दक्षता वाले शीतलन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, स्थायी ऊर्जा समाधानों के लिए क्वाड की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह भारत और अमेरिका के पहले के संयुक्त बयान के अनुरूप है, जिसमें स्वच्छ शीतलन प्रौद्योगिकियों पर विशेष जोर देते हुए लचीली और सुरक्षित वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए एक रोडमैप का विवरण दिया गया था। दोनों बयान वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में किफायती और ऊर्जा-कुशल शीतलन प्रणालियों को तैनात करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

इन प्रयासों में भारत का नेतृत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्वाड की स्वच्छ ऊर्जा पहल के हिस्से के रूप में, भारत ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सौर और शीतलन बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश करने का संकल्प लिया है।

उच्च दक्षता वाले एयर कंडीशनरों और सीलिंग पंखों के लिए विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने की अमेरिका और भारत की संयुक्त योजना के साथ, ये विकास शीतलन प्रणालियों के जलवायु प्रभाव को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकते हैं।

शीतलन से संबंधित उत्सर्जन इन अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की व्यापक प्रासंगिकता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इसके किगाली संशोधन (2016) के लेंस के माध्यम से देखी जा सकती है, जिसने पहले से ही शीतलन से संबंधित उत्सर्जन पर सामूहिक वैश्विक कार्रवाई के लिए एक मिसाल कायम की है। जैसे-जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है, शीतलन की बढ़ती मांग दुनिया के लिए इन रूपरेखाओं के सबक को अपनाना अनिवार्य बनाती है, जिससे हानिकारक उत्सर्जन को कम किया जा सके और साथ ही टिकाऊ विकल्पों की ओर संक्रमण हो सके।

किगाली संशोधन ने इसके दायरे को बढ़ा दिया लक्ष्य हाइड्रोयूरोकार्बन (HFCs), शीतलन उपकरणों में उपयोग की जाने वाली शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें। बायाँ अगर इसे रोका न जाए, तो HFCs 2100 तक 0.52°C तापमान वृद्धि में योगदान दे सकते हैं। किगाली संशोधन के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए HFC चरण-डाउन को ऊर्जा दक्षता सुधारों के साथ संरेखित करना आवश्यक है। अधिक कुशल शीतलन प्रणालियाँ बिजली की खपत में कटौती करके कुल ग्रीनहाउस गैस कटौती का लगभग दो-तिहाई हिस्सा प्रदान कर सकती हैं। इससे उत्सर्जन में कमी आएगी, जीवाश्म ईंधन बिजली संयंत्रों से वायु प्रदूषण कम होगा, और निर्माताओं और उपभोक्ताओं के लिए लागत में बचत होगी।

जलवायु परिवर्तन ने शीतलन से संबंधित दो महत्वपूर्ण खतरों को बढ़ा दिया है: जीवाश्म ईंधन द्वारा संचालित अकुशल एयर-कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन सिस्टम से अप्रत्यक्ष उत्सर्जन, और हानिकारक रेफ्रिजरेंट से प्रत्यक्ष उत्सर्जन। हालाँकि, कई देशों में अभी भी एकीकृत ऊर्जा दक्षता और रेफ्रिजरेंट मानकों का अभाव है।

जलवायु-अनुकूल रेफ्रिजरेंट्स का उपयोग करने वाले उच्च-दक्षता वाले एयर कंडीशनर उपलब्ध हैं, लेकिन पुराने रेफ्रिजरेंट्स का उपयोग करने वाले अकुशल मॉडल अभी भी कई बाजारों पर हावी हैं। मजबूत विनियमन के बिना, विकासशील देशों में इन अकुशल उपकरणों के डंपिंग ग्राउंड बनने का जोखिम है, जिससे जलवायु और ऊर्जा संबंधी चुनौतियाँ और बढ़ जाएँगी।

मिशन-मोड दृष्टिकोण अपनाते हुए 2024 में, भारत के कुछ हिस्सों में 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान का अनुभव हुआ, जिससे थर्मल आराम सुनिश्चित करने, भोजन, चिकित्सा आपूर्ति और औद्योगिक प्रक्रियाओं को संरक्षित करने के लिए शीतलन की आवश्यकता पर बल मिला। भारत, सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील देशों में से एक है, जो लाखों लोगों को खतरे में डालने वाली तेजी से गंभीर गर्मी की लहरों का सामना कर रहा है। 2030 तक, अनुमान है कि 160 मिलियन से 200 मिलियन भारतीय सालाना घातक गर्मी की लहरों का सामना कर सकते हैं। देश का कार्यबल, अत्यधिक गर्मी के संपर्क में है, जिससे उत्पादकता, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण गिरावट का खतरा है। कूलिंग की मांग बढ़ने की उम्मीद है, 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हर डिग्री के लिए एयर कंडीशनर की बिक्री 16% बढ़ जाती है। 2050 तक, भारत में दुनिया की सबसे अधिक कूलिंग की मांग हो सकती है, जिसमें 1.14 बिलियन से अधिक एयर कंडीशनर उपयोग में होंगे।

> स्वच्छ ऊर्जा और शीतलन समाधान पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जलवायु संकट से निपटने में एक और महत्वपूर्ण कदम है

भारत ने 2021 में किगाली संशोधन को मंजूरी दी, जिसके तहत 2047 तक एचएफसी को 85% तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई गई। भारत कूलिंग एक्शन प्लान (आईसीएपी) का लक्ष्य है शीतलन की मांग में 20%-25% की कमी, ऊर्जा खपत में 25-40% की कमी, तथा कम-ग्लोबल वार्मिंग क्षमता (GWP) वाले रेफ्रिजरेंट्स की ओर बदलाव, जलवायु-अनुकूल शीतलन में नेतृत्व का प्रदर्शन। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक मिशन-मोड दृष्टिकोण की आवश्यकता है। संधारणीय शीतलन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के लिए केंद्रित नेतृत्व, अंतर-क्षेत्रीय सहयोग और मंत्रालयों में समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी। एक अंतर-मंत्रालयी कार्य समूह की स्थापना, एक लॉन्च इवेंट की योजना बनाना और एक प्रारंभिक बजट आवंटित करना आवश्यक है। दीर्घकालिक सफलता के लिए राष्ट्रीय क्षमता-निर्माण पहल और समर्पित बजट लाइनों का पालन किया जाना चाहिए।

COP29 और COP28 की गति स्वच्छ ऊर्जा शीतलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ उत्साहजनक हैं, लेकिन प्रौद्योगिकियाँ सस्ती बनी रहनी चाहिए। अमेरिका-भारत साझेदारी और क्वाड की पहल उच्च दक्षता वाले शीतलन प्रणालियों की तैनाती और स्थानीय विनिर्माण पर जोर देती है। चुनौती समान पहुँच सुनिश्चित करने में है, विशेष रूप से विकासशील क्षेत्रों में जहाँ शीतलन की आवश्यकता सबसे अधिक है। बढ़ते वैश्विक तापमान के लिए कमज़ोर बिजली ग्रिडों पर दबाव डाले बिना या कमज़ोर आबादी को पीछे छोड़े बिना ऊर्जा-कुशल समाधानों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

शीतलन चुनौतियों के प्रति भारत का सक्रिय दृष्टिकोण, विशेष रूप से ICAP के माध्यम से, इसे संधारणीय शीतलन में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है। देश जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का नेतृत्व करते हुए अपनी आबादी को गर्मी से बचा सकता है, जिससे सभी के लिए तापीय आराम सुनिश्चित हो सके।

सीओपी28 (दुबई) में 63 देशों ने 2050 तक शीतलन उत्सर्जन को 68% तक कम करने की प्रतिज्ञा की। वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा, हालांकि गैर-बाध्यकारी है, 2050 तक 3.5 बिलियन लोगों को शीतलन सुविधा प्रदान कर सकती है और ऊर्जा लागत में 17 ट्रिलियन डॉलर की बचत कर सकती है।

हालांकि, इसे हकीकत बनाने के लिए वैश्विक कार्रवाई में तेजी लानी होगी। COP29 को कूलिंग प्रतिबद्धताओं का विस्तार करके COP28 की गति को बनाए रखना चाहिए। इसमें ग्लोबल कूलिंग प्लेज में भागीदारी बढ़ाना और विभिन्न क्षेत्रों और देशों में भागीदारी बढ़ाना शामिल है।

संपादक के नाम चिठी

वायु गुणवत्ता प्रबंधन इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ उत्तरी राज्यों में किसानों द्वारा 'पराली जलाने' से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित इन क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह भी एक ऐसी स्थिति है जहाँ भारत के सर्वोच्च न्यायालय को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बार-बार आदेश जारी करने पड़ते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि न्यायालय का इरादा केवल जलाने वालों पर जुर्माना लगाकर समस्या का समाधान करना है या नहीं। इससे यह भी लगता है कि किसानों को दंडित करने के अलावा कोई वैज्ञानिक विकल्प नहीं है। कृषि वैज्ञानिकों और सरकार में योजनाकारों को ही पराली जलाने के अलावा अन्य तरीके खोजने होंगे। पराली से होने वाले नुकसान की भरपाई, किसानों के वित्तीय हितों की रक्षा, और अंततः आम जनता के स्वास्थ्य हितों की रक्षा।

पीआरवी राजा,
पंडालम, केरल

ओलंपिक खेलों की बोली

2036 विश्व कप की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी

ओलंपिक अभी भी अपने अंतिम चरण में है शुरुआती दौर में, लेकिन देश की संभावनाओं को प्रभावित करने वाले कई कारक हो सकते हैं। खेल के बुनियादी ढांचे में भारत का निवेश अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी के लिए उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा। विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने के लिए फ्रांस जैसे अन्य देशों के साथ सहयोग भी एक सकारात्मक प्रभाव है। विशिष्ट विषयों को शामिल करने का प्रस्ताव मददगार हो सकता है।

कोल्लुरु राजू,
काकीनाडा, आंध्र प्रदेश

भारत की रुचि की अभिव्यक्ति 2047 तक 'विकसित' बनने की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वागत योग्य लग सकती है। हालांकि, शहरी और परिवहन में निवेश को छोड़कर भारी लागत खेलों के आयोजन के बाद बुनियादी ढांचे की कमी और खाली पड़े और उग आए मैदानों की भरमार, खराब दीर्घकालिक योजना के कारण भयावह वित्तीय कुप्रबंधन की याद दिलाती है। भारत इस समय इतना बड़ा खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता।

डॉ. थॉमस पालोकारेन, वेल्लोर,
तमिलनाडु

Machine Translated by Google

मोहित पांडे के परिवार और शुभचिंतकों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया और उनकी मौत के लिए मुआवजे और पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फोटो: विशेष व्यवस्था विशेष व्यवस्था

कानून के नाम पर

अक्टूबर में, यूपी में कम से कम दो परिवारों ने आरोप लगाया कि उनके एक सदस्य की हिरासत में यातना के कारण मौत हो गई। पिछले कुछ सालों से सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने पर जोर दे रही है। मयंक कुमार की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पुलिस का हौसला बढ़ा है और कथित तौर पर हिरासत में यातना और मौतें हो रही हैं।

टी आपेश्वरी देवी उस रात का वर्णन करती हैं 25 अक्टूबर को दुख और गुस्से के साथ। उनके बेटे मोहित पांडे (32) का उनके पड़ोसी आदेश कुमार के साथ कुछ हजार रुपयों को लेकर मामूली विवाद हो गया था।

शाम 7 बजे पुलिस पहुंची और मोहित को हिरासत में ले लिया। लखनऊ के चिनहट पुलिस थाने में ले जाया गया।

मोहित, स्कूल के निर्माता और आपूर्तिकर्ता वर्दी, 'उल्लंघन के लिए हिरासत में लिया गया था 'शांति' भारतीय न्याय की धारा 352 के तहत पुलिस के अनुसार, साहिता (बीएनएस) ने बताया कि जब उसकी हत्या की गई तो वह फरार हो गया। भाई, शोभा राम पांडे, पुलिस के पास गए मोहित के बारे में पूछताछ करने के लिए जब पुलिस थाने पहुंची तो उसे भी नशे में होने के कारण हिरासत में ले लिया गया।

अगले दिन, एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जो कथित तौर पर चिनहट पुलिस स्टेशन के लॉकअप में पेश हुआ सार्वजनिक डोमेन। इसमें एक आदमी दिखाया गया है, जो रिश्तेदारों मोहित फर्श पर पड़ा हुआ है। सात अन्य उसके भाई समेत अन्य कैदी उसके कंधे पर हाथ फेरते और मदद के लिए चिल्लाते देखे गए। 77 सेकंड के वीडियो के अंत में, कैदी विनती करते हैं पुलिस से मदद मांगी और शोभा राम ने एक बोतल थमा दी अपने भाई को पानी पिलाया।

उस दिन बाद में देवी का फ़ोन बजा. फोन करने वाले ने मुझे बताया कि मोहित को भेज दिया गया है राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनके स्वास्थ्य की स्थिति की समीक्षा की गई। हालत खराब हो गई थी," वह कहती हैं, उनकी आंखें भर आती हैं देवी अस्पताल पहुंचीं तो उन्हें पता चला कि कि उसका बेटा अब नहीं रहा।

मेडिकल स्टाफ और पुलिस ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक विक्रम सिंह, ने पुष्टि की थी कि मोहित को लाया गया था अपराह्न 3 बजे के आसपास मृत देवी हैरान रह गईं। "उन्होंने उसे मार डाला, और क्या? इतनी छोटी सी बात पर," वह कहती हैं।

मोहित के परिवार में उनकी मां, पत्नी और तीन बच्चों की मौत हो गई। उनके परिवार ने अस्पताल के बाहर दो दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया, उनका दावा था कि पुलिस ने उसकी पिटाई की थी, जिसके कारण उसे मौत। उन्होंने कहा कि पुलिस उसे अस्पताल ले गई ताकि हिरासत में उसे जो यातनाएं झेलनी पड़ीं, वे कम हो जाएं कभी पता नहीं चलेगा.

शोभा राम, जिसे मोहित की हत्या के दिन ही रिहा कर दिया गया था। मर गया, पुलिस स्टेशन को "lthy" के रूप में वर्णित करता है और कहते हैं कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। "जब मैंने पूछा पुलिस ने हमें पानी नहीं दिया। हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। मोहित की तबियत खराब हो गई जिससे वह याद करते हैं, "रात में एक कार में आग लग गई।" शोभा राम का आरोप है कि उनकी कार में आग लग गई थी। भाई की हिरासत में यातना के कारण मृत्यु हो गई।

देवी का दावा है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पड़ोसी, आदेश। "यह इन- के कारण था आदेश के चाचा एक राजनीतिक नेता हैं, उनका कहना है कि मोहित को बहुत यातनाएं सहनी पड़ीं," उन्होंने आरोप लगाया।

उत्तर प्रदेश के लिए एक संदिग्ध गौरव

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, हिरासत में मौतें हिरासत में रहते हुए व्यक्तियों की मृत्यु का उल्लेख करें किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी या न्यायालय की ओर से। वे मानव अधिकारों के सबसे गंभीर उल्लंघनों में से एक हैं कानून के शासन द्वारा शासित समाजों में अधिकार। ऐसी मौतें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति के संबंध के दौरान घटित घटनाओं से जुड़ी हो सकती हैं।

सरकार द्वारा साझा किये गए आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 में लोकसभा में उत्तर प्रदेश हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर रहा 2021-22 में 2,544 में से 501 मौतें दर्ज की गईं देश भर में सबसे ज्यादा मौतें पश्चिम बंगाल में (257 मौतें) हुईं।

"हिरासत में हिंसा के कई मामले दब जाते हैं। केवल वे मामले ही अदालत में पहुंचते हैं सुर्खियों में आना या मीडिया द्वारा जांचे जाने से

> उन्होंने हत्या कर दी उसके लिए, और उसके लिए पर क्या ऐसा छोटी सी बात।
>
> तपेश्वरी देवी
> मोहित की माँ पांडे

कार्रवाई या सज़ा," गजेंद्र सिंह या-दव, एक यातना-विरोधी कार्यकर्ता और वकील, जिन्होंने नेतृत्व किया, कहते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत मोहित की मौत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) से जवाब मांगा है।

उदाहरण के लिए, जून में सीतापुर की एक अदालत ने तीन पुलिस कांस्टेबलों को हिंसा भड़काने का दोषी ठहराया था। आत्महत्या और अवैध हिरासत के आरोप में 10 साल की सजा उनमें से प्रत्येक को 1 वर्ष का कठोर कारावास हिरासत से संबंधित दो दशक पुराने मामले में एक दलित व्यक्ति की मौत।

मोहित के परिवार ने चीफ के घर का दौरा किया 28 अक्टूबर को मंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पीड़ितों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि, आवास, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करें।

सरकारी योजनाओं के बारे में बात करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अराजकता का माहौल है। समाजवादी पार्टी की सरकार है और वह ऐसा करेंगे। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया मोहित की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी कठोर सजा का सामना करना पड़ेगा।

बाद में देवी ने अश्विनी कुमार चतुर्वेदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

चिनहट का स्टेशन हाउस अधिकारी; आदेश; और धारा 103 के तहत अज्ञात पुलिस कर्मियों पर मामला दर्ज (1) (हत्या के आरोपों से संबंधित) और बीएनएस की धारा 61(2) (आपराधिक साजिश से संबंधित)।

मोहित से पहले अमन था

28 वर्षीय अमन गौतम बिजली का काम करते थे। दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं। उनकी बहन सुधा गौतम को 11 अक्टूबर की वह रात याद है जब वह विकास नगर सेक्टर 8 स्थित अंबेडकर पार्क में लखनऊ के एक मोहल्ले में उसी रात उनकी मृत्यु हो गई।

यूपी पुलिस ने एक बयान में कहा कि जुआ गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद वे यहां पहुंचे। पार्क में घुसकर उसे हिरासत में ले लिया गया। उनका दावा है कि जब वह स्टेशन जा रहा था, अमन की हालत बिगड़ने लगी, उसे लोहिया अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

"पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।" वैन। उन्हें उन लोगों ने बुरी तरह पीटा," सुधा अल-

उन्होंने इस घटना को एक "षड्यंत्र" बताया, क्योंकि हिरासत में लिए गए एक अन्य व्यक्ति सोनू बंसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

'जब हमने विकास नगर पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया तो हमें लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी ने भी हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा, "आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए।" उन्होंने मांग की कि अधिकारियों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश से संबंधित मामला दर्ज किया जाना चाहिए। हालांकि, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। धारा 105 (दोषी) के तहत मामला दर्ज किया गया बीएनएस की हत्या (हत्या के बराबर न आने वाली हत्या) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(डी) और 3(2)(वी) जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत मामला दर्ज किया गया।

परिवार का आरोप है कि चिनहट में रहते हुए मृत्यु के मामले में सरकार ने मुआवजा, आवास, मुफ्त शिक्षा और सरकारी सहायता प्रदान की मोहित के परिवार को कोई लाभ नहीं हुआ, उन्होंने बहुत कम मदद की अमन के मामले में बार-बार आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सुधा कहती हैं, "केवल लखनऊ पूर्व के विधायक ओपी श्रीवास्तव ने 'मदद' के तौर पर ₹1 लाख दिए।" हम कहाँ जाएँगे? हम दलित हैं। तो, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है वह कहती है, "मुझे क्या मिलेगा?" सुधा परेशान है लेकिन उसे चिंता भी है अमन की चार साल की बेटी के बारे में तो वह सबसे ज्यादा चिंतित थी।

असफलताओं की टोकरी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मोहम्मद हैदर रिज़वी ने कहा, उन्होंने कहा कि उच्च संख्या के कई कारण हैं यूपी में हिरासत में मौतों के मुख्य कारण हैं: "अपराध की जांच करने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता की कमी, अपने वरिष्ठों से उन पर पड़ने वाला दबाव और उन्हें मिलने वाली धमकियां

ऐसा करने पर उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा या पद से हटा दिया जाएगा 'परिणाम दिखाना' नहीं।" उनका तर्क है कि दूसरा कारण "मानवाधिकार संगठनों द्वारा इस संकट से निपटने में विफलता" है।

अत्याचार विरोधी कार्यकर्ता यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एक विशेष कानून बनाया गया है। सरकार ने पुलिस को और सशक्त बना दिया है कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। उनका मानना है कि इससे न्यायेतर हिंसा को बढ़ावा मिला है। उदाहरण के लिए, सत्ता में आने के कुछ ही महीनों बाद 2017 में आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उनकी सरकार उन लोगों के घरों को भी बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा जो महिलाओं के खिलाफ अपराध को बढ़ावा देने वाला माना जाता है या समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के खिलाफ। उपायों से प्रतिगामी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है यादव कहते हैं, "संदिग्धों से निपटने में पुलिस की भूमिका अहम है।"

झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आदित्यनाथ ने लोगों से वोट देने की अपील की ऐसी सरकार में जो माँ को मिटा देगी, जैसे कोडरमा में, जहाँ रैली आयोजित की गई थी, उनका स्वागत 11 बुलडोजरों द्वारा किया गया।

लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर मोहित की मां तपेश्वरी देवी (बीच में)। फोटो: विशेष व्यवस्था द हिंदू

> उत्तर प्रदेश में कहानी यह है कि राज्य अत्यंत शक्तिशाली और लोगों को कुचल देगा जो गलत काम करते हैं। यह मानसिकता उनमें देखी जाती है पुलिस बल भी
>
> डॉ. साहू
> लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ.

उन्होंने कहा, "2017 से पहले, माँ समूह गर्व के साथ स्वतंत्र रूप से घूमते थे, लेकिन जब से बुलडोजर चलना शुरू हुआ उनके काम से, यहाँ तक कि सबसे कुख्यात लोगों को भी खनन, वन, पशु, संगठित अपराध, शराब और भूमि राज्य से गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गए।"

पीड़ितों के लिए मामले को और अधिक कठिन बनाना उनके परिवार, एनएचआरसी और राज्य मानव संसाधन मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) मुख्य रूप से अनुशंसात्मक प्रकृति के होते हैं। एनएचआरसी और एसएचआरसी न तो मानवाधिकारों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने का अधिकार है और न ही किसी प्रकार की राहत देने का पीड़ितों के लिए उनकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं सरकार पर। "ये समूह बन गए हैं सजावटी संगठन और सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक आश्रय रिजवी का मानना है, "न्यायाधीशों और नौकरशाहों के साथ अन्याय हो रहा है।"

समाजशास्त्रियों का कहना है कि अनियंत्रित सत्ता की संस्कृति कानून प्रवर्तन के भीतर की हिंसा भी एक कारक है। "यूपी में, कहानी यह है कि राज्य अत्यंत शक्तिशाली है और गलत काम करने वालों को कुचल देगा। राज्य में पुलिस बल में यह मानसिकता देखने को मिलती है लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख डीआर साहू कहते हैं।

नियम और कार्यान्वयन का अभाव

हिरासत में हिंसा की घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास में पुलिस हिरासत में मौतों और उत्पीड़न के संबंध में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने एक आदेश जारी किया है। जुलाई में सभी जिलों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे राज्य के पुलिस प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने के लिए जांच की जानी चाहिए इससे पहले कि उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाए; संदिग्ध को पूछताछ के लिए तभी लाया जाना चाहिए जब पुलिस थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी जाए इस बारे में; कि यदि किसी संदिग्ध की तबीयत खराब हो जाती है पुलिस हिरासत में, पूरा घटनाक्रम फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी की जानी चाहिए; उन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ऐसा परिदृश्य; और इसकी केवल जांच ही- पुलिस अधीक्षक या थाना प्रभारी को संदिग्ध से पूछताछ करनी चाहिए।

"लेकिन समस्या नियमों से नहीं है," वे कहते हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने कहा, "यह कार्यान्वयन के साथ है। भारत 142 में से 79वें स्थान पर है।" कानून के शासन सूचकांक 2024. 2015 में यह 57 था. आंकड़े असली तस्वीर बयां करते हैं।'' कानून का शासन सूचकांक हर साल वाशिंगटन स्थित संगठन विश्व न्याय परियोजना द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो विश्व भर में कानून के शासन को आगे बढ़ाने के लिए जागरूकता पैदा करने और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए काम करता है।

कुछ अन्य अपराध-संबंधी मापदंडों पर भी, यूपी का प्रदर्शन निराशाजनक है। ताजा (2022) में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट (एनसीआरबी) के अनुसार, राज्य में सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। महिलाओं के खिलाफ अपराध (बलात्कार जैसे 65,743 मामले) हत्या, अपहरण, बलात्कार के बाद हत्या और सामूहिक हत्या बलात्कार)।

कोई यातना विरोधी कानून नहीं

भारत में यातना के खिलाफ विशेष कानूनों का अभाव है। यातना निवारण विधेयक, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया ई.टी. मोहम्मद बशीर द्वारा लिखित इस पुस्तक का उद्देश्य हिरासत में यातना को रोकना और पीड़ितों को मुआवजा सुनिश्चित करना तथा दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाना है। अधिकारी दंड के लिए उत्तरदायी हैं। "दुख की बात है कि रिज़वी कहते हैं, "इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि यह पारित हो जाएगा।"

बीएनएस के आलोचकों का कहना है कि पुलिस हिरासत में यातना के मामलों की स्वयं जांच करती है, यही कारण है कि ऐसे बहुत कम दोषसिद्धि हैं।

यादव कहते हैं कि वह उस दिन को नहीं भूल सकते जब अजय जौनपुर के एक मजदूर यादव उनसे मिलने आए। प्रयागराज। "वह इतना टूट गया था, वह तैयार था न्याय पाने के लिए अपनी सारी पैतृक जमीन और मवेशी बेच देंगे वह कहते हैं, "यह दुख उनके भाई के लिए है, जिसे पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने के दौरान मार दिया गया।"

मामला फरवरी 2021 का है जब अजय की छोटे भाई कृष्ण यादव उर्फ पुजारी यादव की मृत्यु हो गई। कार्यकर्ता यादव ने इस मामले को आगे बढ़ाया। उच्च न्यायालय से केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है। वे कहते हैं, " जांच से पता चला कि किस तरह से यातनाएं दी जाती थीं मृतक की हत्या की योजना बनाई गई थी। प्रारंभ में, की भूमिका नौ पुलिस कर्मी सामने आते हैं; फिर, और भी पुलिसकर्मी रडार पर आ गए। कई महीनों तक आरोपी गिरफ्तारी वारंट से बच निकला। लेकिन फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वे एक साल से अधिक समय से जेल में हैं।" उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

हालाँकि, यह एक अपवाद है और यह कोई अपवाद नहीं है। 2001 से 2020 के बीच 1,800 से अधिक पूरे भारत में पुलिस हिरासत में लोगों की मौत हो गई, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, केवल 26 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया। एनसीआरबी की भारत में अपराध पर वार्षिक रिपोर्ट।

यद्यपि भारत ने यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं

14 अक्टूबर 1997 से अब तक इसे रेटिंग नहीं दी गयी है।

भारतीय विधि आयोग ने अपनी 113वीं रिपोर्ट में भारतीय विधि अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की थी। साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत यह कहा गया है कि हिरासत में लिए जाने की स्थिति में यदि साक्ष्य उपलब्ध हो तो न्यायालय यह मान सकता है कि चोट पुलिस द्वारा पहुंचाई गई है। उस अवधि के दौरान वह व्यक्ति पुलिस की हिरासत में था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिलीप मामले में के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (1997), न्यायालय ने हिरासत में पूछताछ से संबंधित चिंताओं को दोहराया और पुलिस के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए। इसने पुलिस को थर्ड डिग्री का प्रयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया जांच और पूछताछ के दौरान अपनाए जाने वाले तरीके आरोपी व्यक्तियों की पहचान, पुलिस को प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण देने का आह्वान किया गया तथा बुनियादी मानवीय मूल्यों पर जोर दिया गया।

अमन और मोहित दोनों के परिवार गरीब हैं। सुधा का कहना है कि अमन उनका चौथा भाई है खो दिया है। "मैं सिर्फ़ अपने बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि अपनी भाभी के लिए भी रोती हूँ। उसके पास नौकरी नहीं है। वह कैसे अपना गुजारा करेगी? हमारे जैसे दलितों के लिए यह दुख अंतहीन है," वह कहती हैं। कहते हैं.

mayank.kumar@thehindu.co.in

Machine Translated by Google

thehindu businessline.
शनिवार - 9 नवंबर, 2024

संपत्ति अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से राज्य की असीमित शक्तियों पर अंकुश लगा

मैं संप्रभु शक्ति का एक चौंकाने वाला संशोधन हूँ, सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान के समाजवादी स्वरूप को मौलिक रूप से बदल दिया है। 1950 के दशक की शुरुआत से ही लगातार सरकारों द्वारा इस स्वरूप का अलग-अलग स्तरों पर दोहन किया गया। पीठ के समक्ष मुद्दा 'भौतिक संसाधन' शब्द की व्याख्या और अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) के तहत निजी संपत्ति को इस तरह घोषित करने की शक्ति का था, ताकि इसे राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सके।

अनुच्छेद 39(बी) जो वास्तव में एक निर्देशक सिद्धांत है, कहता है: "राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से वितरित किया जाए कि यह आम भलाई के लिए सर्वोत्तम हो।" न्यायालय ने अब कहा है कि यह एक अनियंत्रित शक्ति नहीं है। इसने न्यायालय की अपनी प्रवृत्ति को भी उलट दिया है, जो 1972 के बाद और अधिक स्पष्ट हो गई, जिसमें निजी संपत्ति के अधिकार को कम करने के लिए सार्वजनिक हित का हवाला दिया गया था।

कुल मिलाकर, सरकारों की अनुचित तरीके से काम करने की शक्ति कम हो गई है और यह ऐसी चीज है जिसके लिए देश को आभारी होना चाहिए। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1970 के दशक के अंत से यह अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं रहा है। इस प्रकार न्यायालय ने खुद को और कार्यपालिका को उस विस्तारित पहुँच से मुक्त कर दिया है जो निष्पक्षता से ज़्यादा विचारधारा पर आधारित थी।

इसका महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता क्योंकि मुख्यधारा के राजनीतिक, आर्थिक और न्यायिक विचारों पर समाजवादी कब्ज़ा होने के बाद से न केवल निजी संपत्ति के बारे में पूरी तरह से टालने योग्य अस्पष्टता रही है, बल्कि अस्पष्ट रूप से परिभाषित सार्वजनिक हित का हवाला देकर राज्य द्वारा असहाय नागरिकों को बेदखल करने का डर भी बना हुआ है। यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ वर्षों में न्यायालय ने खुद कई निर्णयों में इस दृष्टिकोण का विरोध किया है।

लेकिन समस्या यह थी कि संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत राज्य की शक्ति के विस्तार की गुंजाइश हमेशा से थी। इनका इस्तेमाल वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध न्यायाधीशों या यहां तक कि कार्यपालिका को खुश करने के लिए न्यायाधीशों द्वारा किया जा सकता था और किया भी गया। इनसे ऐसे फैसले सामने आए, जिनसे व्याख्या और मिसाल दोनों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई और राज्य की शक्ति का बेधड़क विस्तार हुआ। इसके बावजूद, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सामुदायिक संपत्ति का विचार, या जिसे पश्चिम में 'कॉमन्स' कहा जाता है, दुनिया भर के समाजों में अंतर्निहित रहा है। हालाँकि, समस्या यह रही है कि संप्रभु की प्रवृत्ति नागरिकों को बिना पर्याप्त मुआवज़ा दिए उनकी संपत्ति से वंचित करने की रही है।

हमारे संविधान में चौथा संशोधन

अनिवार्य अधिग्रहण और मुआवज़े के इन मुद्दों पर 1955 में ही विचार किया जा चुका है। हालाँकि, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 31 को राज्य को संपत्ति अधिग्रहण के लिए अधिक लचीलापन देने के लिए कमज़ोर कर दिया गया था। उम्मीद है कि अब अनुच्छेद 39 और संविधान के इसी तरह के प्रावधानों के कारण होने वाली समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में इस फ़ैसले के क्या प्रभाव होंगे, खासकर अगर कार्यपालिका इन प्रभावों को कम करने का फ़ैसला करती है, जैसा कि उसने अतीत में कभी-कभी किया है।

जेब

रविकांत

जलवायु परिवर्तन से जुड़ी विडम्बना यह है कि

'शीर्ष' उत्सर्जन. हवाई यात्रा, स्थानीय परिवहन और सीओपी प्रतिनिधियों के लिए आवास से होने वाला उत्सर्जन चौंका देने वाला है

ईशा दयाल

रॉयटर्स

टी 11-22 नवंबर तक बाकू, अजरबैजान में होने वाले सीओपी29 में देशों द्वारा की गई जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन को रोकने में हुई प्रगति का भी जायजा लिया जाएगा।

हालांकि, इस तरह के बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन की अपनी लागतें हैं, विशेष रूप से अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन - जो कि दुनिया भर में नागरिकों द्वारा अपने दैनिक कार्यों के दौरान पहले से ही उत्सर्जित किए जा रहे कार्बन उत्सर्जन से अधिक है।

हममें से कितने लोगों ने इस पर बारीकी से गौर किया है? क्या आप अपनी हवाई यात्रा के कारण होने वाले कार्बन उत्सर्जन को देखने के लिए अपनी हवाई यात्रा टिकट का उपयोग कर सकते हैं?

यदि यह आपके टिकट पर नहीं है, तो ICAO कार्बन उत्सर्जन कैलकुलेटर (ICEC) (ICAO पर्यावरण) का उपयोग करके देखें।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त इस उपकरण के अनुसार, इस वर्ष के COP29 सम्मेलन में नई दिल्ली से बाकू तक की राउंड-ट्रिप इकोनॉमी क्लास यात्रा के परिणामस्वरूप प्रति यात्री 236 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होगा (हालांकि बिजनेस या प्रथम श्रेणी की यात्रा के लिए उच्च कार्बन पदचिह्न जिम्मेदार माना जाता है)। न्यूयॉर्क (JFK) से इस्तांबुल होते हुए बाकू तक की सबसे कम उड़ान अवधि के लिए, बिजनेस क्लास राउंड ट्रिप के परिणामस्वरूप प्रति यात्री 3,996 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होगा।

इसके अलावा स्थानीय परिवहन और आवास के लिए ऊर्जा के उपयोग से होने वाला उत्सर्जन, तथा खाद्य और पेय पदार्थों और अन्य नाशवान और गैर-पुनर्चक्रणीय उत्पादों के उपभोग से उत्पन्न अपशिष्ट भी इसके लिए ज़िम्मेदार है। UNFCCC ने अपनी रिपोर्ट 'हाउ टू COP' में स्वीकार किया है कि "हरित होना आसान नहीं है" और "सम्मेलन से ग्रीनहाउस गैसों का काफी उत्सर्जन होता है"।

स्थिरता रिपोर्ट

मेजबान देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए सक्रिय कदम उठाएंगे तथा स्थिरता के पहलुओं पर मीडिया या नागरिक समाज संगठनों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के लिए तैयार रहेंगे।

अपनी ओर से, मेजबान देशों ने सी.ओ.पी. आयोजनों के कुछ महीने बाद 'स्थायित्व रिपोर्ट' प्रकाशित की है, जिसमें सम्मेलन के कार्बन पदचिह्न का विवरण दिया गया है।

पिछले COP की तरह, COP29 के लिए भी, आगामी आयोजन को संधारणीय बनाने के उपाय उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए हैं। COP27 में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा से उत्सर्जन 44,103.80 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (CO2e) (COP27 संधारणीयता रिपोर्ट) था, जिसमें दुनिया भर से 46,000 से अधिक प्रतिनिधियों (COP 27 संधारणीयता रिपोर्ट) की मेज़बानी की गई थी (एक टन 1,000 किलोग्राम के बराबर होता है)।

यह देखते हुए कि COP27 का कुल कार्बन फुटप्रिंट 62,695 टन CO2e था, अकेले हवाई यात्रा से कुल कार्बन उत्सर्जन में 70 प्रतिशत से अधिक का योगदान था

इस आयोजन से। COP26 में 38,000 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिसके परिणामस्वरूप कुल कार्बन फुटप्रिंट 131,556 टन CO2e था, (COP 26 संधारणीयता रिपोर्ट) हालांकि आयोजन की संधारणीयता रिपोर्ट में हवाई यात्रा के कारण होने वाले उत्सर्जन की मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है। पिछले साल के COP28 की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है, हालांकि कहा जाता है कि आयोजन से कार्बन उत्सर्जन ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं।

अब, COP29 के लिए बाकू में कितने प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है? 21 अक्टूबर 2024 तक, पंजीकरण पहले ही 32,000 से अधिक हो चुके हैं। कुल अपेक्षित कार्बन उत्सर्जन की सटीक संख्या देना मुश्किल है, क्योंकि न तो उपस्थिति का डेटा अंतिम है, न ही इसे देशों या मूल शहरों में काटा गया है। साथ ही हमारे पास यह डेटा नहीं है कि पंजीकृत प्रतिनिधियों में से कितने वाणिज्यिक एयरलाइनों से उड़ान भरेंगे या निजी जेट का उपयोग करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप और भी अधिक उत्सर्जन होगा।

फिर भी, ये संख्याएँ अतिरिक्त उत्सर्जन के पैमाने को समझने में मदद करती हैं जो किसी भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समय होता है, पहले से हो रहे उत्सर्जन के अतिरिक्त

जहां तक संभव हो, क्यों न व्यक्तिगत बैठकों को आवश्यक बातचीत तक सीमित रखा जाए, या ऑनलाइन विचार-विमर्श का प्रयास किया जाए?

संबंधित गंतव्य तक अन्य विश्वव्यापी यात्राओं के कारण।

बेशक सभी सम्मेलन कार्बन उत्सर्जन को कम करने के भविष्य की दिशा तय नहीं करते, जो विडंबना है कि COP का उद्देश्य है।

मेज़बान देश COP आयोजनों में होने वाले उत्सर्जन और उत्पन्न कचरे को ध्यान में रखते हुए स्थिरता के लिए प्रयास कर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, इलेक्ट्रिक वाहनों और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का उपयोग करने के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए।

फिर भी, तथ्य यह है कि सीओपी आयोजनों से कार्बन उत्सर्जन जारी है, और ये बयान कि ये उत्सर्जन अन्य प्रमाणित हरित कार्यक्रमों से ऋण की खरीद के माध्यम से 'ओसेट' किया जाता है, जो कि इस आयोजन को शून्य-योग खेल के रूप में ग्रीनवाशिंग करने जैसा प्रतीत होता है: जहां सीओपी प्रदूषण करता है, वहीं अन्य कार्यक्रम समतुल्य उत्सर्जन बचाते हैं।

इसके बजाय, क्यों न सकारात्मक परिणाम के लिए प्रयास किया जाए, जहां हर कोई कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करे, तथा हरित कार्यक्रमों के आयोजन का उदाहरण प्रस्तुत करे?

क्यों न एक मानकीकृत कार्बन पदचिह्न मापन और स्थिरता रिपोर्टिंग मानदंड बनाया जाए, जिससे COP आयोजनों में कार्बन उत्सर्जन की वर्ष-दर-वर्ष तुलना की जा सके, तथा कम प्रदूषणकारी 'हरित COPs' की दिशा में काम किया जा सके?

जहाँ तक संभव हो, क्यों न व्यक्तिगत रूप से मिलने-जुलने को आवश्यक बातचीत तक सीमित रखा जाए या ऑनलाइन विचार-विमर्श का प्रयास किया जाए? कोविड महामारी ने हमें वर्चुअल मीटिंग और हाइब्रिड इवेंट के समय-लागत लाभों के बारे में सिखाया है।

जलवायु उपाय

इन उपायों के माध्यम से धन की बचत क्यों न की जाए और इसका उपयोग उन मायावी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में क्यों न किया जाए, जिनका उद्देश्य कम विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और उसके अनुकूल होने में मदद करना है?

कार्बन को नज़रअंदाज़ करने का आदर्श तरीका सी.ओ.पी. की लागत, चाहे वैश्विक वार्षिक उत्सर्जन में उनका योगदान बड़ा हो या छोटा, यह सुनिश्चित करके पूरी की जा सकती है कि बहुपक्षीय तंत्र अपने वादों को पूरा कर रहा है: वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करना और हमारे ग्रह के तापमान में कमी लाने में मदद करना।

दुर्भाग्य से, वैश्विक जलवायु कार्रवाई धीमी रही है, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण निकायों की रिपोर्ट, जिनमें नवीनतम 24 अक्टूबर को जारी की गई यूएनईपी उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2024 है, लगातार हमें प्रलय के दिन की ओर बढ़ती घड़ी की याद दिला रही है। चल रहे युद्धों पर उभरते हुए डेटा और शोध, जिनमें यूएनएफसीसीसी के पक्षकार देश शामिल हैं, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को और बढ़ाने में इन संघर्षों की भूमिका को उजागर करते हैं।

इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सभी विरोधाभासों पर गंभीरता से विचार करे, तथा आगे बढ़ते हुए उपरोक्त सुझावों पर विचार करे - यह ध्यान में रखते हुए कि चरम मौसम की घटनाएं न केवल जीवन और आजीविका पर बल्कि वनस्पतियों और जीव-जंतुओं पर भी गंभीर प्रभाव डाल रही हैं।

लेखक नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) में फेलो हैं। व्यक्त किए गए विचार निजी हैं

वाशिंगटन में आत्म-खोज का समय है

अवैध प्रवास, सामूहिक निर्वासन और गर्भपात पर शोरगुल के बीच हैरिस खेमा आर्थिक पहलू को नजरअंदाज कर सकता है

श्रीधर कृष्णस्वामी

मैं एक से अधिक तरीकों से, अमेरिका में हर तरफ राहत की बात है कि 5 नवंबर का दिन बीत चुका है और डोनाल्ड ट्रम्प अगले राष्ट्रपति होंगे। अंतिम गणना नेवादा और एरिज़ोना के परिणामों का इंतजार कर रही है, लेकिन

291 इलेक्टोरल वोटों के साथ, ट्रम्प बहुत आगे हैं। इसके अलावा, राष्ट्रपति-चुनाव का फ़ोन भी बज रहा है। चाहे वह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस द्वारा चुनाव स्वीकार करना हो या राष्ट्रपति जो बिडेन की ओर से बधाई कॉल के साथ व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण हो, जो संदेश गया है वह यह है कि चुनाव प्रक्रिया में सभी शिष्टाचार खो नहीं गए हैं।

2020 में इसे कुछ समय के लिए किनारे कर दिया गया था।

दोनों पक्षों में भावनाएँ अभी भी तीव्र हैं लेकिन अलग-अलग कारणों से। लेकिन अभियान ने राजनीतिक पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है जो आमतौर पर एक प्रत्याशित क्लिहैंगर के साथ आता है। डेमोक्रेट्स बस इस बात से हैरान हैं कि आने वाले 47वें राष्ट्रपति ने गलत सूचना और कटुता के बीच इसे खींच लिया।

डेमोक्रेटिक पार्टी के अन्य लोग इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि वे संकेतों को इतनी सावधानी से नहीं पढ़ सके कि वे आगे बढ़ सकें।

शोर के बीच से। फिर भी यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि ट्रम्प जाति, लिंग संबंधी संदेहों से अछूते रहे, जो उनके रास्ते में फेंके गए थे। उदाहरण के लिए लैटिनो समुदाय ने ट्रम्प का जोरदार समर्थन किया और सामूहिक निर्वासन या सरोगेट्स द्वारा चरित्र चित्रण की आशंकाओं को हवा में उड़ा दिया। यही बात ट्रम्प के बारे में भी कही जा सकती है।

नव-निर्वाचित राष्ट्रपति का महिलाओं, अफ्रीकी अमेरिकियों या एशियाई समुदाय के साथ प्रदर्शन।

मतदाताओं के वे सभी वर्ग कहाँ थे, जिन्हें सात युद्धभूमि राज्यों में अंतर पैदा करना था? ट्रम्प ने पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन के तथाकथित ब्लू वॉल राज्यों में अपना रास्ता बना लिया; और जब मतगणना पूरी हो जाएगी तो वह सभी सात स्विंग राज्यों को सील कर सकता है, कुछ ऐसा जो बिडेन ने 2020 में उत्तरी कैरोलिना को छोड़कर किया था।

इस पर अंतिम निर्णय लेने में समय लगेगा अरब अमेरिकी, यहूदी, हिस्पैनिक (प्यूर्टो रिकान सहित), एशियाई मतदाताओं ने किस प्रकार अपनी प्राथमिकताएं दर्शायीं, इस पर वक्तव्य।

एक - दूसरे पर दोषारोपण

उँगली उठाने की कवायद शुरू हो गई है। 2024 के तात्कालिक परिप्रेक्ष्य में

हैरिस समर्थक। हताश लोग रॉयटर्स

चुनाव के बारे में एक धारणा यह है कि हैरिस के पास तैयारी के लिए केवल तीन महीने थे और राष्ट्रपति बिडेन को जून की बहस में उनके लड़खड़ाने तक इंतजार नहीं करना चाहिए था।

लेकिन कुल मिलाकर डेमोक्रेट्स के भीतर धीरे-धीरे यह भावना कम होती जा रही है कि शायद अब समय आ गया है कि पार्टी की गहराई और दिशा को जानने के लिए एक वास्तविक आत्ममंथन किया जाए, जो शायद अपनी राह से भटक गई है। एक तर्क यह है कि पार्टी के पास कोई "असली" नेता नहीं है; और दूसरा यह है कि विचारधारा इतनी दूर वामपंथी हो गई है कि अब यह केंद्र-दक्षिणपंथी नहीं रह गई है जैसा कि होना चाहिए।

ट्रम्प एक संदेशवाहक के रूप में शायद वह नहीं हैं जिसकी ग्रैंड ओल्ड पार्टी को जरूरत है; लेकिन उनका

अशिष्टतापूर्वक तैयार किए गए संदेश इतने शक्तिशाली थे कि वे व्हाइट हाउस, सीनेट और संभवतः प्रतिनिधि सभा में भी बहुमत बरकरार रख सकते थे।

डेमोक्रेटिक रणनीतिकार जेम्स कारविल, जिन्होंने 'इट्स द इकॉनमी, स्टुपिड' के नारे के साथ राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की यात्रा की पटकथा लिखी थी, को भुलाया नहीं गया है। इस बार मुख्य मुद्दा अर्थव्यवस्था रहा है, जिसे हैरिस अभियान सामूहिक निर्वासन, गर्भपात, मूल्यों और लोकतंत्र के भविष्य पर शोरगुल के बीच ठीक से समझने में विफल रहा।

वाशिंगटन धीरे-धीरे गियर बदल रहा है — एक शोरगुल भरे अभियान के मौसम से 20 जनवरी, 2025 को संक्रमण की ओर। कहा जाता है कि राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए उम्मीदवार पूरी तरह से इस प्रक्रिया में डूबे हुए हैं और मीडिया भी ऐसा ही है। आम सोच यह है कि ट्रम्प निश्चित रूप से एक ऐसे प्रशासन में अपना रास्ता बना लेंगे जो उनकी सोच और वादों को पूरी तरह से दर्शाता है। और वादों की उस सूची में सबसे ऊपर है पहले दिन से ही बड़े पैमाने पर निर्वासन शुरू करना, भले ही ट्रम्प को अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभावों की याद दिलाई जा रही हो।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने यह रिपोर्ट दी है। वाशिंगटन डीसी में उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र पर चर्चा

संपादक को पत्र अपने पत्र ईमेल द्वारा bleditor@thehindu.co.in पर भेजें या डाक द्वारा 'संपादक को पत्र', द हिंदू बिजनेस लाइन, कस्तूरी बिल्डिंग, 859-860, अन्ना सलाई, चेन्नई 600002 पर भेजें।

ट्रम्प की विदेश नीति 'ट्रम्प की राजनीतिक वापसी - एक ऐतिहासिक मोड़' (8 नवम्बर) लेख के संदर्भ में।

डोनाल्ड ट्रंप की 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत से अमेरिकी विदेश नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। उनका 'अमेरिका फर्स्ट' सिद्धांत, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं पर घरेलू समृद्धि और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, संभवतः उनके प्रशासन के विदेश नीति निर्णयों को आकार देना जारी रखेगा।

इससे चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ तनाव बढ़ सकता है, साथ ही एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और गठबंधनों में भी बदलाव आ सकता है।

इसके अतिरिक्त, ट्रम्प की आर्थिक चीनी आयात पर संभावित शुल्क और ईरान पर प्रतिबंध सहित अन्य नीतियों का वैश्विक व्यापार और सुरक्षा गतिशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

अमरजीत कुमार हज़ारीबाग़,
झारखण्ड

जलवायु 'अंतराल'

'जलवायु वित्त अंतराल को पाटना' के संबंध में (8 नवम्बर)।

विकसित देशों को विकासशील देशों की जलवायु नियंत्रण परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन डॉलर का योगदान देना है।

बाकू, अज़रबैजान में आगामी जलवायु शिखर सम्मेलन को केंद्रीकृत करना होगा जलवायु वित्त मुद्दा और सक्रियता

विकसित देशों से 100 अरब डॉलर के कोष में योगदान देने का आग्रह किया गया।

अब जब ट्रम्प सत्ता में हैं, तो जलवायु शमन और अनुकूलन के लिए धन जुटाना और भी मुश्किल हो जाएगा।

कठिन.

एन.आर. नागराजन
शिवकाशी

धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना 'डिजिटल गिरफ्तारी से बचना' लेख के संदर्भ में, डिजिटल भुगतान की तीव्र वृद्धि ने घोटालेबाजों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं क्योंकि वे लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके विकसित कर रहे हैं।

साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं, जैसे नकली UPI ट्रांजैक्शन इमेज, ईमेल के ज़रिए नेट बैंकिंग धोखाधड़ी आदि। धोखाधड़ी की घटनाओं की तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध शाखा को रिपोर्ट की जानी चाहिए।

हेल्पलाइन। सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। सरकार को एक मजबूत और सख्त जागरूकता अभियान शुरू करना होगा ताकि ये घोटालेबाज खुलेआम न घूम सकें।

बाल गोविंद
नोएडा

फसल विविधीकरण संपादकीय 'फार्म ट्रुथ्स' (8 नवंबर) के अनुसार। जबकि विभिन्न कारक किसानों को फसलों की खेती के निर्णय को प्रभावित करते हैं, सरकार को उपभोक्ताओं को अपने आहार पैटर्न को बदलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि किसानों को खेती की गतिविधियों में विविधता लाने के लिए प्रभावित किया जा सके।

यद्यपि न्यूनतम समर्थन मूल्य महत्वपूर्ण है, तथापि मांग

किसी विशेष फसल की खेती के लिए क्षेत्र का विस्तार करने के लिए किसानों के लिए बाजार में कृषि उपज की उपलब्धता महत्वपूर्ण है।

काटना।
इससे जुड़े जोखिम

किसानों की संभावित हानि को कम करने के लिए लगातार होने वाले जलवायु परिवर्तनों को बेहतर ढंग से कम करने की आवश्यकता है।

पानी, उर्वरक और कीटनाशकों के तुलनात्मक रूप से बढ़ते उपयोग को देखते हुए, खेती में भारी बदलाव आया है।

धान से बाजरा की खेती करना पोषण मूल्य बढ़ाने के साथ-साथ ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के अप्रत्यक्ष प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए भी जरूरी है। इसलिए फसल विविधीकरण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है क्योंकि एमएसपी में केवल बदलाव से कोई मदद नहीं मिलेगी।

वी.एस.के. पिल्लई
चंगनाचेरी (केरल)

निर्मला लक्ष्मण द्वारा प्रकाशित तथा प्रवीण सोमेश्वर द्वारा मुद्रित, एचटी मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं. 8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201306, टीएचजी पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई-600002 की ओर से। संपादक: रघुवीर श्रीनिवासन (पीआरपी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेदार संपादक)।
आईएसएसएन 0971 - 7528

ट्रम्प 2.0 को आगे बढ़ाने के लिए छह कदम

अजय श्रीवास्तव

मैं भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका व्यापार 190 बिलियन डॉलर से अधिक है, और यह गूगल, फेसबुक और अमेज़ॅन जैसी अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों के सबसे बड़े उपयोगकर्ता आधार का घर है।

ट्रम्प के नेतृत्व वाले व्यापार युग में लाभ उठाने के लिए भारत को कैसे तैयार रहना चाहिए? यहाँ छह कदम बताए गए हैं जो भारत उठा सकता है।

कम आयात शुल्क: डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से

ट्रंप के दृष्टिकोण से, भारत में टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने पिछले पांच सालों में बार-बार भारत को "टैरिफ किंग" करार दिया है, जिसमें हार्ले-डेविडसन मोटर-साइकिलों पर 100 प्रतिशत और अमेरिकी व्हिस्की पर 150 प्रतिशत टैरिफ जैसे उदाहरण दिए गए हैं। श्री ट्रंप द्वारा "पारस्परिक टैरिफ" पर ज़ोर दिए जाने से भारत पर टैरिफ सुधारों पर विचार करने का दबाव पड़ सकता है, भले ही भारत की दरें विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मानदंडों के भीतर हों। भारत का औसत टैरिफ 17 प्रतिशत वास्तव में अमेरिका के 3.3 प्रतिशत से ज़्यादा है, लेकिन दक्षिण कोरिया (13.4 प्रतिशत) और चीन (7.5 प्रतिशत) जैसे देशों के बराबर है।

हालांकि श्री ट्रम्प के दावे अतिरंजित हो सकते हैं, फिर भी भारत को रणनीतिक टैरिफ समीक्षा से लाभ हो सकता है जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित है, जैसे कि कम लागत, मूल्य-वर्धित विनिर्माण और व्यापार का समर्थन करना। मामूली समायोजन के साथ, भारत अपने औसत टैरिफ को लगभग 10 प्रतिशत तक कम कर सकता है, बिना किसी प्रभाव के।

राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह संभव है क्योंकि 85 प्रतिशत टैरिफ राजस्व 10 प्रतिशत से कम टैरिफ लाइनों से आता है, जबकि 60 प्रतिशत टैरिफ लाइनें राजस्व में 3 प्रतिशत से कम योगदान देती हैं। एक सोची-समझी कटौती भारत के टैरिफ ढांचे को सरल बना सकती है - स्लैब को 40 से अधिक से घटाकर 5 करना, उच्चतम टैरिफ को 50 प्रतिशत पर सीमित करना, और यह सुनिश्चित करना कि अधिकांश इनपुट सामग्रियों पर तैयार माल की तुलना में कम कर लगाया जाए। टैरिफ को परिष्कृत करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समीक्षा अंतरराष्ट्रीय जांच से बचने में मदद कर सकती है जबकि एक टैरिफ नीति को बढ़ावा दे सकती है जो भारत के आर्थिक उद्देश्यों का समर्थन करती है।

आईटी निर्यात में विविधता लाएं: आउटसोर्सिंग की श्री ट्रम्प की आलोचना और एच-1बी वीजा पर उनकी सख्त नीतियों ने भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जो अपने निर्यात राजस्व के 80 प्रतिशत के लिए अमेरिका पर निर्भर है। आउटसोर्सिंग पर संभावित प्रतिबंध भारतीय आईटी फर्मों की आय को प्रभावित कर सकते हैं और कुशल प्रतिभाओं को काम पर रखना कठिन बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त, श्री ट्रम्प की

सख्त आव्रजन रुख से वीजा प्रक्रिया जटिल हो सकती है, भारतीय कंपनियों के लिए लागत और परिचालन संबंधी बाधाएं बढ़ सकती हैं और अल्पकालिक अमेरिकी नियुक्तियों पर कुशल पेशेवरों की आवाजाही सीमित हो सकती है।

इन जोखिमों को कम करने के लिए, भारत के आईटी क्षेत्र को अमेरिका से आगे बढ़कर अन्य बाजारों में परिचालन का विस्तार करना चाहिए तथा वैश्विक उद्योगों के लिए डिजिटल परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एकीकरण जैसी उच्च-मूल्य वाली सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

डेटा नीतियों को मजबूत करें: भारत एक बड़ा डिजिटल डेटा जनरेटर है। नई AI-संचालित अर्थव्यवस्था के लिए डेटा कच्चा माल है, अमेरिकी तकनीकी कंपनियाँ सीमाओं के पार डेटा के मुक्त प्रवाह का पक्षधर हैं। श्री ट्रम्प भारत पर अधिक खुली डेटा-साझाकरण नीतियों को अपनाने के लिए दबाव डाल सकते हैं।

विश्व व्यापार संगठन में, अमेरिका भारत पर ई-कॉमर्स पर संयुक्त वक्तव्य पहल में शामिल होने के लिए दबाव डाल सकता है, जो अप्रतिबंधित डेटा आवागमन के उसके दृष्टिकोण के अनुरूप होगा।

भारत को डेटा को स्वतंत्र रूप से साझा करने के लिए बाहरी दबाव का विरोध करना चाहिए। एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने भारत की आईटी आउटसोर्सिंग हब से बदलने की क्षमता पर जोर दिया

एआई इनोवेशन इकोसिस्टम में, इसके विशाल डेटा और कंप्यूटिंग विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए। वे कहते हैं, "किसी और को इसका फ़ायदा उठाने देने का कोई कारण नहीं है।"

चीन डेटा को भूमि, श्रम और पूंजी की तरह उत्पादन का एक कारक मानता है, तथा इसे वैश्विक कंपनियों के साथ साझा नहीं करता है।

आईपीईएफ के व्यापार स्तंभ से इनकार: हालांकि टैरिफ पर श्री ट्रम्प के रुख में नरमी आने की संभावना नहीं है, लेकिन वे भारत से इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) के "व्यापार स्तंभ" में शामिल होने का आग्रह कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टैरिफ में कटौती शामिल नहीं है।

14 देशों के इस समझौते में भारत ने चार में से तीन क्षेत्रों के लिए प्रतिबद्धता जताई है। भारत ने समझदारी से आईपीईएफ व्यापार स्तंभ से बाहर निकलने का विकल्प चुना है क्योंकि यह टैरिफ कटौती लाभ की पेशकश किए बिना डिजिटल व्यापार और श्रम मानकों के आसपास घरेलू नीतियों को प्रतिबंधित करता है।

भारत को अपना रुख नहीं बदलना चाहिए।

मेक इन इंडिया को मजबूत करें: श्री ट्रम्प से उम्मीद की जाती है कि वे मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम जैसी पहलों के माध्यम से डब्ल्यूटीओ नियमों को दरकिनार करते हुए अमेरिकी विनिर्माण सब्सिडी को बढ़ावा देंगे। भारत इसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम को मजबूत करने के संकेत के रूप में ले सकता है।

ग्राम, सतह-स्तर की असेंबली के बजाय गहन विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत और अमेरिका कच्चे माल के चरण से सौर सेल का उत्पादन करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। इससे चीन पर निर्भरता कम होगी और दोनों को लाभ होगा।

समान रूप से जवाब दें: भारत को अमेरिका के साथ एक समान भागीदार के रूप में जुड़ना चाहिए, अपने हितों को निष्पक्ष रूप से व्यक्त करना चाहिए, और सभी लेन-देन में मापा हुआ पारस्परिकता के साथ जवाब देना चाहिए - ऐसा कुछ जो उसने पहले भी सफलतापूर्वक किया है। उदाहरण के लिए, मार्च 2018 में, जब अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्युमीनियम पर टैरिफ लगाया, तो भारत ने 29 विशिष्ट अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर जवाब दिया। यह प्रतिक्रिया सावधानीपूर्वक कैलिब्रेट की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत अमेरिकी आयात से उतना ही राजस्व एकत्र करे जितना अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्युमीनियम से किया था।

भारत को नए ट्रम्प युग से लाभ उठाने के लिए पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए और अप्रत्याशित स्थिति से बचना चाहिए।

लेखक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च के संस्थापक हैं
पहल

चित्रण: अजय मोहंती

बयानबाजी के पीछे का सच

सादी राजनीति

अदिति फडनिस

एक नई व्यवस्था स्थापित की गई है
जैसे -जैसे वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यभार संभालना
दुनिया बदल रही है।
दक्षिण एशिया में भारत के लिए क्या संभावनाएं हैं?

कई लोगों का तर्क है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने पड़ोस में दोस्तों को दुश्मन बनाने के अलावा कुछ नहीं किया है। वे भूटान की ओर इशारा करते हैं, जहां थिम्पू से भारत के साथ अपने सारे रिश्ते सुधारने की मांग उठ रही है। नेपाल में एक नई सरकार है, जो कथित तौर पर नई दिल्ली के खिलाफ है। वहां के पर्यवेक्षकों का कहना है कि भारत से आमंत्रण न मिलने की वजह से नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दिसंबर में भारत आने से पहले चीन का दौरा करेंगे, जिससे एक तरह की परंपरा टूट जाएगी। बांग्लादेश में दुश्मन नंबर एक, अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में मेजबानी करके नई दिल्ली ने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए हैं कि अनुभवी राजनयिक भी पूछ रहे हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान कभी दोस्त बन सकते हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके (एकेडी) स्पष्ट रूप से भारत विरोधी और वैचारिक रूप से चीन समर्थक हैं और ऐसा अनुमान है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। "इंडिया आउट" अभियान के साथ, नई दिल्ली ने मालदीव में मित्रतापूर्ण स्वीकार्यता का हर निशान खो दिया है। दक्षिण एशिया में, भारत की कूटनीति दोषपूर्ण है और चीन का दबदबा है।

इसमें से, भारत एक गम के पेड़ पर है।

लेकिन क्या हालात सचमुच इतने बुरे हैं?

इस वर्ष अक्टूबर में भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने 40 मेगावाट बिजली के व्यापार के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल के लिए, किसी तीसरे देश को बिजली बेचना पहली बार है, क्योंकि भारत अब तक इसका एकमात्र खरीदार रहा है। फिलहाल, नेपाल भारत को बिजली भेजेगा, इससे पहले कि भारत बांग्लादेश को बिजली भेजे, इस तरह वह पहली बार एक ईमानदार मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। यह 1997 से बहुत अलग है, जब भारत और नेपाल के बीच बिजली-व्यापार समझौता संसद में पेश भी नहीं किया जा सका था, क्योंकि इसे भयंकर राजनीतिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था (नेपाल के संविधान में यह अनिवार्य किया गया था कि नेपाल के प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े विदेशी समझौतों को संसद द्वारा दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए और उस समय भारत के बारे में संदेह बहुत अधिक था)। माना कि यह केवल 40 मेगावाट है, लेकिन कम से कम यह एक शुरुआत तो है।

श्रीलंका में, सितंबर में जब AKD को राष्ट्रपति चुना गया था, तब नीतिगत बदलावों के बारे में भयावह भविष्यवाणियाँ की गई थीं। उनके और उनकी पार्टी के अतीत - मार्क्सवादी, लेनिनवादी और ट्रॉट्स्कीवादी, और बाद में अति-राष्ट्रवादी सिंहल बौद्ध - ने कैसंड्रा को यह भविष्यवाणी करने के लिए प्रेरित किया कि भारत-श्रीलंका संबंध सबसे पहले धराशायी होंगे। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। सच है, सरकारी स्वामित्व वाली श्रीलंकाई एयरवेज के निजीकरण को रोक दिया गया है और सरकारी स्वामित्व वाली सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा निजीकरण के बजाय सुधार को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अदानी-जॉन कील्स होल्डिंग्स (JKH) उद्यम का पहला चरण, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल (WCT), 2024 की पहली तिमाही में चालू हो जाएगा-

25. लाल सागर में व्यवधान के कारण अधिक व्यापार कोलंबो की ओर जा रहा है और इसलिए अच्छा पैसा कमाया जा रहा है। और नहीं, सरकार WCT का राष्ट्रीयकरण नहीं कर रही है।

मालदीव में बयानबाजी को दरकिनार कर कूटनीति काम कर रही है। जिस देश ने भारतीय सैनिकों की मौजूदगी के कारण भारत को बाहर जाने का आदेश दिया था, वह मालदीव है।

अक्टूबर में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की नई दिल्ली यात्रा के दौरान द्वीप समूह के सैनिकों ने एक विशिष्ट रक्षा घटक के साथ व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की थी।

भारत के विदेश मंत्री अक्टूबर में पाकिस्तान गए थे, जो 12 वर्षों में इस पद पर आसीन किसी व्यक्ति की पहली यात्रा थी।

उनके प्रत्यर्पण की मांग के बावजूद, बांग्लादेश की नई सरकार ने यह मान लिया है कि शेख हसीना ही जनता की दुश्मन हैं, भारत नहीं। बिजली आपूर्ति में लगभग 50 प्रतिशत की कटौती के बाद, ढाका ने अदानी पावर को बकाया राशि का अपना हिस्सा चुका दिया है, जो झारखंड संयंत्र से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करता है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि वह राजनीति को वाणिज्य के रास्ते में नहीं आने देगा। ऊपर दिया गया त्रिपक्षीय बिजली समझौता जारी है।

बेशक, दक्षिण एशिया में हाथी चीन ही बना हुआ है। लेकिन पड़ोस में ऐप पर प्रतिबंध लगाने से कहीं आगे जाकर नियंत्रण की रणनीति अपनाई जा रही है। भारत ने नेपाल से कहा है कि वह चीनी निवेश वाली संस्थाओं, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, से बिजली नहीं खरीदेगा। नेपाली निवेशकों ने चीनी कंपनियों से कहना शुरू कर दिया है: "हमें कॉल न करें, हम आपको कॉल करेंगे।"

बांग्लादेश, सुश्री हसीना के प्रधानमंत्री रहने के दौरान भी चीन के साथ मित्रवत नहीं था। लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इसका भविष्य क्या होने वाला है। भूटान के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री शेरिंग टोपगे ने इस साल की शुरुआत में अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए नई दिल्ली को चुना, जिससे भूटानी राजनीतिक अभिजात वर्ग के बीच पहले की सोच बदल गई कि देश को अपनी भू-रणनीतिक प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करना चाहिए। भारत असम-भूटान सीमा पर एक नए "माइंडफुलनेस" शहर गेलेफू को विकसित करने में मदद कर रहा है।

बयानबाजी से कुछ और ही संकेत मिल सकता है। लेकिन पड़ोस में भारत का अभी भी प्रभाव है - और दोस्त भी।

ट्रम्प, मोदी, राहुल और फॉर्मूला 3

तीन स्तंभों का एक सूत्र है जिस पर सफल अभियान टिका होना चाहिए। ट्रंप ने इसका पालन किया है, जैसा कि मोदी ने 2014 और 2019 में किया था, लेकिन 2024 में नहीं

डब्ल्यू डोनाल्ड ट्रम्प की जीत क्या बताती है हमें बताएं कि नेता क्या करते हैं चुनाव हारना या जीतना, लेकिन बहुत कम। अभी ट्रंप के बारे में सोचिए, अक्सर राहुल के बारे में, और इस साल जून में नरेंद्र मोदी के बारे में।

ट्रम्प की शानदार जीत से पहला सबक एक सफल अभियान के लिए तीन स्तंभों का सूत्र है। मान लीजिए राष्ट्रवाद, विजयवाद और निराशावाद। यह कैसे काम करता है, यह देखने के लिए MAGA (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) अवधारणा को देखें।

यह कि अमेरिका वर्तमान की तुलना में कहीं अधिक महान होने का हकदार है, राष्ट्रवाद को दर्शाता है। यह कि इसे फिर से महान बनाया जाएगा - कुछ दूर नहीं के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हुए जब अमेरिका शीर्ष पर था - विजयवाद है। लड़ाई शुरू होने से पहले हमेशा जीत की घोषणा करें।

और यदि आप तर्क देते हैं कि अमेरिका पहले से ही बढ़िया, इसकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है — 2008 में लगभग 50 प्रतिशत की तुलना में यूरोज़ोन के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से लगभग दोगुनी हो गई है — इसके शेयर बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और प्रौद्योगिकी और नवाचार में इसका नेतृत्व दुनिया को रोशन कर रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा कि निराशावाद क्या होता है। चुनावी राष्ट्रवाद में, मेरा देश तब तक महान नहीं है जब तक मैं प्रभारी नहीं हूँ। फिर, यह बहुत बेहतर होगा।

राष्ट्रीय हित

शेखर गुप्ता

जैसे-जैसे हम महाद्वीपों से आगे बढ़ते हैं और भारत की ओर बढ़ते हैं, हम देख सकते हैं कि 2014 और 2019 में राहुल गांधी क्यों हताश हो गए, जबकि मोदी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। और फिर, 2024 में मोदी अपनी खुद की उम्मीदों - और बाजारों और पोलस्टर्स की उम्मीदों - से इतने पीछे क्यों रह गए? वह 240 उनके लिए एक निराशा थी। अंकों के आधार पर जीत एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक निराशा थी जो जल्दी से नॉकआउट करने का आदी था। उसे इस स्थिति तक क्यों लाया गया?

कांग्रेस और राहुल को हमारे तीन बिंदुओं पर परखना आसान है: राष्ट्रवाद, विजयोन्माद और निराशावाद। 2014 में राहुल एक दशक से सत्ता में रही पार्टी के लिए प्रचार अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन उनके अभियान ने शायद ही कभी, अगर कभी, इसकी उपलब्धियों को उजागर किया हो। क्या उनकी पार्टी के दशक ने भारत को महान बनाया है? और क्या वह अब इसे और भी महान बनाने जा रहे हैं? क्या इस दशक ने भारत को सैन्य और कूटनीतिक रूप से अधिक मजबूत, रणनीतिक रूप से अधिक सुरक्षित और वैश्विक रूप से अधिक प्रभावशाली बनाया है? क्या कांग्रेस/संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने भारत को उस "दलदल" से बाहर निकाला है जिसमें "वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे छोड़ दिया था"? ऐसा कुछ नहीं हुआ।

इससे राष्ट्रवाद और विजयवाद खत्म हो गया।

यह अभी भी अमीर और गरीब, असमानता, भाजपा की सांप्रदायिकता, गरीबों, वंचित जातियों और आदिवासियों के लिए उनकी और उनकी पार्टी की चिंता के बारे में था। राहुल और उनके समर्थक तर्क दे सकते हैं कि वे सच्चाई के करीब रह रहे थे - कि उनकी पार्टी के शासन के 10 साल बाद भी वास्तव में बहुत गरीबी, असमानता और अभाव था - और पूछ सकते हैं कि वे इस तरह के विजयी अभियान को कैसे बना सकते हैं। इसका उत्तर हमारे तीन-बिंदु प्रस्ताव के तीसरे भाग में निहित है: निराशावाद।

यह राजनीति है। आप मतदाता से बात कर रहे हैं-

या, वास्तव में, दो तरह के मतदाता। एक मतदाता जो अभी तक निर्णय नहीं ले पाया है, वह आपके और आपके प्रतिद्वंद्वी के बीच बहुत अंतर नहीं देख पा रहा है और सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है।

और, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके अपने वफ़ादार मतदाता। यह ज़रूरी है कि आप उन्हें इतना प्रेरित करें कि उन्हें यकीन हो जाए कि वे जीतने वाले हैं और बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए बाहर आएँ। ध्रुवीकृत निर्वाचन क्षेत्रों में, ऐसी चीज़ें ही चुनावी हार और जीत को अलग करती हैं।

2019 तक, किसी के पास होगा सोचा था कि कांग्रेस मोदी के पांच साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आएगी और तर्क देगी कि उसने बहुत बेहतर काम किया है और अगर भारत उसी शानदार रास्ते पर लौटना चाहता है तो मतदाताओं को उसे फिर से वोट देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह सब मोदी सरकार के "भ्रष्टाचार" (चौकीदार चोर है), कुशासन, विफल नोटबंदी और निश्चित रूप से सांप्रदायिकता के आरोपों के बारे में था। पूरा अभियान नकारात्मक था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह कहे कि कांग्रेस के शासन में भारत महान था और इसे फिर से महान बनाने के लिए हमें वोट दें।

यह कहना एक बात है कि मोदी ने पुलवामा के बाद की लहर का फायदा उठाकर अपनी सभी विफलताओं को भुला दिया, लेकिन हमें यह भी पूछना होगा कि क्या कांग्रेस के अभियान में कोई राष्ट्रवाद था। या फिर आशावाद, अगर विजय की उम्मीद करना बहुत ज्यादा है?

हालांकि, 2014 में मोदी एक ऐसी लहर पर सवार होकर आए थे, जो 2024 में ट्रंप के विचारों से बहुत अलग नहीं थी। भारत की सुरक्षा और सशस्त्र सेना कमजोर थी और दुनिया ने इसे गंभीरता से नहीं लिया; लगातार आतंकवादी हमले हो रहे थे, और भारत ने विनम्रतापूर्वक दूसरा गाल (राष्ट्रवाद) आगे कर दिया; भारत ब्रिक्स में अस्थिर "आई" था और वह भारत को फिर से शीर्ष पर ले जाने वाले थे, जैसा कि इसके "सोने की चिड़िया" अतीत में था; और चीन के लिए, "लाल आंख" (लाल आंख, जिसका अर्थ है कठोर शक्ति) उपचार होगा ,

और पाकिस्तान के लिए 56 इंच का सीना (विजयवाद)।

यह इतना भारी था और कांग्रेस अपने ही अंतर्विरोधों में इतनी उलझी हुई थी -

एक बार फिर से जनादेश की मांग करते हुए, पिछले दो चुनावों को परोक्ष रूप से नकारते हुए - कि किसी ने उन्हें यह तक याद नहीं दिलाया कि भारत 8 प्रतिशत वार्षिक जीडीपी के दशक से आगे बढ़ रहा है, या सभी नए संस्थान बनाए गए हैं। और अगर मोदी ने कभी भी इनमें से किसी को भी स्वीकार करने की जहमत नहीं उठाई, तो यह पुराने जमाने की निराशावादिता थी। वह भारत को फिर से महान बनाने के लिए निकले थे, उससे भी बड़ा नहीं। जैसा कि ट्रम्प ने अब किया है।

तो फिर मोदी अपने लक्ष्य से क्यों चूक गए? 2024 में क्या अलग है? सच तो यह है कि उन्होंने उसी तीन-सूत्री जीत के फॉर्मूले के साथ अभियान को काफी अच्छी तरह से तैयार किया था।

भारत उनके नेतृत्व में महान बन गया था, जैसा कि G20 में कैमरे के सामने विश्व नेताओं द्वारा उन्हें गले लगाने की परेड से पता चलता है; यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है; और पिछले पांच साल पिछले पांच दशकों में सबसे अधिक आतंकवाद मुक्त रहे हैं। क्या आप उन्हें वोट नहीं देंगे यदि वे केवल भारत को और महान बनाने जा रहे थे?

अब उनके अभियान पर वापस जाएं और 10 मुख्य बिंदुओं को चुनें। लगभग सभी मुद्दे कांग्रेस की बातों, या उसके वादों या कथित तौर पर किए जाने वाले वादों के बारे में थे: मंगलसूत्र, बुफ-फलो, घुसपैठिए, पाकिस्तान प्रेम, अल्पसंख्यकवाद, जातिवाद, वंचित जातियों के नेताओं के साथ उसने कितना घटिया व्यवहार किया, वंशवाद, भ्रष्टाचार। आप गिनती जारी रख सकते हैं।

अभियान के दौरान उन्होंने कई चुनावी मुद्दे बनाए थे - वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रतिष्ठा (जी20), महिला मतदाता (महिला आरक्षण) और राम मंदिर के मुद्दे पर अन्य पिछड़े वर्गों से अपील, चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देना - सभी को भुला दिया गया। यह मोदी का नया, रक्षात्मक अवतार था। हमने 27 अप्रैल, 2024 को नेशनल इंटरेस्ट कॉलम में इसका उल्लेख किया था। अगर कोई एक बात थी जो हमने नहीं सुनी, या निश्चित रूप से अक्सर नहीं सुनी, तो वह कुछ इस तरह थी: "देखो मैंने इन 10 सालों में भारत को कैसे महान बना दिया है। क्या तुम मुझे इसे और भी महान बनाने के लिए फिर से पाँच साल नहीं दोगे?"

तथ्य यह है कि मोदी अपने स्वभाव के विपरीत, जीत के घोड़े से उतरकर अखाड़े में चले गए।

लड़ाई। इसने प्रमुख राज्यों में उनकी गति को तोड़ दिया। जैसे-जैसे अभियान से बड़े, राष्ट्रवादी, विजयी संदेश कम होते गए, विपक्ष के आरोपों पर गुस्सा, नाराजगी भरी प्रतिक्रिया ने उस प्रतिक्रिया को बदल दिया जो आमतौर पर तिरस्कारपूर्ण, मोदी-शैली की निराशावादी प्रतिक्रिया होती थी।

यह सिर्फ़ संदेश में बदलाव नहीं था। 2024 का मोदी प्रस्तावों की इस तिकड़ी पर सवार नहीं था, जिसने उसे दो बार बहुमत दिलाया था और हाल ही में ट्रंप को फिर से सत्ता में लाया था। वह सिर्फ़ अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए लड़ रहा था। वह इसे बनाए रखने में सफल रहा, हालाँकि मुश्किल से। इस तरह 2019 के 303 घटकर 240 रह गए।

चुनावी लोकतंत्रों में क्या काम करता है, इसका एक पैटर्न अब तय हो चुका है। आपको ज़्यादातर दूसरे लोकतंत्रों में भी कुछ इसी तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय गौरव, संस्कृति और पहचान शुद्ध, लेन-देन संबंधी अर्थशास्त्र पर हावी हो जाती है।

(इस सप्ताह के लिए वादा किए गए रक्षा बजट के दूसरे भाग को अमेरिकी चुनावों ने पीछे छोड़ दिया। यह अगले शनिवार को प्रकाशित होगा)

दिप्रिंट के साथ विशेष व्यवस्था द्वारा

भारतीय क्रिकेट की घरेलू सच्चाई

नेत्र संस्कृति

विशाल मेनन

वी विराट कोहली, आधुनिक समय के बल्लेबाज एक प्रतिभाशाली कलाकार, के पास सितारों से भरा रिज्यूम है - जो कि इसमें टेस्ट क्रिकेट में भारत के तीन सबसे कम स्कोर में से दो का हिस्सा होना भी शामिल है।

एक हताश कप्तान के रूप में, वह उस समय एक्शन में थे जब उनकी टीम अपने अब तक के सबसे कम स्कोर - 36 रन पर ऑल आउट - से हारी थी।

चार साल पहले एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में भारतीय बल्लेबाज़ों ने एक बार फिर से बुरी तरह हार का सामना किया।

पिछले महीने बेंगलुरू में दोपहर के समय बादल छाए रहने के दौरान न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी, मैट हेनरी और विल ओ'रूर्के ने भारतीय बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दीं। भारत केवल 46 रन ही बना सका, जो घरेलू मैदान पर उसका सबसे कम स्कोर था। पुणे में हुए अगले टेस्ट मैच में भी वे संघर्ष करने का साहस नहीं दिखा पाए।

न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाज़ी पारी की शुरुआत धमाकेदार रही। बाएं हाथ के स्पिनर मिशेल सेंटनर ने भारत की मजबूत बल्लेबाजी को झकझोरते हुए 13 विकेट चटकाए। मुंबई में तीसरे टेस्ट में हालात तब बिगड़ गए जब 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम 121 रन पर आउट हो गई।

न्यूजीलैंड, जिसे कभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के पोस्टर बॉयज़ में नहीं गिना जाता था, ने भारत की कमज़ोरी, अहंकार और अक्षमता को उजागर करते हुए 3-0 की अविश्वसनीय जीत दर्ज की। ऐसा करके उन्होंने घरेलू मैदान पर भारत के 12 साल और 18 सीरीज़ के अभेद्य वर्चस्व को समाप्त कर दिया।

परिणाम संभावित रूप से जटिल हो सकता है
भारत की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में जगह पक्की हो गई है।

डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया में आगामी पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हराना होगा।

भारत को अपने बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण आत्मसमर्पण करना पड़ा।

कोहली और कप्तान रोहित शर्मा थके हुए और विचारों से रहित दिखे, जबकि सरफराज खान और शुभमन गिल जैसे युवा भी कम तैयार दिखे।

मूलतः, इस श्रृंखला हार ने एक बुनियादी प्रश्न को सामने ला दिया है: क्या टी-20 बल्लेबाजी की भावना टेस्ट क्रिकेट में भी फैल रही है?

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इस दौर में भारतीय बल्लेबाजों के लिए धैर्य अब कोई गुण नहीं रह गया है। उन्हें रक्षात्मक शॉट खेलते हुए शायद ही कभी देखा जाता है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता; आक्रमण ही बचाव का सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका है, और शॉट चयन में उतावलापन आ गया है।

दुख की बात है कि पुरानी दुनिया के अच्छे गुणों की जगह अब पावर गेम और रेंज हिटिंग ने ले ली है। यह एक व्यापक पीढ़ीगत समस्या है जिसमें टी20 प्रारूप टेस्ट मैच की बल्लेबाजी कौशल के खिलाफ काम कर रहा है। यह एक गहरी जड़ वाली बीमारी है जिसने भारत के प्रमुख बल्लेबाजों को जकड़ लिया है, और चिंता की बात यह है कि इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि हम 36 ऑल आउट और 46 ऑल आउट जैसे विस्फोटों को इतनी बार देख रहे हैं।

अनुभवी क्रिकेट लेखक के अनुसार
गिदोन हेघ के अनुसार, टेस्ट क्रिकेट के पांच सबसे कम स्कोर 2010 के बाद से आए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह टी20 और फ्रैंचाइज़ क्रिकेट के उदय के साथ हुआ है। टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पिछले महीने पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्हाइट-बॉल क्रिकेट के प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार किया था।

गंभीर ने कहा, "यह पूरी तरह से टी20 क्रिकेट पर निर्भर करता है। जितना अधिक टी20 क्रिकेट खेला जाएगा, उतना ही कम लोग इसका बचाव करेंगे।"

उन्होंने विस्तार से बताया, "कभी-कभी आप गेंद को इतनी ताकत से पकड़ने के आदी हो जाते हैं कि आप नरम हाथों और उन सभी चीजों को भूल जाते हैं जो शायद 8 या 10 साल पहले हुआ करती थीं। मुझे लगता है कि हमें बेहतर तरीके से बचाव करना चाहिए, खासकर टर्निंग ट्रैक पर, क्योंकि अगर आपको अपने बचाव पर भरोसा है, तो बहुत सी चीजें सुलझ सकती हैं।"

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में शामिल भारतीय टीम के सामने एक अस्तित्वगत प्रश्न खड़ा है: उनके लिए घरेलू मैदान पर खेलने का क्या फायदा है?

भारत अब वह दुर्गम गढ़ नहीं रहा, जो 1990 और 2000 के दशक में था, जिसके कारण पूर्व आस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीफन वॉ ने इसे "अंतिम सीमा" की संज्ञा दी थी।

आईपीएल के उदय का मतलब है कि दुनिया भर के प्रमुख खिलाड़ी साल में कम से कम एक बार भारत आते हैं। नकदी से भरपूर टी20 लीग ने क्रिकेट के नक्शे को छोटा कर दिया है, जिससे भारत का रहस्य, आभा और साज़िश खत्म हो गई है। फिर भी, इस महीने की शुरुआत में न्यूजीलैंड ने इन तटों पर जो हासिल किया, उसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। अपने तावीज़ खिलाड़ी केन विलियमसन के बिना, न्यूजीलैंड ने भारत को उसके ही घर में 3-0 से हराया। यह न्यूजीलैंड के क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाएगी, जो 2021 WTC जीत के बराबर है।

सैंटनर ने इसे सटीक रूप से व्यक्त किया जब उन्होंने कहा: "हमने उन्हें (भारत को) उनके ही खेल में हराया। हमने उनकी अपनी परिस्थितियों में उनसे बेहतर प्रदर्शन किया।"

बुखारा एक ही क्यों है?

हाँ, लेकिन...

संदीप गोयल

मैं पहले बुखारा तरीके से खाया 1986 में भी. वो भी सिकंदरी रान को मशहूर शेफ मदन लाल जैसवाल ने पकाया। सच कहूं तो मैंने दाल बुखारा **जैसी दाल वाली डिश का स्वाद** तब तक नहीं चखा था। मैं हैरान था कि दाल इतनी स्वादिष्ट हो सकती है।

मेन्यू काफी सादा था - बराह कबाब थे, और तब भी, इसमें तंदूरी आलू, नान बुखारा और फिरनी का स्वाद था। 1980 के दशक में खुली रसोई का अनुभव एक नई बात थी। अंदरूनी भाग - देहाती लालित्य का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण, पारंपरिक कालीनों से सजी पत्थर की दीवारें, खुरदरी नक्काशीदार टेबल, लकड़ी के स्टूल, साथ ही तांबे के बर्तनों और कलशों की गर्म चमक, रेस्तरां के अद्वितीय सौंदर्यशास्त्र में योगदान करते हैं। हुसैन पेंटिंग जो इन दिनों पत्थर के खंभों में से एक पर लटकी हुई है, उसे अभी तक इस प्रसिद्ध भोजनालय को इस कलाकार द्वारा उपहार में नहीं दिया गया था।

खाद्य एवं पेय टीम

मौर्या में अब मशहूर हो चुके लकड़ी के मेन्यू को फिर से डिजाइन किया जाना था। मैं तब विज्ञापन एजेंसी एचटीए में नौसिखिया था। होटल के जनरल मैनेजर अनिल चन्ना दोपहर के भोजन के समय मुझे जानकारी देने के लिए वहां मौजूद थे। मेरे अप्रशिक्षित और अभी भी अनुभवहीन विज्ञापन दिमाग के लिए, लकड़ी के मेन्यू के साथ छेड़छाड़ करना एक अनावश्यक अभ्यास जैसा लग रहा था। 1978 में शुरू किया गया बुखारा पहले से ही एक प्रतिष्ठित रेस्तरां था - राजीव और सोनिया गांधी उन दिनों नियमित रूप से वहां आते थे; और बुखारा में भोजन किए बिना किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए भारत की यात्रा पूरी नहीं होती थी।

आईटीसी के दिग्गज चेयरमैन अजीत हक्सर ने बुखारा (या ऐसा कहा जाता है) की शुरुआत की थी, ताकि दिल्ली के मशहूर मोती महल से बेहतर भारतीय खाना परोसा जा सके। नए रेस्तराँ ने सभी उम्मीदों को पार करते हुए भारत का अब तक का नंबर 1 रेस्तराँ बन गया है।

शुक्र है कि दोपहर के भोजन के दौरान मेन्यू पर चर्चा बीच में ही खत्म हो गई, जब शेफ जैसवाल ने इसे बदलने की जरूरत पर सवाल उठाया। श्री चन्ना अब दो विचारों में थे। मैं अपनी राय व्यक्त करने के लिए बहुत जूनियर था और मैंने अपनी सलाह को अपने पास रखना पसंद किया। धीरे-धीरे, टेबल के चारों ओर आम सहमति बन गई कि लकड़ी का मेन्यू बुखारा के प्रतीकों, दृश्यों और ध्वनियों का एक हिस्सा था। शुक्र है कि यह निर्णय 38 वर्षों से अपरिवर्तित है।

बुखारा में मेरा अगला बड़ा काम कुछ इस प्रकार था:

सालों बाद। आईटीसी मुख्यालय में बुखारा को न्यूयॉर्क में फ्रेंचाइजी देने का निर्णय लिया गया था। मैं स्तब्ध था। दूसरा बुखारा बनाने की क्या जरूरत थी? आखिर, केवल एक ताजमहल है, केवल एक एफिल टॉवर है ... क्या एक और बुखारा खोलने से मूल रेस्तरां का आकर्षण (और विशिष्टता) कम नहीं हो जाएगा? लेकिन मैं कौन होता हूं ग्राहक के बड़े लोगों की बुद्धिमता पर सवाल उठाने वाला? मेरे क्रिएटिव पार्टनर, गुल्लू सेन और मुझे पार्टनर के रूप में चुने गए कश्मीरी सज्जन से मिलवाया गया। वह "मूल बुखारा को अमेरिकी लहजे के साथ लॉन्च करना चाहते थे।" मुझे अंदरूनी हिस्सों के चित्र पसंद नहीं आए। मौर्य में बुखारा के अधिकांश तत्वों को "बदलाव" करने का प्रस्ताव था। और हां, हमें मेनू को फिर से डिजाइन करने के लिए कहा गया था

आईटीसी में सभी को यह पसंद आया।
निजी तौर पर, मैं अब भी यही सोचता था कि अमेरिकी साहसिक कार्य को निरस्त कर देना चाहिए - बुखारा इतनी कीमती संपत्ति है कि उसे अन्यत्र दोहराया नहीं जा सकता।

न्यूयॉर्क में लॉन्च होने के एक साल के भीतर ही बुखारा को बंद कर दिया गया। अच्छी शुरुआत के बावजूद, रेस्तराँ कभी भी मूल रेस्तराँ की तरह सफ़लता हासिल नहीं कर पाया। कारोबार इतना ठंडा था कि फ्रैंचाइज़-

12 महीने से भी कम समय में ही चिसी ने हार मान ली।

आईटीसी के शीर्ष अधिकारी दंग रह गए।

बहुत आत्मचिंतन और आत्ममंथन हुआ। यह निर्णय लिया गया कि बुखारा कभी नहीं होगा। अन्य आईटीसी संपत्तियों में लगभग समान अनुभव और मेनू वाले रेस्तरां को पेशावरी (और रॉयल अफगान) कहा जाएगा। बुखारा की पेशकश प्राचीन रहेगी।

बुखारा में कभी चावल नहीं परोसा गया - कभी नहीं परोसा जाएगा। मेज़ पर कभी अचार नहीं परोसा जाता। नान कभी आधी नहीं परोसी जाती। बटर चिकन नहीं, ग्रेवी नहीं।

अमेरिकी असफलता के बावजूद, बाद के वर्षों में हांगकांग, बैंकॉक, अजमान, काठमांडू, सिंगापुर और मॉन्ट्रियल में बुखारा शुरू करने के प्रयास किए गए। सभी विफल रहे। 1997 से केवल एक बुखारा है। मूल बुखारा। लंबे समय से अपेक्षित सबक सीखा गया था। आखिरकार।

पिछले चार दशकों में अर्नोल्ड श्वार्जनेगर, रोजर फेडरर, मिक जैगर, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, स्टिंग, बिल और हिलेरी क्लिंटन, प्रिंस फिलिप, टोनी ब्लेयर और कई अन्य मशहूर हस्तियों को बुखारा ने आमंत्रित किया है। वे रेस्तरां के आसपास के रहस्य और इसके अप्रतिम आकर्षण के कारण यहां आए थे। क्योंकि बुखारा केवल एक ही है।

यह कभी न बदले।

लेखक रेडिफ्यूजन के अध्यक्ष हैं

Machine Translated by Google

The Hindustan Times
ई एसटीए ब्लिशेडिन 1 9 24

{ हमारा विचार }

जलवायु संकट पर कोई बहाना नहीं

COP29 को उत्सर्जन को सीमित करने और जीवाश्म ईंधन से संक्रमण के लिए विकासशील देशों के लिए वित्त जुटाने की प्रगति के लिए अमेरिका से आगे देखना होगा

एन राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल और जलवायु कार्यकर्ता COP29 के लिए बाकू, अज़रबैजान में एकत्रित हुए डोनाल्ड ट्रम्प की पृष्ठभूमि में सोमवार से शुरू हो रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ट्रम्प की वापसी अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन के प्रति संशयवादी हैं और उनकी वापसी को जलवायु वार्ता, उत्सर्जन के मामले में विश्व की प्रगति और विकासशील देशों के लिए धन जुटाने में बाधा के रूप में देखा जा रहा है, ये मुद्दे बाकू में विचार-विमर्श में हावी रहने वाले हैं।

जलवायु संकट पर ट्रंप की अड़ियल नीति के बारे में चिंता समझ में आती है। 1850-2022 के बीच अमेरिका 20% CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है और प्रति व्यक्ति 18 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है

समतुल्य (tCO2e) की तुलना में वैश्विक औसत 4.7 tCO2e है। वर्तमान में, चीन वैश्विक उत्सर्जन में सबसे आगे है, उसके बाद अमेरिका, भारत और यूरोपीय संघ का स्थान है।
अमेरिका द्वारा किसी भी नीति में बदलाव से वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के प्रयास पटरी से उतर सकते हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र पहले ही 3.1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की चेतावनी दे चुका है।
ट्रम्प ने, न भूलें, ग्रीन न्यू डील को समाप्त करने और मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम को निरस्त करने की धमकी दी है; उनके प्रशासन ने 2020 में पेरिस समझौते से हाथ खींच लिया। उन्होंने यह भी कहा है कि वह "ड्रिल, ड्रिल, ड्रिल" करेंगे।

हालाँकि, जलवायु परिवर्तन पर कई बहुपक्षीय समझौते हुए हैं। अमेरिकी एकतरफावाद के सामने जलवायु संकट से निपटने का रास्ता तैयार किया है। वास्तव में, अमेरिकी चुनाव परिणाम को, शायद, एक प्रोत्साहन के रूप में देखा जाना चाहिए
पेरिस समझौते को प्राप्त करने के लिए अधिक वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है।
समझौते के लक्ष्य। अमेरिकी प्रशासन ने, किसी भी मामले में, जलवायु पर सख्त रुख बनाए रखा है और ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मांग की है कि उभरती अर्थव्यवस्थाएं जलवायु पर कार्रवाई का बोझ उठाएं और प्रदान करने से इनकार कर दिया

पर्याप्त वित्त की कमी के कारण समानता और साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत कमजोर हो रहे हैं।
ट्रम्प 2.0 इसे और बदतर बना सकता है।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु बैठकों को किस प्रकार से अलग रखा जा सकता है? शासन परिवर्तन के झटके? सबसे पहले यह होगा कि यह माना जाता है कि जलवायु व्यवधान के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान उत्सर्जन को सीमित करने में होने वाली लागतों की तुलना में कहीं अधिक हैं।
दूसरा, जलवायु वित्त को विकसित देशों से विकासशील देशों में प्रवाहित किया जाना चाहिए जैसा कि सम्मेलन में निर्धारित किया गया है; वित्त के बिना, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, और यदि विकासशील देश जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहना जारी रखते हैं तो विकसित दुनिया को भी समान रूप से नुकसान होगा। तीसरा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) जैसे एकतरफा व्यापार उपाय अलग-थलग कर सकते हैं और नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं

विकासशील देशों में तनाव बढ़ने से पहले इन उपायों पर खुली बातचीत ज़रूरी है। चौथा, देशों को सुधारों को लागू करने के लिए बाज़ार की ताकतों पर भरोसा करना चाहिए।
दुबई में COP28 में, दुनिया ने ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के लिए एक न्यायसंगत, व्यवस्थित और न्यायसंगत तरीके से सहमति व्यक्त की। इसने वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा क्षमता को तिगुना करने और 2030 तक ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को दोगुना करने पर भी सहमति व्यक्त की।

दुबई से पहले भी, सौर और पवन ऊर्जा की घटती लागत ने जीवाश्म ईंधन से संक्रमण के लिए आर्थिक तर्क प्रदान किया था। यह एक वैश्विक प्रवृत्ति है - हालांकि भंडारण और संचरण की चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

अब इसका दायित्व अन्य विकसित देशों पर होगा। यूरोपीय संघ, चीन और भारत द्वारा खेल को आगे बढ़ाने के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर नेतृत्व प्रदान करें। बीजिंग वर्तमान में अग्रणी उत्सर्जक है, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा में भी अग्रणी है।
यह भारत के लिए भी एक अवसर है: जलवायु आपातकाल हमारे समय का अस्तित्वगत संकट है और भविष्य की विरासत इसके प्रभाव को कम करने के लिए प्रदान किए गए नेतृत्व के इर्द-गिर्द निर्मित होगी।

एक पीढ़ी को सशक्त बनाना भारत के स्वप्नदर्शी

रतन टाटा का जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्चे नेतृत्व को केवल किसी की उपलब्धियों से नहीं मापा जाता है, बल्कि सबसे कमजोर लोगों की देखभाल करने की क्षमता से मापा जाता है।

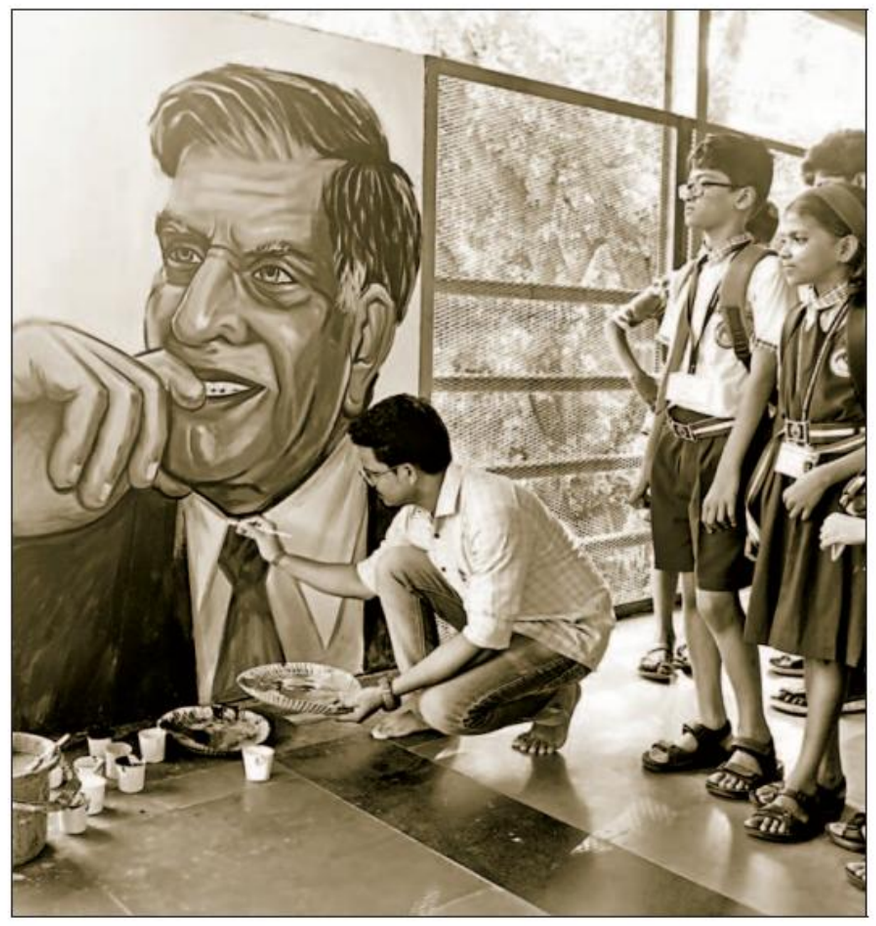

रतन टाटा उन लोगों के जीवन में जीवित हैं जिन्हें उन्होंने छुआ और जिन सपनों को उन्होंने संजोया। भारत को एक बेहतर, दयालु और अधिक आशावान स्थान बनाने के लिए पीढ़ियाँ उनकी आभारी रहेंगी एएनआई

नरेंद्र मोदी

मैं रतन टाटाजी को गुजरे एक महीना हो गया है हमें छोड़ दिया। हलचल भरे शहरों और कस्बों से गांवों में उनकी अनुपस्थिति का गहरा एहसास होता है समाज के हर वर्ग के अनुभवी उद्योगपति, नवोदित उद्यमी, और मेहनती पेशेवर शोक मनाते हैं उनके नुकसान के लिए हम सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। पर्यावरण के प्रति भावुक और परोपकार के लिए समर्पित लोग भी उतने ही दुखी हैं। उनकी अनुपस्थिति दुखद रही है।
पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसे गहराई से महसूस किया गया बल्कि विश्व भर में भी।

युवाओं के लिए रतन टाटा एक महान व्यक्तित्व थे। प्रेरणा, एक अनुस्मारक कि सपने प्रयास करने योग्य हैं और सफलता करुणा के साथ भी सह-अस्तित्व में रह सकते हैं विनम्रता के रूप में। दूसरों के लिए, उन्होंने भारतीय संस्कृति की बेहतरीन परंपराओं का प्रतिनिधित्व किया उद्यमशीलता और ईमानदारी, उत्कृष्टता और सेवा के मूल्यों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता। उनके नेतृत्व में,

टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ दुनिया भर में सम्मान, ईमानदारी और विश्वसनीयता। इसके बावजूद, उन्होंने अपनी उपलब्धियों को हल्के में लिया, विनम्रता और दयालुता के साथ.

रतन टाटा का अटूट समर्थन दूसरों के सपने उनकी सबसे परिभाषित चीजों में से एक थे हाल के वर्षों में, वह अपने गुणों के लिए जाने जाते हैं। भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मार्गदर्शन देने के लिए, कई आशाजनक उद्यमों में निवेश कर रहे हैं। लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को समझा युवा उद्यमियों को मान्यता दी गई भारत के भविष्य को आकार देने की उनमें जो क्षमता थी, उसका उपयोग करके। उनके प्रयासों का समर्थन करते हुए, उन्होंने सपने देखने वालों की एक पीढ़ी को साहसिक जोखिम उठाने और आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाया सीमाएँ।

इससे नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति का निर्माण करने में काफी मदद मिली है। मुझे विश्वास है कि इसका भारत पर आने वाले दशकों तक सकारात्मक प्रभाव पड़ता रहेगा।

उन्होंने हमेशा उत्कृष्टता की वकालत की और भारतीय उद्यमों से वैश्विक मानक स्थापित करने का आग्रह किया। मुझे उम्मीद है कि यह दृष्टिकोण हमारे उद्यमियों को प्रेरित करेगा। भविष्य के नेताओं को भारत का पर्याय बनाना होगा विश्व स्तरीय गुणवत्ता.

उनकी महानता यहीं तक सीमित नहीं थी बोर्डरूम या साथी इंसानों की मदद करना। सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा का भाव। पशुओं के प्रति उनका गहरा प्रेम जगजाहिर था और वह पशु कल्याण पर केंद्रित हर संभव प्रयास का समर्थन किया। वह अक्सर अपनी तस्वीरें साझा करते थे कुत्ते, जो उनके जीवन का उतना ही हिस्सा थे जितना किसी भी व्यवसाय उद्यम। उनका जीवन एक अनुस्मारक था हम सभी के लिए सच्चा नेतृत्व मापा जाता है, न कि सिर्फ़ अपनी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपनी योग्यता से भी सबसे कमजोर लोगों की देखभाल करना।

करोड़ों भारतीयों के लिए रतन टाटा का देशभक्ति उस समय सबसे अधिक चमकी संकट। उनके द्वारा शीघ्रता से पुनः खोले जाने से मुंबई में प्रतिष्ठित ताज होटल के बाद 26/11 आतंकी हमला एक एकजुटता का आह्वान था राष्ट्र के प्रति - भारत एकजुट है, आतंकवाद के आगे झुकने से इंकार कर दिया।

व्यक्तिगत रूप से, मुझे उन्हें बहुत करीब से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने गुजरात में मिलकर काम किया, जहां उन्होंने बड़े पैमाने पर निवेश किया। अभी कुछ सप्ताह पहले, मैं वडोदरा में था। स्पेन सरकार के राष्ट्रपति, पेड्रो सांचेज़ और हमने संयुक्त रूप से एक का उद्घाटन किया विमान परिसर जहां सी-295 विमान होंगे रतन टाटा ने ही इस पर काम करना शुरू किया था। कहने की ज़रूरत नहीं कि रतन टाटा की मौजूदगी की कमी बहुत खल रही थी।

मैं रतन टाटाजी को एक साहित्यकार के रूप में याद करता हूँ। - वह अक्सर मुझे विभिन्न विषयों पर पत्र लिखते थे मुद्दे, चाहे वह शासन का मामला हो, अभिव्यक्ति का सरकारी समर्थन के लिए सराहना, या चुनावी जीत के बाद बधाई संदेश भेजना।

रीस.

हमारे बीच घनिष्ठ संपर्क तब भी जारी रहा जब मैं वे केंद्र में आ गए और वे हमारे राष्ट्र निर्माण प्रयासों में एक प्रतिबद्ध भागीदार बने रहे।
स्वच्छ भारत के प्रति रतन टाटा का समर्थन मिशन मेरे दिल के बहुत करीब था। इस जन आंदोलन के मुखर समर्थक थे, यह समझना कि सफाई, स्वच्छता और स्वच्छता भारत की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। मैं अभी भी उनके हार्दिक वीडियो संदेश को याद करें स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ अक्टूबर की शुरुआत में। यह उनके अंतिम कार्यों में से एक था सार्वजनिक उपस्थिति.

युवाओं के लिए रतन टाटा एक प्रेरणा थे, एक अनुस्मारक कि सपने सच होने के लायक हैं और सफलता करुणा और विनम्रता के साथ मिल सकती है। दूसरों के लिए, उन्होंने भारतीय उद्यम की बेहतरीन परंपराओं और ईमानदारी, उत्कृष्टता और सेवा के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व किया।

उनके दिल के करीब एक और मुद्दा स्वास्थ्य था देखभाल और विशेषकर कैंसर के विरुद्ध लड़ाई। मुझे दो साल पहले असम में हुआ कार्यक्रम याद है। कुछ समय पहले, जहां हमने संयुक्त रूप से विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया था राज्य में कैंसर अस्पतालों में कैंसर के मरीजों की संख्या में वृद्धि के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अपने अंतिम वर्ष स्वास्थ्य को समर्पित करना चाहते थे स्वास्थ्य और कैंसर को बेहतर बनाने के उनके प्रयास देखभाल सुलभ और सस्ती थी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति, यह विश्वास कि न्यायपूर्ण समाज ही एकमात्र उपाय है जो सबसे कमजोर लोगों के साथ खड़ा था।

आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें उस समाज की याद दिलाई जिसकी उन्होंने कल्पना की थी - जहां व्यापार अच्छे कार्य के लिए एक शक्ति के रूप में कार्य कर सकता है, जहाँ हर व्यक्ति की क्षमता को महत्व दिया जाता है, और जहाँ प्रगति सभी की भलाई और खुशी से मापी जाती है। वह अभी भी जीवित है जिन जिंदगियों को उन्होंने छुआ और जिन सपनों को उन्होंने संजोया। आने वाली पीढ़ियाँ उनके प्रति आभारी रहेंगी भारत को एक बेहतर, दयालु और अधिक आशापूर्ण स्थान बनाना।

नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं

वित्तीय बातचीत का असहनीय भारीपन

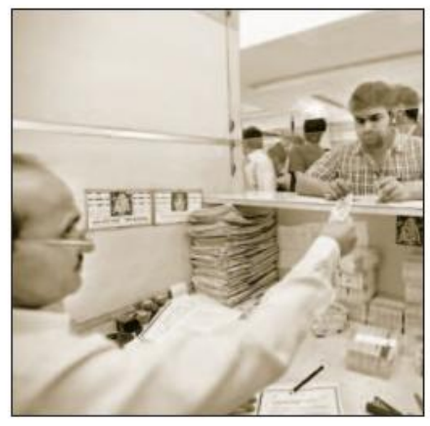

मोनिका हलान

संयुक्त व्यय और परिवार भर में लागतों के बंटवारे को लेकर पैसों को लेकर तनाव उत्पन्न होता है एचटी आर्काइव

मैं लंबे समय से पैसे के बारे में पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं के सवालों का जवाब दिया है मैंने उन्हें समय के साथ बदलते देखा है। पहले इसमें प्रवेश स्तर के प्रश्न होते थे बैंक में जमा ₹50,000 का क्या करें, कौन से स्टॉक और फंड खरीदें, परिसंपत्ति आवंटन के आसपास पोर्टफोलियो प्रश्न, रणनीति प्रश्न - इसके आसपास प्रश्नों की एक पूरी श्रृंखला

पैसे का निवेश। लेकिन जैसे ही मैं एक साल पूरा करूंगा मेरे ऑडियो-ओनली पॉडकास्ट के बारे में, कुछ गहरे सवाल आने शुरू हो गए हैं - झिझकते हुए, जिनमें से अधिकांश गुमनामी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिक स्थिरता से। ये हैं

परिवार और वित्तीय मामलों को लेकर, विरासत और कठिनाई पैसे के बीच बातचीत जीवनसाथी, और एक का पूर्ण मिथक बड़ा खुशहाल बड़ा भारतीय परिवार। हम त्यौहारों के दौरान एक साथ पार्टी कर सकते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से अदालत में भी मिलेंगे अगले दिन लाजपत नगर में फ्लैट पापाजी ने भैया को दिया था मुझे नहीं"।

परिवारों में वित्तीय तनाव शुरू जीवन के विभिन्न चरणों में उभरना। इसकी शुरुआत हो सकती है विवाह के बाद जब अलग-अलग मूल्य प्रणालियाँ होती हैं, खर्च करने की आदतें और जीवनशैली से जुड़ी ज़रूरतें खुद को जोड़े के रूप में पेश करना शुरू करें पहले फ्लश से लेकर लीक को ठीक करने तक की प्रक्रिया फ्लश। मुझे एक श्रोता से एक प्रश्न मिला जो अपनी पत्नी की जीवनशैली से संबंधित प्रबंधन नहीं कर सका ज़रूरतें। ऐसा लगता है कि वह एक ऐसी ज़िंदगी चाहती थी जो उसके वह इसे वहन नहीं कर सकता था और इसके लिए तैयार नहीं था एकल आय वाले घर में रहने के लिए खर्च में कटौती की गई। यह एक ऐसी ट्रेन थी जो विनाश की ओर जा रही थी।
एस्टर जो या तो कर्ज या तलाक में समाप्त होगा, संभवतः दोनों.

हालांकि मध्यम वर्ग के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है भारत और उसके वैवाहिक कलह के कारण, आंकड़े संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.) से पैसे की ओर इशारा करता है तलाक के प्रमुख कारणों में से एक है। एक अध्ययन तलाक वित्तीय विश्लेषण संस्थान द्वारा (tinyurl.com/5h2eejaz) ने पैसे के मुद्दे को मुद्दा बनाया 22% मामलों में यह तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि विवाह क्यों नहीं होता असफल, 43% पर बुनियादी असंगति के बाद आता है और बेवफाई 28% है। इसमें यह भी कहा गया है कि बुनियादी असंगति भी इसमें शामिल है पैसे के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों के इर्द-गिर्द तनाव। ऐसी कहानियाँ

दोनों तरह से काम करें। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ ऐसे जोड़े जहां पत्नी कमाती है और पति पति की जीवनशैली की जरूरतों को ध्यान में रखें उसे जुए में जोत दिया गया।

अगला चरण वह है जब वयस्क बच्चे घर पर ही रहना चुनते हैं।
उनके माता-पिता। जबकि बड़े विस्तारित भारत में परिवारों का एक साथ रहना आम बात है, नई शहरी वास्तविकता ज्यादातर परमाणु है। लेकिन शहरों में भी साथ रहने का विकल्प तनाव हमेशा बना रहता है, खासकर तब जब एक युवा परिवार के लिए नई संपत्ति बनाना बहुत मुश्किल होता है। संयुक्त व्यय के इर्द-गिर्द धन के बारे में जानकारी उभरती है और परिवार भर में लागतों का बंटवारा। शुद्धतावादी इन पर चर्चा करने के किसी भी प्रयास का उपहास करते हैं मुद्दे, लेकिन अधिकांश तीन-सीट-सोफा रहने वाले कमरों में कालीन के नीचे, दबाए गए क्रोध की कहानियां हैं क्योंकि परिवार का एक हिस्सा खींचता है

लेकिन बढ़ती संख्या को देखते हुए इस क्षेत्र के बारे में मेरे लिए सबसे पहले सवाल यही है कि बदलाव की जरूरत है। निष्पक्ष होने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि युवा लोगों की आय सामान्य लोगों की तुलना में बहुत कम है उनके करियर का चरम, संयुक्त रूप से विभाजित होना है आनुपातिक आधार पर खर्च। प्रत्येक योगदान देता है बराबरी के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार खर्च का हिस्सा। किसी बिंदु पर, यह वृद्धों की सेवानिवृत्ति के बाद समीकरण बदलेगा कोहोर्ट - इसलिए वार्षिक अद्यतन की आवश्यकता है अनुपात बदलें.

संभवतः सबसे विवादास्पद चरण वह है जब विरासत के मुद्दे हैं। और विरासत में, संपत्ति सबसे बड़ी वस्तु बनी हुई है

वित्तीय परिसंपत्तियों को खरीदना कहीं अधिक आसान है वसीयत करना और इसके लिए आमतौर पर नामांकन की आवश्यकता होती है वसीयत और मृत्यु प्रमाण पत्र द्वारा स्थानांतरित होने के लिए पैसा नहीं, बल्कि अचल संपत्ति है जो कई बार अदालत में पहुंच जाते हैं। नीति अनुसंधान रिपोर्ट (tinyurl.com/37jyfvr9) अनुमान है कि सभी मामलों में से लगभग एक चौथाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भूमि से संबंधित निर्णय विवादों और सभी सिविल मामलों का तीन-पांचवां हिस्सा भारत में संपत्ति विवाद से संबंधित मामले हैं। बेशक, सभी विरासत से जुड़े नहीं हैं, लेकिन इनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

हालाँकि, माता-पिता के पैसे के मुद्दे शायद हल न हों यह उतना ही सरल है कि किसे क्या मिलता है, लेकिन हो सकता है कई आयाम। एक श्रोता ने पाया कि उनकी माँ, जो एक स्कूल शिक्षिका हैं, ने उनसे गृह ऋण लिया था। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक एक साल पहले पदभार ग्रहण किया। उनसे पूरी तरह से ऋण लेने की उम्मीद थी उनकी कड़ी मेहनत से हासिल की गई वित्तीय स्थिरता नष्ट हो गई। एक अन्य व्यक्ति अपने परिवार के घर के लिए अपनी बहनों को मुआवजा देने के लिए धन जुटाना चाहता था। विरासत में मिला।

बहुत सारे मतभेदों से बचा जा सकता है यदि हम स्पष्ट रूप से बता देंगे कि हम क्या बनना चाहते हैं हमारे जाने के बाद हमारी संपत्तियों के साथ क्या किया जाएगा। लेकिन यहां तक कि मृत्यु का विषय भी भावनात्मक हो जाता है कई घरों में बम धमाका होता है। अगर बातचीत की शुरुआत बेटा या बेटी करते हैं, तो दो तरह के बम होते हैं। प्रतिक्रियाएँ - आप अपने हिस्से के लिए लालची हैं या क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, लेकिन बस एक इच्छा है कि हमारे बीच कोई बड़ा मुद्दा न हो भाई-बहनों के निधन के बाद नामांकन और इच्छाशक्ति दूसरे चरण के निर्णय हैं, पहला चरण है हम यह तय करेंगे कि हमारे जाने के बाद किसे क्या मिलेगा।

जैसे-जैसे मैं अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता हूँ पैसे और रिश्तों के इन मुद्दों के इर्द-गिर्द, मुझे लगता है कि एक गैर-भावनात्मक, बोझ-मुक्त दृष्टिकोण सबसे अच्छा काम करता है। अगर हम अलग हो सकते हैं

अतीत की घटनाओं की लौह-जंजीरें जो हमें बताती हैं आज ही प्रतिक्रियाएँ लें और पैसे से जुड़े फ़ैसले लें निष्पक्षता, तर्कसंगतता और जिम्मेदारी बनाए रखना मन में जो बात होगी, उससे हमारा जीवन हल्का हो जाएगा। भारतीय न्यायालयों की स्थिति

अस्वीकरण: मैं केवल रणनीति संबंधी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ पॉडकास्ट पर, व्यावसायिक रूप से अभ्यास न करें और किसी विशिष्ट उत्पाद की अनुशंसा नहीं करते हैं।

मोनिका हालन इस पुस्तक की सर्वाधिक बिकने वाली लेखिका हैं। पैसे पर पुस्तकों की श्रृंखला 'चलो बात करते हैं'। व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं

{ किसी और दिन }

नमिता भंडारे

1984 के सिख विरोधी दंगे: भारत का न भरा घाव

एक भीड़ द्वारा दर्शन कौर की हत्या के बाद पति जल गया, उसने उसे इकट्ठा किया तीन बच्चे, सबसे छोटा अभी-अभी 15 दिन पुराना है, और बोल्टेड है। उन्माद, बच्चा 19 वर्षीय से फिसल गया दर्शन के हाथ। लेकिन समय नहीं था। अगले तीन दिनों तक वह और शेष दो बच्चे भाग गए पुलिस थाने से लेकर गुरुद्वारा तक तलाश कर रही है एक सुरक्षित जगह।

तीन दिन तक कोई नहीं मिला।
31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके सिख अनुयायियों द्वारा हत्या के बाद के दिनों में अंगरक्षकों, राजधानी शहर उपरिकेंद्र था यह एक सामूहिक नरसंहार का मामला है, क्योंकि कथित तौर पर कांग्रेस नेताओं द्वारा उकसाई गई और राजीव गांधी के इस बयान से प्रेरित होकर कि, "जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, तो जमीन हिलती है", भीड़ ने निर्दोष सिखों को निशाना बनाया।

सरकारी अनुमान के अनुसार, लगभग 2,800 दिल्ली में मारे गए लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फुल्का का अनुमान है कि यह संख्या 4,000 के करीब थी।

त्रिलोकपुरी में दर्शन कौर के 12 पुरुष रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई। उसने एक आदमी को देखा काला चश्मा और सफेद कुर्ता पायजामा भीड़ को निर्देश दिए। अदालत में, उसने उनकी पहचान अब दिवंगत कांग्रेस नेता एचकेएल भगत के रूप में हुई।

अपराधी ठहराया हुआ।

अंततः केवल 587 एफआईआर दर्ज की गईं। जिसके परिणामस्वरूप मुश्किल से दो दर्जन लोगों को सजा मिली। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 33 साल लग गए उस समय संसद सदस्य, 30 अगस्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस वर्ष, एक ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने एक अन्य कांग्रेस सदस्य के विरुद्ध आरोप तय करने का आदेश दिया। नेता, जगदीश टाइटलर।

"क्या हम उस देश के नागरिक नहीं हैं जो दर्शन कौर पूछती हैं, "क्या आपको न्याय मिलना चाहिए?" "लेकिन समाज हमें भूल गया है।"

उन दिनों को याद करने के लिए, फुल्का, जिन्होंने वर्षों तक पीड़ितों के लिए निःशुल्क कार्य किया 1984 के दंगों के बारे में हाल ही में एक वीडियो जारी किया गया इस सीरीज को उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया था। महीने में, सनम सुतिर-अथ वज़ीर द्वारा 1984 की कौरें सीमित साहित्य में जोड़ी गईं दंगों पर.

हालांकि इन्हें देखना या पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन संक्षिप्तीकरण के युग में आवश्यक परिवर्धन ध्यान अवधि। यदि न्याय विफल हो गया है, तो कम से कम इसका कोई रिकॉर्ड तो है; एक दस्तावेज भारत के सबसे शर्मनाक अध्यायों में से एक।

1984 पहले ही राष्ट्रीय इतिहास से पीछे छूट चुका है चेतना और जो लोग रहते थे उन दिनों के लोग अब बूढ़े हो चुके हैं या मर चुके हैं। मैं कॉलेज में था और अपने माता-पिता के साथ रहता था मुझे याद है कि जब मैं ऊपर देख रहा था तो आसमान आग की लपटों से लाल हो गया था। झंडेवालान में टायर की दुकानें सबसे ज्यादा हैं सिखों के स्वामित्व में है।

सोनिया सिर्फ तीन साल की थी जब उसका परिवार, 13 वर्षीय बहन को छोड़कर बाकी सभी की हत्या कर दी गई। उन दिनों की यादें धुंधली हैं, लेकिन वह वह इसे अपनी जिम्मेदारी समझती है कि उसे यह जिम्मेदारी दी जाए बेटा उसकी बहन ने उसे क्या बताया - भीड़ ने उसे कैसे मारा पुरुषों, यहाँ तक कि बच्चों को भी निशाना बनाया गया। कई लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई क्योंकि शर्म करो।

दर्शन कौर अंततः पुनः मिल गईं एक और महिला अपने खोए हुए बच्चे के साथ उसे ढूंढ लिया और सुरक्षित रख लिया। यह शायद उसकी कहानी में एकमात्र सकारात्मक बात यह थी कि 17 वर्षीय पोती, इशप्रीत, अब 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा कहती है कि वह अपने दादा को कभी नहीं जान पाई: "लेकिन क्योंकि हमें कभी न्याय नहीं मिला, हम कभी नहीं भूल सकते।"

नमिता भंडारे लिंग पर लिखती हैं। व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं

{ संपादक की पसंद }

एचटी के संपादक हर शनिवार को एक पुस्तक की सिफारिश करते हैं, जो इतिहास, संदर्भ प्रदान करती है और हाल की समाचार घटनाओं को समझने में मदद करती है

पेड़ों की कहानी

इससे बुरी खबर और कुछ नहीं हो सकती थी बाकू, अज़रबैजान में जलवायु वार्ता के लिए - 2024 के लिए औसत वैश्विक तापमान, जो अब तक का सबसे गर्म वर्ष होगा यह तापमान पूर्व-औद्योगिक युग से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा, जो कि अब तक का सबसे अधिक तापमान है। ध्यान रखें कि पेरिस समझौते में सीमाएं तय की गई हैं। तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। इससे चिंता पैदा हुई और जलवायु संकट के बारे में बातचीत।

बेशक, इस बारे में बात करने के कई तरीके हैं जलवायु संकट और पर्यावरण। रिचर्ड पॉवर्स 2018 का उपन्यास द ओवरस्टोरी कल्पना के माध्यम से ऐसा करता है लेखन। लोग कथानक को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पाठक वह हमेशा से जानता है कि पेड़ ही इसके असली नायक हैं। प्रोग्रामर से लेखक बने पॉवर्स ने नौ किताबें लिखीं ऐसे पात्र जिनके जीवन में वृक्षों का समावेश हुआ है क्षमता या अन्य - एक पारिवारिक "विरासत", एक उद्धारकर्ता, यहां तक कि एक खलनायक (एक तरह का) - वनों की कटाई के बारे में बात करने के लिए, इसके प्रभाव, और पाठ्यक्रम सुधार। गैर-काल्पनिक लेखन के बंधनों के बिना, पॉवर्स इसे बनाने में सक्षम है समस्या बौद्धिक से कम और शारीरिक से अधिक जुड़ी हुई है पाठक के लिए, इस प्रकार जलवायु संबंधी कार्य करना।

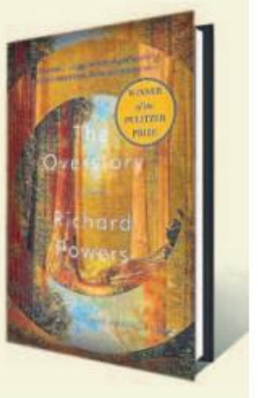

ओवरस्टोरी:
रिचर्ड पॉवर्स
वर्ष: 2018

आरएनआई संख्या 503/1957 • डाक पंजीयन संख्या डीएल(एनडी)-11/6058/2018-19-20 'पूर्व भुगतान के बिना पोस्ट करने का लाइसेंस' लाइसेंस संख्या यू(सी)-113/2006-08, हवाई अधिभार: रायपुर और उससे आगे रेल या सड़क मार्ग से - रु. 5/-, अहमदाबाद, बैंगलोर, कोयंबटूर, चेन्नई, कोचीन, गोवा, हैदराबाद, खजुराहो, मुंबई, त्रिवेंद्रम, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और उससे आगे रेल या सड़क मार्ग से - रु. 10/-;

एचटी मीडिया लिमिटेड की ओर से मनहर कपूर द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित , 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 तथा प्लॉट संख्या-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) स्थित एचटी मीडिया लिमिटेड प्रेस में मुद्रित, पिन-201306।
बोर्ड: (011) 23361234 • संपादकीय: (011) 66561234 एक्सटेंशन 1254, 1268 • प्रसार: (011) 66561111 • विज्ञापन: (011) 66561389 • फैक्स: (011) 66561270.

संपादक: कुणाल प्रधान - पीआरपी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेदार, @ सभी अधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्ण या आंशिक रूप से पुनरुत्पादन निषिद्ध है।

Machine Translated by Google

EDITORIAL

"महासंघ एक संघ है क्योंकि यह अविनाशी है"

बीआर अम्बेडकर

इंडियन एक्सप्रेस एक उद्योग नहीं है। यह एक मिशन है।

— रामनाथ गोयनका

व्यावहारिक व्यावसायिक सूझबूझ से अमेरिकी टैरिफ़ खतरे को मात दी जानी चाहिए

डोनाल्ड ट्रम्प की अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में वापसी से भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर विशेष ध्यान केन्द्रित होगा।

ट्रंप ने अपने 'अमेरिका फर्स्ट' रुख के तहत टैरिफ की एक नई लहर का वादा किया है, जो भारत जैसे देशों और उसके प्रमुख क्षेत्रों जैसे आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, रसायन और ऑटोमोटिव पार्ट्स पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ऑटोमोबाइल जैसे विशिष्ट उद्योगों में भारत के टैरिफ से ट्रंप की नाराजगी उनके पहले कार्यकाल के दौरान पूरी तरह स्पष्ट थी; पिछले महीने तक, उन्होंने पारस्परिक टैरिफ लगाने की अपनी धमकी जारी रखी, भारत को "सबसे बड़ा टैरिफ चार्जर" करार दिया। उन्होंने यहां तक कि सभी क्षेत्रों में आयात शुल्क में 10-20 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव रखा, जो संभावित रूप से व्यापार संतुलन को बदल सकता है जो 2023-24 में 35.3 बिलियन डॉलर के अधिशेष के साथ भारत के पक्ष में बना हुआ है। संयोग से, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है पिछले दशक में व्यापार 2023-14 में 61.5 बिलियन डॉलर से लगभग दोगुना हो गया है, लेकिन ट्रम्प 2.0 टैरिफ का डर भारतीय निर्यातकों को परेशान कर रहा है।

जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, भारतीय मुद्रा और इक्विटी बाजार ट्रम्प 2.0 की संभावना से बहुत उत्साहित नहीं हैं। रुपया 17 पैसे गिरकर 84.28 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया, गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट आई, जिससे फैसले के बाद हुई सारी बढ़त खत्म हो गई। ऐसा कहा जाता है कि अगर ट्रम्प वास्तव में चीन से अलग होने के लिए दबाव डालते हैं, जहां वे 60 प्रतिशत तक टैरिफ लगाना चाहते हैं, तो यह कदम भारत को संभावित रूप से अधिक अमेरिकी कंपनियों को आकर्षित करके लाभ पहुंचा सकता है जो आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना चाहती हैं। नोमुरा की एक हालिया रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि व्यापार और आव्रजन पर संभावित तनाव के बावजूद, भारत ट्रम्प की नीतियों से लाभान्वित हो सकता है जो आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए चीन से दूर ले जाती हैं।

दिलचस्प बात यह है कि हालांकि कई लोगों को डर है कि भारतीय निर्यातकों को ट्रंप 2.0 के तहत उच्च सीमा शुल्क का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वे यह भी उम्मीद और अनुमान लगाते हैं कि आने वाला अमेरिकी प्रशासन व्यापार करने में व्यावहारिक और लेन-देन वाला बना रहेगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापस आने से भारत-अमेरिका संबंधों के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों ही मिल सकती हैं। यह देखना अभी बाकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके द्वारा साझा की गई गर्मजोशी एच1-बी वीजा नीति को सख्त करने के कारण संभावित जोखिमों को कम करने में मदद करेगी या नहीं। संतुलन पर, दोनों के पास एक ऐसी साझेदारी बनाने का अवसर है जो न केवल भारत और अमेरिका के लिए फायदेमंद है, बल्कि वैश्विक व्यापार असंतुलन को बहाल करने में भी मदद करती है।

देखभाल के लिए मानदंड तय करें बंदी हाथियों के लिए

केरल का हाथियों के साथ हमेशा से ही एक जटिल रिश्ता रहा है, जो राज्य के सांस्कृतिक इतिहास का एक अभिन्न अंग रहे हैं। जबकि हाथियों को हमेशा से मलयालम साहित्य और संस्कृति में एक पंथ का दर्जा प्राप्त रहा है, वे पैसे कमाने का एक ज़रिया भी रहे हैं जिन्हें धार्मिक उत्सवों और निजी समारोहों में परेड के लिए राज्य भर में ले जाया जाता है और उन्हें अकल्पनीय यातनाएँ दी जाती हैं।

बंदी हाथियों की दुर्दशा पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बनी हुई है, यहाँ तक कि न्यायपालिका ने भी इस मुद्दे को उठाया है। केरल उच्च न्यायालय ने बंदी हाथियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी और न्यायमित्र ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

रिपोर्ट में हाथियों के जुलूसों के लिए सख्त नियम बनाने, उनके इस्तेमाल को सीमित करने और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है। इसमें हाथियों का इस्तेमाल केवल धार्मिक समारोहों के लिए करने की सलाह दी गई है, उद्घाटन जैसे निजी आयोजनों के लिए नहीं। इसमें जानवरों की भलाई के लिए जुलूसों के बीच 24 घंटे का अनिवार्य आराम भी शामिल है। रिपोर्ट में आगे सुझाव दिया गया है कि हाथियों को प्रतिदिन 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं ले जाया जाना चाहिए। इसमें जुलूसों में हाथियों के बीच कम से कम तीन मीटर का अंतर और कार्यक्रमों में दर्शकों और हाथियों के बीच 10 मीटर की दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। एमिकस क्यूरी ने सिर उठाने की प्रतियोगिता, झुककर प्रणाम करने और फूल बरसाने पर भी रोक लगाने की सिफारिश की है। एमिकस क्यूरी ने जोर देकर कहा कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के हाथियों का इस्तेमाल जुलूसों में नहीं किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए, न्यायालय ने टिप्पणी की, "यह आभारी होने का कारण है कि व्हेल भूमि पर नहीं रहती हैं।" जंगली जानवरों को कैद में रखने के प्रति दृष्टिकोण समय के साथ बदल गया है; न्यायाधीश की टिप्पणी इस परिवर्तन को दर्शाती है। संस्कृति की खातिर हाथियों के साथ क्रूरता करना आधुनिक संवेदनशीलता से मेल नहीं खाता है, भले ही अतीत में इस तरह की प्रथाएँ कितनी भी मूल्यवान क्यों न रही हों। हालाँकि भारत में केरल में सबसे अधिक संख्या में बंदी हाथी हैं, लेकिन यह मुद्दा केवल राज्य तक ही सीमित नहीं है। भारत में 3,500 से अधिक बंदी हाथियों का उपयोग वन शिविरों, यात्रा, पर्यटन और चिड़ियाघरों और मंदिरों में किया जाता है। हालाँकि उन सभी को जंगल में छोड़ना कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वे जीवित नहीं रह पाएँगे, लेकिन सीमित कैद में उन्हें अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। हाथियों की दुर्दशा के प्रति बढ़ती सामाजिक संवेदनशीलता को अधिकारियों को इस संवेदनशील विशालकाय जानवर के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

त्वरित ले लो

नफरत की लहरों को शांत करना

यूरोपा लीग के बाद देश की राजधानी में भड़की हिंसा डच पुलिस से शुरुआत में 62 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि कुछ रिपोर्टों ने इसे यात्रा करने वाले इज़रायली प्रशंसकों पर लक्षित यहूदी-विरोधी हमला कहा, अन्य ने मैकाबी प्रशंसकों को स्थानीय अरबों को फ़िलिस्तीन-विरोधी नारे लगाते हुए दिखाया। चाहे जो भी उकसावा हो, ऐसी हिंसा की दोनों पक्षों द्वारा निंदा की जानी चाहिए। भारत एक ऐसा दुर्लभ देश है जिसका यहूदी-विरोधी इतिहास नहीं है।

हर साल हमारे देश का दौरा करने वाले इज़रायलियों को ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर भारतीयों को भड़काना नहीं चाहिए। और भारतीय नागरिक समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर ऐसी आग भड़कती है, तो उसे भड़कने से पहले ही बुझा दिया जाए।

हम सामाजिक-आर्थिक वर्गों और संघीय राजनीति के बीच व्यापक विभाजन देखते हैं। हमें कुछ चुनिंदा लोगों को समृद्ध करने के बजाय सभी की भलाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए

अब समय आ गया है आर्थिक प्रजातंत्र

के.एम. चंद्रशेखर
पूर्व कैबिनेट सचिव और लेखक
जैसा अच्छा है मेरा शब्द: ए इतिहास

डब्ल्यू जब मैं कैबिनेट सचिव के पद पर कार्यरत था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुझसे आग्रह करते थे कि मैं उनसे कम से कम सप्ताह में एक बार व्यक्तिगत रूप से मिलूं। अगर मैं एक सप्ताह में उनसे मिलने से चूक जाता तो वे अपने सौम्य तरीके से नाराज़गी व्यक्त करते। जब भी मैं उनसे मिलता, तो वे इस सवाल से शुरू करते, "देश की स्थिति क्या है?" मैं उन्हें आंतरिक सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद, प्रशासन, उल्लेखनीय घटनाओं और मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी देता। उनका ध्यान मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर केंद्रित रहता था।

अगर मुझसे अब यह सवाल पूछा जाए, तो मेरा जवाब क्या होगा? मैं कहूंगा कि समाज में नफरत और विभाजन का स्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी कम है, और हम निर्विवाद रूप से ज्वालामुखी के शीर्ष पर बैठे हैं। मैं कहूंगा कि आय पिरामिड अभी भी विषम है, अरबपति अमीर होते जा रहे हैं और मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग और निराश्रित अभी भी आशा से वंचित हैं।

आर्थिक नीति बहुत अमीर लोगों के लिए बनाई गई है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि राज्यों का मानना है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय संसाधनों का बहुत बड़ा हिस्सा हड़प रही है और वित्त आयोग की सिफारिशों को चतुराई से दरकिनार किया जा रहा है।

फिर भी, इस साल के दौरान देश में बहुत बड़ा बदलाव आया है। साल के पहले हिस्से में उम्मीद थी कि मोदी और उनकी सरकार 2014 और 2019 के समान बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी, शायद उससे भी ज़्यादा।

मुझे दिल्ली में सिविल सेवा अधिकारी संस्थान में एक लंच की याद आती है, जहाँ मैंने उम्मीद जताई थी कि चुनाव के बाद संसद में संतुलन बना रहेगा और कोई भारी बहुमत नहीं होगा। राजनीति में आए एक सहकर्मी ने मुझे बताया कि भाजपा उसी तरह, या उससे भी ज़्यादा, बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी। अयोध्या में मंदिर उद्घाटन में शामिल हुए एक मित्र ने लिखा कि चुनाव हो चुका है और मतपेटी सिर्फ़ औपचारिकता रह गई है।

यह तर्क से परे नहीं लग रहा था क्योंकि विपक्ष ने शुरुआत में ही अपनी कमर कस ली थी, एकजुट होने की कोशिश की, लेकिन फिर कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस ने जब यह तय कर लिया कि वे अपने दम पर जीत सकते हैं, तो उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में करारी हार के बाद वे फिर से इंडी गठबंधन की अवधारणा पर आ गए।

चुनाव प्रचार में पिछले चुनावों के विपरीत, गाली-गलौज वाली भाषा का खुलकर इस्तेमाल किया गया। मुसलमानों को घुसपैठिया कहा गया, धमकी दी गई-

सौरव रॉय

मतदाताओं की बहनों और बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई। कहा गया कि वे "अधिक बच्चे" पैदा करेंगे, जिससे हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। कहा गया कि अयोध्या में राम मंदिर को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा और गैर-भाजपा सरकार मुसलमानों को प्राथमिकता देगी, यहां तक कि खेलों में भी। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के लिए 'दीमक' शब्द का इस्तेमाल किया गया।

दूसरी तरफ से भी नफरत की आग उगली गई। 2019 के चुनाव में कांग्रेस का नारा था 'चौकीदार चोर है' । इस साल के चुनाव में सुर अलग थे, विपक्ष ने कहा कि वे 'मोहब्बत की दुकान' का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि भाजपा 'नफ़रत की दुकान' का। इसी समय, जाति विभाजन का मुद्दा बन गई।

आज भी कई मोर्चों पर मतभेद जारी हैं, जो सोशल मीडिया में हिंसक भाषा के कारण और भी बढ़ गए हैं। अंतर भाजपा और उसके मूल संगठन आरएसएस के बीच हुए समझौते में है। साल के पहले हिस्से में आरएसएस को अलग-थलग महसूस हुआ, भाजपा अध्यक्ष ने यहां तक कहा कि वे अब अपने दम पर काम कर सकते हैं और आरएसएस, एक वैचारिक मोर्चे की उतनी जरूरत नहीं है जितनी पहले थी।

आरएसएस केंद्र के हाथों में सत्ता के संचय और बुलडोजर तथा ईडी, सीबीआई और एनआईए के अंधाधुंध इस्तेमाल के पक्ष में नहीं था। उन्हें गृहयुद्ध और भारत के विखंडन की आशंका थी। केंद्र को जिस सीमित अंतर से काम करना पड़ता है और प्रबंधन के लिए अन्य दलों पर उसकी निर्भरता

आर्थिक मोर्चे पर, जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय पर ध्यान केंद्रित करने से, अन्य मानव विकास संकेतकों की अनदेखी करने से ऐसी नीतियाँ बन सकती हैं जो असमानताओं को तेज़ी से बढ़ाएँगी। भारत की जीडीपी 2010 में 1 ट्रिलियन डॉलर, 2017 में 2 ट्रिलियन डॉलर और 2020 में 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गई। समय के साथ, यह 5 ट्रिलियन डॉलर और उससे भी आगे पहुँच जाएगी, लेकिन अगर कुछ लोग 4.8 ट्रिलियन डॉलर और बाकी लोग बाकी को साझा करते हैं, तो यह किसी भी तरह से समृद्धि का संकेत नहीं है।

हमें 'आर्थिक लोकतंत्र' की आवश्यकता है, जो कुछ चुनिंदा लोगों की निरंतर समृद्धि के बजाय हमारी संपूर्ण आबादी के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता हो।

इसके लिए हमें अपनी सोच में बदलाव करना होगा - विकास के संकेतकों के रूप में प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी से हटकर मानव विकास संकेतकों पर ध्यान देना होगा। 16वें वित्त आयोग को राज्यों की ज़रूरतों पर ध्यान से विचार करना होगा, ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण पर अपनी सिफारिशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र का सुझाव देना होगा, केंद्र द्वारा विचलन के बिना, और क्षैतिज हस्तांतरण के मापदंडों को बदलना होगा ताकि राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा अधिक न्यायसंगत हो।

विदेशी संबंधों में हम महान वैश्विक नेताओं के रूप में पहचाने जाने और विदेशों में विवादों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सार्क, जिसमें हमारे सबसे करीबी पड़ोसी शामिल हैं, अभी भी कोमा में है। अब जबकि जम्मू-कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं और लोकतंत्र आंशिक रूप से बहाल हो चुका है, तो शायद यह सार्क और साफ्टा के पुनरुद्धार और आपसी चर्चाओं का समय है, जो हमें आर्थिक मोर्चे पर भी मजबूत करेगा।

आने वाले संकटों से निपटने के लिए हमारे देश को आगे ले जाने के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाले नेतृत्व की आवश्यकता है।

(ये मेरे निजी विचार हैं)
(kmchandrasekhar@gmail.com)

नम्बी-पाम्बी उदारवादी बनाम फिक्स-इट रूढ़िवादी

प्रतीक कांजीलाल
वर्षों से लेखक आश्चर्यजनक रूप से सहिष्णु जनता से सहजता से बात करते रहे हैं।

स्पीकईज़ी

डोनाल्ड ट्रम्प अपनी वापसी को एक चमत्कार के रूप में प्रस्तुत करते हैं और दुनिया को महीनों तक इस बात पर बहस का सामना करना पड़ता है कि उन्होंने क्या सही किया और कमला हैरिस ने क्या गलत किया।

हम उम्मीदवारों पर नज़र रखने का काम पंडितों पर छोड़ देंगे। आगे जो कुछ भी बताया गया है, वह उन मतदाताओं के अवलोकन पर आधारित है जो वास्तव में चुनाव के नतीजों को निर्धारित करते हैं। हम चुनाव में सामने आए कुछ रहस्यों पर भी नज़र डालेंगे। इनमें से कोई भी धागा मानव स्वभाव या बुद्धिमत्ता को अच्छी रोशनी में नहीं दिखाता है।

मुख्य रहस्य यह है कि एक ऐसे राष्ट्र में, जो कानून को बहुत गंभीरता से लेता है (अदालत में होने वाले नाटकों और पुलिस धारावाहिकों की संख्या इसकी गवाही देती है), अधिकांश अमेरिकियों ने एक अभियोजक को क्यों अस्वीकार कर दिया और एक ऐसे अपराधी को क्यों अपनाया जो अनिश्चित ढंग से सोचता है, धमकी भरे लहजे में बोलता है और सभी को पीड़ा पहुंचाने का वादा करता है?

इसके दो उत्तर हैं, और पहला उत्तर बहुत ही मूर्खतापूर्ण है: ट्रम्प के समर्थक उन्हें एक मनोरंजनकर्ता के रूप में पहचानते हैं। क्या स्टैंड-अप कॉमेडियन भी अभद्र नहीं होते? मनोरंजनकर्ता अच्छे सरकार प्रमुख बन सकते हैं, जैसे यूक्रेन में वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और अमेरिका में रोनाल्ड रीगन। अगर टेलर स्विफ्ट राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ती हैं, तो वह वास्तव में जीत सकती हैं।

लेकिन मनोरंजन करने वाले के रूप में पहचाने जाने वाले पेशेवर राजनेता एक अलग प्रजाति हैं, खासकर यदि मनोरंजन शासन को प्रभावित करता है।

ट्रम्प को चुनने का दूसरा कारण ज़्यादा ठोस है: बिडेन प्रशासन के तहत कामकाजी वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहा था, डेमोक्रेट्स इस बात से इनकार कर रहे थे, और दूर-दराज़ के दक्षिणपंथी अभियान की रणनीति आश्वस्त करने वाली लग रही थी। एक बार फिर, यह अर्थव्यवस्था थी, और डेमोक्रेट्स बेवकूफ़ी कर रहे थे।

ट्रम्प ने जो बिडेन को एक ऐसे मूर्ख के रूप में पेश किया है जिसने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया।
सच्चाई यह है कि महामारी के बाद बिडेन प्रशासन ने अर्थव्यवस्था को बचाया।

अपने विजय भाषण में ट्रम्प ने दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया। यह मुश्किल नहीं होना चाहिए: अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले से ही दुनिया की सबसे स्वस्थ अर्थव्यवस्था है।

लेकिन अर्थव्यवस्था के बारे में तथ्यों, जिन्हें समझने में बहुत कम लोग सक्षम हैं, और धन के मूल्य तथा जीवन की गुणवत्ता के बारे में रोजमर्रा की धारणाओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।

श्रमिक वर्ग के लोग इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि उनके द्वारा घर लाए जाने वाले सामानों की संख्या महामारी से पहले की तुलना में कम रह गई है।

अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन घर के बजट में सुधार नहीं हुआ है - और लोग परेशान हैं क्योंकि ट्रंप जिसे 'डीप स्टेट' कहते हैं, उसे उनका दर्द समझ में नहीं आया। ट्रंप उदासीन रूप से शिक्षित रूढ़िवादी पुरुषों से अपील करते हैं, खास तौर पर वह जनसांख्यिकी जो अपने परिवारों का भरण-पोषण न कर पाने पर अपमानित महसूस करती है।

'डू-' की एक कम अनुकूल मजबूरी आंकड़ों का दावा है। अपराध दर वास्तव में गिर रही है। और सरकार के पास लाखों अवैध अप्रवासियों का पता लगाने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं है। ट्रम्प का अप्रवासी-अनुदान विरोधी अभियान दिल दहला देने वाला राजनीतिक नाटक पैदा करेगा, न कि वास्तविक सफ़ाई।

लेकिन यहाँ एक रहस्य है: ट्रम्प के अभियान द्वारा उन पर किए गए नस्लवादी अपमान के बावजूद लैटिनो ने ट्रम्प का समर्थन क्यों किया? क्योंकि जो अप्रवासी पहले से ही अमेरिकी कार्यबल में शामिल हो चुके हैं, वे अवसर खोने के डर से अपने समुदाय से आगे के अप्रवास का विरोध करते हैं।

अमेरिका में आप्रवासन हमेशा से ही अलग रहा है। ब्रिटेन, इटली और जर्मनी जैसे 'घरेलू देशों' से आने वाले लोगों का मध्य अमेरिकी देशों से आने वाले गरीब आप्रवासियों की तुलना में अधिक स्वागत किया जाता है।

अब, उन देशों के भीतर नस्लवादी विभाजन नए आप्रवासियों को रोकने के लिए उभर रहा है।

गर्भपात के अधिकार हैरिस के लिए एक प्रमुख मुद्दा थे, क्योंकि अगर अमेरिका में प्रतिबंध से खतरे में पड़ी महिलाएं ट्रंप के खिलाफ वोट देतीं, तो वह हार जाते। जब हैरिस ने चुनौती स्वीकार की थी, तब यही स्थिति थी। लेकिन अब, यह मुद्दा कम जरूरी लगता है क्योंकि सात राज्य गर्भपात के पक्ष में कानून बना रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से, इनमें मिसौरी जैसे राज्य भी शामिल हैं, जहां ट्रंप ने जीत हासिल की है।

ऐसा लगता है कि अमेरिका ट्रम्प और गर्भपात दोनों का समर्थन करता है, जिसका वह विरोध करते हैं। ऐसे विरोधाभास ऐसे समाज में संभव हैं जहाँ रेखाएँ अब स्पष्ट रूप से नहीं खींची गई हैं, जहाँ यूनियन कार्यकर्ता और अप्रवासी रिपब्लिकन को वोट देने के लिए दशकों की परंपरा को तोड़ रहे हैं।

एक से ज़्यादा अमेरिकी विश्लेषकों का कहना है कि पोल विश्लेषण व्यर्थ है क्योंकि अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण काम किसी अश्वेत महिला को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा, जबकि ट्रम्प अभियान ने वादा किया था कि वह इसे "ठीक कर देगा", एक ऐसा संचार जो प्लंबर के कॉलिंग कार्ड की तरह दिल से काम करने वाला था, हैरिस का मुख्य संदेश नकारात्मक था: उसने जोर देकर कहा कि वह ट्रम्प नहीं है। वह खुशी और रोशनी के लिए खड़ी थी, जबकि ओल्ड ड्रेडफुल ने डर और अंधेरे का प्रचार किया। दुख की बात है कि अंधेरा पक्ष आमतौर पर जीतता है।

(ये मेरे निजी विचार हैं)
(ट्वीट्स @pratik_k)

'फ्यूस' की वजह से डेमोक्रेट्स को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है: बिडेन ने गाजा में नागरिकों के खिलाफ नेतन्याहू के युद्ध को हथियार और धन देना जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई थी, जिसे हैरिस ने बरकरार रखा होगा।
चुनाव से बहुत पहले, इजरायल से विनिवेश की मांग को लेकर अमेरिका भर में कैंपस में विरोध प्रदर्शन से पता चला था कि लोग इस बात को लेकर असहज थे कि उनके कर के पैसे का इस्तेमाल इजरायल के लिए किया जा रहा है।

अमेरिकी चुनावों में मतदाताओं पर नजर रखने से विभिन्न धारणाएं सामने आती हैं।
हालांकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन महामारी के बाद घरेलू बजट में सुधार नहीं हुआ है। अमेरिकी इस बात से परेशान हैं कि डेमोक्रेट्स को उनका दर्द समझ में नहीं आया।
ट्रम्प के लिए बढ़ता लैटिनो समर्थन अवसरों की रक्षा के बारे में है

नागरिकों, विशेषकर बच्चों पर बम से हमला किया। हैरिस ने इस बेचैनी की कोई कद्र नहीं की।

ट्रम्प के समर्थकों का मानना है कि एक व्यवसायी होने के नाते, वह युद्ध के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता वापस ले लेंगे क्योंकि वे व्यापार के लिए बुरे हैं। वे इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकते।

युद्ध अच्छे सम्पर्क वाले लोगों के लिए लाभदायक है।

ट्रम्प का अभियान आप्रवासी-विरोधी दुष्प्रचार की आधारशिला पर आधारित था, जिसने एक दशक से अधिक समय से लोगों को यह विश्वास दिला रखा है कि अमेरिका भर में कैंपस में विरोध प्रदर्शन से पता चला था कि लोग अवैध विदेशियों की भीड़ का सामना कर रहा है, जिनका कमजोर उदारवादियों द्वारा लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जा रहा है, कि वे जन्मजात अपराधी हैं, तथा ट्रम्प उनमें से लाखों लोगों को बाहर निकाल देंगे।

इनमें से कुछ भी सच नहीं है। हालाँकि भारत जैसे देशों से भी अप्रवासन बढ़ रहा है, लेकिन अवैध प्रवासियों की संख्या कहीं भी नहीं है।

संसद ने भाजपा को और अधिक उदार बना दिया है। हरियाणा में जीत संभवतः माता-पिता और उसके बच्चों के बीच एक नरमी का संकेत है । महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणाम मजबूती या अस्थिरता की प्रक्रिया हो सकते हैं।

हालांकि, अभी भी कई विभाजन के बिंदु छिपे हुए हैं। मणिपुर का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है, कुकी-मीतेई विभाजन - जो हिंदू-ईसाई विभाजन भी है - लगातार कठिन होता जा रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा और वक्फ विधेयक अत्यधिक विवादास्पद हो सकते हैं। संसदीय परिसीमन, जो जनगणना के बाद होगा, दोनों गठबंधनों में विभाजन पैदा करेगा। यूपी और बिहार अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए परिसीमन चाहेंगे, जबकि आंध्र, पूरा दक्षिण और पूर्व इसका कड़ा विरोध करेंगे। अगर परिसीमन को आगे बढ़ाया जाता है तो हम 60 के दशक के भाषा आंदोलन की पुनरावृत्ति की उम्मीद कर सकते हैं।

MAILBAG

WRITE TO: letters@newindianexpress.com

हरित सब्सिडी

संदर्भ: समाज को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकारों को प्राथमिकता (8 नवंबर) सरकार को सीएनजी वाहनों पर सब्सिडी देनी चाहिए।
कर्मचारियों को मेट्रो यात्रा भत्ता दिया जा सकता है।
उन्हें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ानी चाहिए।
प्रदूषण की रोकथाम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है।
नवनीत पाणिग्रही, रायगडा

रहने लायक नहीं शहर

स्वस्थ भारत एक बड़ा सवाल है क्योंकि वाहनों से निकलने वाले कार्बन के ऑक्साइड हवा को प्रदूषित करते हैं। बिना उपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट लगभग सभी नदियों में खुलेआम बहते हैं। अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो सभी शहर रहने लायक नहीं रह जाएंगे।

राजकुमार अरुलानंदम, पलायमकोट्टई

दक्षिण का समर्थन

संदर्भ: बेहतर दक्षिणी असुविधा के लिए गोलियाँ (नवंबर 8). जनसंख्या नियंत्रण लंबे समय से राष्ट्रीय अनिवार्यता रही है और दक्षिण भारत, विशेष रूप से केरल, जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए अथक प्रयास करने में सबसे आगे रहा है। विडंबना यह है कि इस प्रयास का प्रतिफल हाशिए पर जाने से मिलने वाला है। इन राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कानून जल्द ही बनाए जाने चाहिए।

एस माधवन थम्पी, हरिपद

सहकारी संघवाद

यह एक कड़वी सच्चाई है कि देश की आजादी के सात दशक बाद भी बीमारू राज्य अपनी स्थिति बनाए हुए हैं।
सभी सामाजिक विकास मापदंडों में अभी भी वांछित स्तर तक पहुंचना बाकी है। जैसा कि लेखक ने सही कहा है, यह सही समय है कि केंद्र राजस्व को समान रूप से साझा करने में दक्षिणी राज्यों की वास्तविक शिकायतों का समाधान करे ताकि घर्षण-मुक्त सहकारी संघवाद का पालन किया जा सके।

आर श्रीधरन, चेन्नई

बच्चों को शामिल करना

संदर्भ: माता-पिता मीडिया की अधिक उपयोगिता पर (8 नवंबर) पारिवारिक स्तर पर, माता-पिता और अभिभावक बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में उनके साथ शामिल हो सकते हैं और किताबें पढ़ने की संस्कृति विकसित कर सकते हैं। इस तरह, वे गैजेट के इस्तेमाल से ध्यान हटाकर अपने बचपन का उत्पादक उपयोग कर सकते हैं।

शक्ति सुप्रिता सिंह, होसुर

स्क्रीन की लत

भारत में माता-पिता बच्चों को भी मोबाइल इस्तेमाल करने और कार्टून देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि उन्हें अपने लिए समय मिल सके। इसके अलावा, दोनों माता-पिता ऑफिस की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं और एकल परिवार में बच्चों के प्रति देखभाल की कमी होती है। माता-पिता को अपने बच्चों को बढ़ते हुए समय में समय देना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें अधिक मनोवैज्ञानिक शक्ति और सुरक्षा मिलेगी।

श्रीनिवासन रमन, बेंगलुरु

न्यू इंडियन एक्सप्रेस
बोर्ड के अध्यक्ष: मनोज कुमार सोंथालिया संपादक: सांत्वना भट्टाचार्य
रेजिडेंट एडिटर (तेलंगाना) : टी कल्याण चक्रवर्ती* एक्सप्रेस पब्लिकेशन्स (मदुरै) प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आरके झुनझुनवाला द्वारा मुद्रित और प्रकाशित , एच.नं.6-3-1113/1, बीएसमक्ता लेन, सोमाजीगुडा, ग्रैंड काकतीय होटल के पास, पुंजागुट्टा, हैदराबाद - 500 016 और उनके द्वारा साक्षी प्रेस, प्लॉट नंबर डी-75 और ई-52, इंडस्ट्रियल एस्टेट (एपीआईई), बालानगर, मेडचल-मलकाजगिरी जिला, तेलंगाना में मुद्रित। हैदराबाद: खंड 48, संख्या 267 आरएनआई पंजी. संख्या 32179/77।
फोन : 040-23413908। * पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेदार। कॉपीराइट : एक्सप्रेस पब्लिकेशन्स (मदुरै) प्राइवेट लिमिटेड, सभी अधिकार सुरक्षित। पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा, पूर्णतः या आंशिक रूप से पुनरुत्पादन निषिद्ध है।

Machine Translated by Google

the pioneer
pinion

भारत 2047 का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसकी आकांक्षाएं हैं
मैं विकास में से एक बनने के लिए
खुले राष्ट्रों के लिए प्रयास करना, और जाहिर है, इसका मतलब होगा प्रयास करना, ईमानदारी से और सामूहिक रूप से अपने प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए। उम्मीद है, विकास में
भारत में किसी को भी मुफ्त की जरूरत नहीं होगी
राशन और मुफ्त में बांटी जाने वाली चीजें
वोट के लिए प्रलोभन
इतिहास बन जाएगा। यह भी
पीने योग्य पानी की निर्बाध उपलब्धता
पानी, स्वच्छ हवा, सभी मौसम
सिर पर छत और 'काम न करने' की स्थिति से मुक्ति।
भूख, खराब स्वास्थ्य और
कुपोषण उसकी आदत बन जाएगी-
टोरी! भारत में एक प्रणाली होगी
ऐसी शिक्षा जो सुनिश्चित करेगी
पहुँच और सफलता की समानता
बच्चों के लिए समान स्तर'
लुटियंस क्षेत्र और
झाबुआ गांव!
रहेगी
'आवश्यक स्वप्नलोक'!
इस दिशा में आगे बढ़ना आवश्यक है
निरर्थक से छुटकारा
हर किसी का सामाजिक-सांस्कृतिक बहिष्कार
हम एक ऐसे राष्ट्र की अपेक्षा करते हैं जो
है- घातक हथियारों का अल्पसंख्यक उत्पादन लंबे समय तक पीड़ित है,
बहुमत की चिंता! उनकी बिक्री और उनके विभिन्न पहलुओं का क्रमिक रूप से अध्ययन करने के बाद

सामाजिक एकता और धार्मिक
मैत्री - या सामाजिक और धार्मिक
सामंजस्य और मैत्री – भारत में,
इस बात को स्वीकार करने से कोई बच नहीं सकता
कि यह बहुत जटिल है
सांप्रदायिक वक्रता की पहेली जो विभिन्न प्रकार से
प्रतिरोधी है
नेक इरादे वाली पहल
इसे चिकना करें.
कुछ मानवीय मूल्य हैं जो
हर धर्म में समान, और
ये आधार बन सकते हैं
बिना किसी भेदभाव के भाईचारा मजबूत करने के लिए
किसी भी तरह से हस्तक्षेप करना
आस्था और धार्मिक प्रथाओं के तरीके। कट्टरपंथ,
आतंकवाद और कट्टरपंथ का वैश्विक उदय और
इसके परिणामस्वरूप अविश्वास, उत्पीड़न और
कट्टरता का विस्तार

एकांतवास निश्चित रूप से लोगों के बेहतर जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, चाहे कितने भी अधिक
गैजेट्स को उनके अनुसार उपलब्ध कराया जाता है
घरों.
दुःख की बात यह है कि यह बात बहुत स्पष्ट थी
सहस्राब्दी का वह मोड़ जब
आने वाले दिनों में चीजें और भी खराब हो जाएंगी
नेतृत्व के लिए इसे संभालना कठिन हो गया है,
और अस्तित्व का अस्तित्व
मानव जाति खतरे में पड़ जाएगी।
21वीं सदी का तीसरा दशक, मानवता और ग्रह
पृथ्वी चुनौतियों का सामना करती है

जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न समस्या
मनुष्य की तीव्र गिरावट-शिक्षा अब और नहीं
प्रकृति के साथ रिश्ते, और हमेशा के लिए एक
विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती हिंसा
रूपों और प्रारूपों। सांप्रदायिक वैमनस्य और
शांति स्थापना प्रयासों की सार्थकता
जिनके आर्थिक
हितों को अधिक समर्थक की आवश्यकता
अब कोई छुपी हुई बात नहीं रह गई
गुप्त।
तनाव, उथल-पुथल और
यह सब चिंता पैदा करता है
अब अनुभव किया जा रहा है
हर जगह, खास तौर पर
पश्चिम ने स्वीकार किया
शरणार्थियों और घुसपैठियों के साथ
खुले हाथों से, उनमें से कई हैं
अब अपनी नीतियों पर पछता रहे हैं
अतीत! अविश्वास का उदय
और आशंका बनती है
छिटपुट घटनाओं से भी बड़ा खतरा
हिंसा के उदाहरण जिनके
यूरोप में बढ़ रहे हैं
राष्ट्रों.
ये उदाहरण कुछ उदाहरण देते हैं
दुनिया के पहले के संकेत
आज के युवा और वे लोग
कौन सत्ता संभालेगा
कल!
भारत एक प्रमुख एशियाई राष्ट्र है
जो भारी बाढ़ से ग्रस्त है
अवैध प्रवासियों की संख्या, और अधिकांश
उन्हें कई राजनीतिक दलों से समर्थन मिलता
है। यह स्पष्ट है
यह समर्थन इस बात पर आधारित है
विशुद्ध रूप से सांप्रदायिक विचारों पर,
और निश्चित रूप से नहीं है
राष्ट्रीय हित में यह महत्वपूर्ण है।
वह नाजुक रिश्ता जो
हमेशा से अस्तित्व में था, और हमेशा से ही प्रज्वलित था
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
और विभाजन का कारण बना

भारत में सामाजिक एकता और धार्मिक
सौहार्द प्राप्त करना अभी भी असंभव बना
हुआ है।
द्वि-राष्ट्र सिद्धांत
एक बहुधा उद्धृत उद्धरण में विस्तारपूर्वक बताया गया है
सर सैयद अहमद का भाषण
खान ने अपने मेरठ भाषण में कहा
मार्च 1888 में दिया गया उनका भाषण
परिदृश्य का दृश्य जो हो सकता है
ब्रिटिशों के जाने के बाद उभरेंगे:
"क्या यह संभव है कि इनके तहत
परिस्थितियाँ दो राष्ट्र -
मुसलमान और
हिंदू - उसी पर बैठ सकते हैं
सिंहासन और बराबर रहना
शक्ति? निश्चित रूप से नहीं।"
सर सैयद सबसे महान लोगों में से एक थे
सम्मान और प्रशंसा का पात्र
मुस्लिम समुदाय के नेता जिन्होंने
आधुनिक शिक्षा के द्वार
और इसलिए, प्रबुद्ध मुस्लिम युवाओं ने उन्हें
पसंद किया
उपरोक्त का सार यह है कि
मुस्लिम समुदाय की प्रचलित भावनाओं का
प्रतिनिधित्व करता था, और इन्हें दूसरों द्वारा,
विशेष रूप से
जो लोग इन विचारों का विरोध करते थे
आधुनिक शिक्षा पर सर सैयद के विचार,
हालांकि, उन्होंने
दो राष्ट्रों का विचार!
इसके बाद, उसी व्याख्यान में सर सैयद ने
अपने विचारों को विस्तार से बताया।
आगे विचार: का सिद्धांत
एक प्रतिनिधि सरकार है
'कि यह एक सरकार है
राष्ट्र, और यह कि राष्ट्र
प्रश्न स्वयं पर शासन करता है
'यह लोगों और अपनी ज़मीन के मालिकाना हक के लिए है।'
इतना ही सरल: हो सकता है
द्वारा निर्वाचित किसी भी प्रतिनिधि सरकार
की कोई संभावना नहीं है

हिंदू और मुसलमान मिलकर हमेशा भारत पर
शासन करते रहे हैं, जिसमें न केवल राष्ट्र
शामिल हैं
हिंदुओं और मुसलमानों का लेकिन
अन्य लोगों को भी अपना राष्ट्र बनाना चाहिए।
भारतीय लोकतंत्र स्थापित करता है
सांप्रदायिक सद्भाव है
संभव है, और दोनों समुदाय समान रूप से
प्रबुद्ध हैं
साथ मिलाकर काम करना।
जबकि सर सैयद इसके हकदार हैं और
अपने भविष्यदर्शी दृष्टिकोण के लिए प्रशंसा प्राप्त करता है
आधुनिक शिक्षा पर दृष्टिकोण
और इसके उत्थान की सख्त जरूरत है
मुसलमानों, यह निश्चित रूप से
गंभीर विषय बना हुआ है
इस बात पर बहस हो रही है कि क्या उनकी परिभाषा
दोनों देशों के बीच हुए इस विवाद ने वहां के लोगों
की मानसिकता पर गहरा प्रभाव डाला।
समुदाय जो आज भी कायम है
आज।
द्वि-राष्ट्र का सिद्धांत
सिद्धांत अंततः दफन हो गया
बांग्लादेश का गठन,
और उभरते बहु-धार्मिक
यूरोप के समाजों में अगर ऐसा है तो
एक राष्ट्र जो प्रस्तुत कर सकता है
धार्मिक का एक कार्यात्मक मॉडल
एकता है यह भारत है, हिन्दू है
और भारत के मुसलमान.
कहीं और नहीं, समानता
सभी धर्मों की जड़ें इतनी गहरी हैं
विचार और कर्म में जैसा कि
प्राचीन भारतीय संस्कृति। यह
वंशानुगत संवादात्मक परंपरा द्वारा पुनर्जीवित
किया जा सकता है
ऐतिहासिक दृष्टि से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

(प्रोफेसर राजपूत यहां कार्यरत हैं) शिक्षा, सामाजिक एकता और धार्मिक सौहार्द। वह एक पीएमएमएल में अटल फेलो, नई दिल्ली; दृश्य व्यक्तिगत हैं)

(एआई) नया स्वरूप ले रहा है
कृत्रिम होशियारी में उद्योग
दुनिया भर में एआई का चलन बढ़ रहा है और
भारत भी इसका अपवाद नहीं है।
विकास के अवसरों, नए व्यापार मॉडल का
वादा करता है,
और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता
बढ़ेगी।
हालाँकि, इससे गंभीर चिंताएँ भी पैदा होती
हैं, विशेष रूप से
नौकरी की सुरक्षा के बारे में। यह है
यह बात श्रमिकों के लिए विशेष रूप से सत्य है
उन क्षेत्रों में जिन्हें अधिक माना जाता है
स्वचालन के प्रति संवेदनशील,
जैसे आईटी, प्रबंधन, लेखन और मनोरंजन।

आशावाद का द्वंद्व
एआई की क्षमता और चिंताएं
नौकरी विस्थापन एक है
भारत के लिए यह एक ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि
इन दृष्टिकोणों को संतुलित करने का प्रयास किया
गया है।
व्यापार क्षेत्र में, ए.आई.
मुख्य रूप से स्वचालित करने के लिए उपयोग किया जाता है
नियमित कार्यों को सुव्यवस्थित करना
प्रबंधन कार्य,
जिसके परिणामस्वरूप निर्णय लेने की
क्षमता में सुधार हुआ।
मध्य प्रबंधन भूमिकाएँ
विशेष रूप से असुरक्षित हैं
एआई के आने से स्वचालन
जटिल कार्य, जैसे आपूर्ति
श्रृंखला, डेटा और ग्राहक
प्रबंधन, न्यूनतम
मानवीय हस्तक्षेप। इन परिचालनों को
अनुकूलित करके, कंपनियाँ अधिक नियंत्रण
प्राप्त करती हैं

और दक्षता, लेकिन
बिचौलिया-प्रबंधन नौकरियों की संभावित
लागत.
इसी प्रकार, रचनात्मक उद्योग भी इसका
प्रभाव महसूस कर रहे हैं।
एआई। मॉडलिंग जैसे क्षेत्र,
विज्ञापन, आवाज अभिनय, और
सामग्री निर्माण को एआई-जनरेटेड ग्राफिक्स,
आवाज, से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना
करना पड़ रहा है।
और लिखित सामग्री। AI मॉडल अब काफी
उन्नत हो चुके हैं
यथार्थवादी चित्र बनाने के लिए,
सुसंगत लेखों का मसौदा तैयार करना, और
यहां तक कि मानव आवाजों की नकल भी कर सकते हैं,
मानवीय ज़रूरतों को कम करना
रचनात्मक कार्यों में भागीदारी।
इस बदलाव से विशेषज्ञों को लाभ होगा
इन क्षेत्रों को लेकर चिंता
भविष्य में रोजगार की संभावनाएं।
चुनौती अनुकूलन में है
इन परिवर्तनों का लाभ उठाते हुए
नौकरी छूटने की संभावना को कम करते हुए एआई के
लाभों पर चर्चा की गई।
भारत सरकार
के निहितार्थ को पहचानता है

रोजगार सृजन पर एआई का प्रभाव
सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं
इन चुनौतियों में से एक
मुख्य रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना है
मानव पूंजी विकास
और कार्यबल की तैयारी।
प्रधान जैसी पहल
मंत्री कौशल विकास योजना
(पीएमकेवीवाई) का उद्देश्य कौशल उन्नयन करना है
का महत्वपूर्ण हिस्सा
जनसंख्या, एआई पर जोर देते हुए,
मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स। इन पहलों का
उद्देश्य
नये रोजगार के अवसर पैदा करना
एआई में इसके प्रबंधन करते हुए
कार्यबल पर प्रभाव।
निजी क्षेत्र भी
इस प्रयास में योगदान दे रहे हैं।
प्रमुख भारतीय आईटी कंपनियां जैसे
जैसे इंफोसिस, विप्रो और टाटा
कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस),
व्यापक रूप से लॉन्च किया गया है
कौशल उन्नयन कार्यक्रम
अपने कर्मचारियों को इसके लिए तैयार करें
डिजिटल भविष्य.
उदाहरण के लिए, इंफोसिस ने
एक वैश्विक प्रशिक्षण विकसित किया
अपने कार्यबल की मदद के लिए पहल
प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखें
एआई और अन्य उभरते क्षेत्रों में
प्रौद्योगिकी। ये परिवर्तन-केंद्रित कार्यक्रम
एआई, क्लाउड में कौशल को प्राथमिकता दें
कंप्यूटिंग, और डेटा विज्ञान,
श्रमिकों को काम पर बने रहने के लिए तैयार करना
तेजी से विकसित हो रहे युग में प्रासंगिक
रोजगार का बाजार।
कुछ कंपनियां भी

एआई को एकीकृत करने के तरीके खोजना
जो बढ़ाते हैं, बजाय इसके कि
मानव उत्पादकता को प्रतिस्थापित करना।
एआई-संचालित में परिवर्तन
अर्थव्यवस्था के अपने लाभ हैं और
चुनौतियाँ। एक ओर, एआई
इससे आर्थिक विकास और नवाचार को
बढ़ावा मिलने तथा नए अवसर पैदा होने की
उम्मीद है।
दूसरी ओर, इससे नौकरी की सुरक्षा और
रोजगार के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं।
कार्य का पुनर्वितरण.
इन चुनौतियों का समाधान
सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है
श्रमिकों, व्यवसायों,
और सरकार।
श्रमिकों के लिए अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है
कुंजी, इच्छा की आवश्यकता है
नए कौशल हासिल करें और
बदलते कार्य परिवेश को अपनाएं। व्यवसायों
और
नीति निर्माताओं के अनुसार,
निवेश करने की साझा जिम्मेदारी
पुनः कौशलीकरण पहलों में और
ऐसी नौकरियाँ बनाएँ जो AI-संचालित
परिवर्तनों के साथ संरेखित हों। मानव
पूंजी को प्राथमिकता देकर और एक
सक्रिय दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर
कार्यबल विकास, भारत
लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार कर सकता है
एआई से, जबकि न्यूनतम
बड़े पैमाने पर नौकरी छिनने का खतरा।

(लेखक फैकल्टी-इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, वाधवानी हैं) सरकार के लिए केंद्र डिजिटल परिवर्तन; विचार व्यक्तिगत हैं)

महोदया - हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने,
अपने ऐतिहासिक फैसले में इसे बरकरार रखा है
उत्तर प्रदेश की संवैधानिक वैधता
मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए कहा कि
"यह असंवैधानिक था।"
मदरसा अधिनियम एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है
उत्तर प्रदेश में इन संस्थानों के लिए
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था
इस अधिनियम के तहत छात्रों के लिए इस्लाम और अन्य विषयों
का अध्ययन करना अनिवार्य कर दिया गया है।
आधुनिक विषयों को वैकल्पिक बना दिया गया,
जो कि स्वतंत्र अधिकार का उल्लंघन है
अनुच्छेद के तहत अनिवार्य शिक्षा
संविधान की धारा 21ए के अनुसार।
के शैक्षिक अधिकारों को कायम रखते हुए
उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय,
सुप्रीम कोर्ट ने अब पुष्टि कर दी है
राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को विनियमित कर सकता है ताकि मानकों
को सुनिश्चित किया जा सके
उत्कृष्टता। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि
अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अधिकार प्राप्त है
संविधान की स्थापना और
धार्मिक शिक्षा देने के लिए मदरसा का संचालन करना
या धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, अधिकार नहीं है
पूर्णतः। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक
चूंकि विनियमन उचित और तर्कसंगत है, इसलिए राज्य प्रशासन
को संभालने के अपने अधिकारों का उल्लंघन किए बिना
अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षा के पहलुओं को विनियमित कर
सकते हैं। साथ ही, एक महत्वपूर्ण कदम में, सुप्रीम कोर्ट ने एक
हिस्से को रद्द कर दिया है।
मदरसा अधिनियम की धारा 9 जो अनुमति देती है
बोर्ड को डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह इसके खिलाफ है
यूजीसी मानदंड। सामान्य तौर पर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
न केवल मदरसा के अधिकार की रक्षा करता है
छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, साथ ही
संवैधानिक सिद्धांतों की पुष्टि करता है कि
धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके शैक्षिक संस्थानों की सुरक्षा करना।

पी विक्टर सेल्वराज | तिरुनेलवेली

जाकिर हुसैन | कानपुर

महोदया - "ट्रम्प की जीत" के संबंध में
7 नवंबर को प्रकाशित "हाथ नीचे"।
कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे गंभीर मामले हों
उनके खिलाफ यहां तक कि उनकी उम्मीदवारी भी
पुष्टि नहीं हुई है, और उस स्थिति से
उम्मीदवारी सुरक्षित करने के लिए, दो जीवित
हत्या के प्रयास और बनना
राष्ट्रपति पद पर पुनः भारी बदलाव
और उपलब्धि, और यह एक होगा
ट्रम्प को एक कहावत-बाइल फ़ीनिक्स कहना अतिश्योक्ति
नहीं होगी। अब वह अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति चुने जाने
वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं।
हो सकता है कि वह सत्ता से बाहर हो गए हों
2020 से 2024 तक, लेकिन वह कभी भी इससे दूर नहीं रहे
अमेरिका की मानसिकता। या तो आप उससे प्यार करते हैं या
उससे नफरत करते हैं, लेकिन वह यहीं रहने वाला है।
उनका मुख्य चुनावी मुद्दा था-
अमेरिकी अर्थव्यवस्था, लुप्त होती मुद्रास्फीति, और अवैध
आव्रजन, और ये सब
अमेरिकी मतदाताओं के बीच इसका प्रभाव देखने को मिला है।
इस फैसले की व्याख्या नहीं की जा सकती
कमला हैरिस, यह जो के खिलाफ अधिक है
बिडेन प्रशासन। उसके पास मुश्किल से 100 थे
तैयारी, अभियान और लड़ाई के लिए दिन।
दुनिया को उम्मीद है कि ट्रम्प आगे बढ़ेंगे
बातचीत और युद्ध को समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाता है
यूक्रेन-रूस में.
ट्रम्प की नीतियों का उत्सुकता से स्वागत किया जाएगा
देखा क्योंकि अगर वह अमेरिका का अनुसरण करता है
पहली नीति, फिर कपड़ा-टाइल्स, फार्मा और ऑटोमोबाइल में
भारतीय निर्यातकों को लग सकता है झटका
चुटकी और H1-B नियम आगे बढ़ सकते हैं
कड़ा किया जाएगा, जिसका मतलब यह हो सकता है कि भारतीय
आईटी पेशेवरों और कंपनियों को
प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।

बाल गोविंद | नोएडा

महोदया - दिल्ली कांग्रेस ने एक महीने की 'न्याय यात्रा' शुरू की
8 नवंबर, इस लक्ष्य के साथ
निवासियों की चिंताओं और उनके लिए वकालत
सरकारी कार्रवाई। वरिष्ठ नेता जैसे
मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी,
और केसी वेणुगोपाल को आमंत्रित किया गया है
उस सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करें, जो
सभी 70 विधान सभा क्षेत्र।
यह जानकारी राज्य इकाई प्रमुख ने दी।
देवेन्द्र यादव कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे
स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी चिंताएं सुनें और सुझाव एकत्र
करें।
4 दिसंबर तक चलेगा अभियान
विभिन्न प्रकार के सामुदायिक सदस्यों को प्रदर्शित करना
और एक अग्रदूत के रूप में कार्य करना
आगामी विधानसभा चुनाव।

नेहा तोमर | उज्जैन

Machine Translated by Google

the pioneer

analysis

प्रथमस्तंभ

ट्रम्प की व्हाइट में वापसी 2024 में सदन में उथल-पुथल मचेगी के भविष्य के बारे में सवालों का नाटो, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, सहयोगियों के साथ संबंध, और यूक्रेन युद्ध की दिशा। ट्रम्प के पिछले कार्यकाल में यूक्रेन युद्ध की दिशा में एक मजबूत झुकाव दिखा था।
"अमेरिका फर्स्ट" नीतियां, अक्सर दीर्घकालिक वैश्विक गठबंधनों को चुनौती देती हैं
और बहुपक्षीय प्रतिबद्धताएँ। इसलिए, ट्रम्प के नेतृत्व वाली प्रेसीडेंसी भू-राजनीतिक परिदृश्य को नाटकीय रूप से बदल सकती है, नाटो जैसे सहयोगियों को अनिश्चितता में छोड़ सकती है, अमेरिका की आर्थिक नीतियों को पुनः उन्मुख कर सकती है, भारत के संतुलन कार्य का परीक्षण कर सकती है, और पुनर्परिभाषित कर सकती है
चीन संबंध.

नाटो का भविष्य: धीरज या क्षरण? नाटो, आधारशिला 1949 से पश्चिमी रक्षा, एक के रूप में खड़ा है
ट्रम्प के साथ अटकलों का केंद्रीय विषय वापसी। अपने राष्ट्रपति काल के दौरान, ट्रम्प गठबंधन की प्रासंगिकता, विशेषकर इसके वित्तीय दायित्वों पर सवाल उठाया, यहां तक कि
इसका मतलब है कि अमेरिका संभवतः वापस लौट सकता है
सदस्यों ने अपना उचित योगदान नहीं दिया
साझा करें।" इस रुख से बेचैनी पैदा हुई
नाटो सहयोगियों के बीच, जो अमेरिका पर निर्भर हैं
महत्वपूर्ण रक्षा संसाधनों के लिए, विशेष रूप से रूसी आक्रामकता के बीच।
ट्रम्प ने पदभार संभाला, उनका दृष्टिकोण नाटो को और भी अधिक साहसिक पुनर्संतुलन से गुजरना पड़ सकता है। यूरोपीय रक्षा संरचना,
अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर होने के कारण, इसका सामना करना पड़ सकता है
महत्वपूर्ण रणनीतिक और वित्तीय बदलाव, संभवतः यूरोपीय शक्तियों को प्रेरित करना अधिक रक्षा जिम्मेदारियां लें।
नाटो के लिए अमेरिकी सैन्य और वित्तीय सहायता में कटौती से विरोधी ताकतों, खासकर रूस का हौसला बढ़ सकता है।

अमेरिकी प्रतिबद्धता का मतलब पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए कमज़ोरी हो सकता है
पोलैंड और बाल्टिक राज्य, जो इस पर निर्भर हैं
नाटो की सुरक्षा छत्रछाया पर जवाबी कार्रवाई
रूसी विस्तारवाद का प्रभाव
इसलिए, नाटो काफी हद तक इस पर निर्भर करता है
ट्रम्प के रणनीतिक निर्णय
गठबंधन का बोझ साझा करना और उनकी क्षमता यूरोपीय सहयोगियों को बढ़ाने के लिए राजी करना उनके रक्षा व्यय.

वैश्विक दांव: एक निर्णायक चौराहा

ट्रम्प की वापसी के निहितार्थ विस्तृत होंगे अमेरिका की सीमाओं से कहीं आगे। चीन के साथ रूस की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं और वैश्विक सुरक्षा गतिशीलता को आकार देने में ट्रम्प की भूमिका विदेश नीति के विकल्प महत्वपूर्ण होंगे परिणाम। उनका लेन-देन संबंधी दृष्टिकोण
गठबंधनों के लिए, "अमेरिका पहले" अर्थशास्त्र,
और रक्षा पर अप्रत्याशित रुख
गठबंधन अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नया आकार दे सकते हैं, पारंपरिक सहयोगी अमेरिकी समर्थन पर अपनी निर्भरता पर पुनर्विचार कर सकते हैं। नाटो की प्रतिबद्धताओं को संभालने में उनका योगदान,

यूक्रेन युद्ध और वैश्विक संबंधों
भारत और चीन जैसी ताकतें तय करेंगी
पश्चिमी प्रभाव की भविष्य की स्थिरता
और वैश्विक शक्ति संतुलन।

चीन और भारत: प्रतिस्पर्धी शक्तियां:
ट्रम्प के शासन में अमेरिका-चीन संबंध
प्रतिद्वंद्विता द्वारा परिभाषित एक पर वापस लौट सकता है, जैसे उन्होंने लगातार सख्त रुख की वकालत की है
चीन के व्यापार व्यवहार और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं पर ट्रम्प का रुख सख्त हो सकता है।
चीनी वस्तुओं पर टैरिफ लगाना और
अमेरिका में काम कर रही चीनी कंपनियों पर और भी कड़े प्रतिबंध, जिसका उद्देश्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाना है।
प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में चीन का प्रभाव
और विनिर्माण। भारत के लिए, ट्रम्प की वापसी में अवसरों का मिश्रण होता है और
चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनका प्रशासन उल्लेखनीय रूप से भारत के प्रति गर्मजोशी दिखाते हुए, "2+2" वार्ता जैसे समझौतों के माध्यम से मजबूत आर्थिक और रक्षा संबंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
चीन का मुकाबला करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा सकता है
भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनाएं, खास तौर पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में। ट्रंप शायद
भारत को अधिक रक्षा सहयोग की पेशकश करें या

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संभावित रूप से
भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत करना
एशिया में आर्थिक स्थिति.
हालाँकि, भारत का संतुलनकारी कार्य
अमेरिका और रूस के बीच-
भारत के रक्षा संबंधों को देखते हुए
मास्को—जटिल हो सकता है अगर
ट्रम्प ने इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया
यूक्रेन संघर्ष। रूस-यूक्रेन मुद्दे पर भारत की सावधानीपूर्ण तटस्थता जांच को आकर्षित कर सकती है, ट्रम्प को संभवतः उम्मीद है कि

अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी के साथ अधिक समन्वय प्राथमिकताएं.

आर्थिक नतीजे-अमेरिका का वित्तीय भविष्य: ट्रम्प का आर्थिक दृष्टिकोण पारंपरिक रूप से संरक्षणवाद की ओर झुकाव,
नौकरियों को बहाल करने, व्यापार सौदों पर फिर से बातचीत करने और सीमित करने पर ध्यान केंद्रित करना
विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता
जंजीरें। यह आर्थिक दर्शन
अगर वह वापस लौट आए तो उन्हें फिर से ताकत मिल सकती है
ओवल ऑफिस में, संभावित रूप से
व्यापार, मुद्रास्फीति पर प्रभाव,
और अमेरिका में रोजगार।
संभावित परिणाम यह है कि चीन पर टैरिफ जारी रहेगा या और भी तीव्र हो जाएगा, जिसका उद्देश्य अमेरिकी प्रतिबंधों को कम करना है।
अमेरिकी व्यापार घाटा। हालाँकि,
इन टैरिफों ने ऐतिहासिक रूप से योगदान दिया
अमेरिकियों के लिए लागत में वृद्धि
उपभोक्ताओं और व्यवसायों,
आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं और मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ रहा है।
एक और संरक्षणवादी प्रयास हो सकता है
समान परिणाम होते हैं, मजबूरन
कंपनियों के दबाव के कारण अमेरिकियों को रोजमर्रा के उत्पादों के लिए अधिक भुगतान करना पड़ेगा
टैरिफ लागत.
ट्रम्प का "अमेरिका फर्स्ट" दृष्टिकोण
इसका मतलब कर सुधार भी हो सकता है या
कंपनियों को घरेलू स्तर पर विनिर्माण करने के लिए प्रोत्साहन।
रीशोरिंग से नौकरियाँ पैदा हो सकती हैं लेकिन उत्पादन भी बढ़ेगा
उच्च मजदूरी के कारण लागत में वृद्धि होगी, जिससे अमेरिकी सामान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी बन जायेंगे।
इसके अलावा, एक कठोर रुख
व्यापार संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है
आर्थिक रूप से एकीकृत सहयोगी,

ट्रम्प द्वारा व्यापार की मांग के साथ
अमेरिका के लिए उचित समझी जाने वाली शर्तें।
इससे मौजूदा समझौते बाधित हो सकते हैं और वैश्विक स्तर पर नए आर्थिक तनाव पैदा हो सकते हैं।

दबाव में सहयोगी: A
वैश्विक व्यवस्था का पुनर्निर्माण?
ट्रम्प प्रशासन का
गठबंधन के प्रति दृष्टिकोण अक्सर
अप्रत्याशित, कुछ नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हुए
दूसरों को अलग-थलग करना। उनकी "लेन-देन वाली" विदेश नीति शैली को प्राथमिकता दी गई
दीर्घकालिक साझेदारियों पर तत्काल लाभ, जिसके परिणामस्वरूप
सहयोगियों के साथ मतभेद। अब ट्रम्प की वापसी का मतलब तीव्र हो सकता है
सहयोगियों पर प्राथमिकता तय करने का दबाव
बहुपक्षीय समझौतों की अपेक्षा द्विपक्षीय समझौतों को प्राथमिकता दी गई
सहयोग, यूरोपीय संघ, जापान के साथ संबंधों में परिवर्तन,
दक्षिण कोरिया और अन्य सहयोगी देश।
यूरोप के प्रति ट्रम्प की नीतियाँ
की मांग में प्रकट हो सकता है
अनुकूल व्यापार सौदे या रक्षा खर्च पर रियायतें।

जापान और दक्षिण कोरिया के लिए उनका फिर से उभरना खतरे को और बढ़ाने वाला संकेत हो सकता है।
अधिक योगदान देने का दबाव
उनकी रक्षा व्यवस्था, उनके सुरक्षा गठबंधनों का संभावित परीक्षण
अमेरिका के साथ भी। यहां तक कि मध्य पूर्वी
सऊदी अरब जैसे सहयोगी देशों को इसका सामना करना पड़ सकता है
ट्रम्प के नेतृत्व में नई उम्मीदें
प्रशासन की अधिक रुचि
अमेरिका पर विशिष्ट, ठोस रिटर्न।
अमूर्त प्रतिबद्धताओं के बजाय समर्थन।

यूक्रेन युद्ध: एक विखंडित सर्वसम्मति?

ट्रम्प की व्हाइट हाउस में वापसी
एक विकल्प पेश किया जा सकता है
यूक्रेन संघर्ष पर पश्चिमी दृष्टिकोण यूक्रेन के लिए बड़े पैमाने पर एकजुट समर्थन से अलग है।

ट्रम्प ने खुले तौर पर उच्च न्यायालय की आलोचना की है।
यूक्रेन को अमेरिकी वित्तीय सहायता से यह संकेत मिलता है
कि यूरोपीय संघ यूक्रेन को वित्तीय सहायता दे रहा है।
देशों को अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए
भार।
इस संघर्ष में अरबों डॉलर की अमेरिकी सहायता खर्च हो जाने के कारण, उन्होंने कहा

अमेरिका की भागीदारी को कम करने का विकल्प चुन सकता है, जिससे दबाव बढ़ेगा
यूरोपीय सहयोगियों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन और संभावित रूप से सम्मोहक
यूक्रेन से वार्ता पर विचार करने को कहा।
ट्रम्प के नेतृत्व वाला प्रशासन शायद
टकराव से बचने का प्रयास करें
रूस, जो कमजोर हो सकता है
युद्ध के मैदान में यूक्रेन की स्थिति। ट्रम्प का टकराव की बजाय कूटनीति पर ज़ोर

मॉस्को नाटो की एकजुटता को प्रभावित कर सकता है,
कुछ सदस्य संभावित रूप से एक मजबूत रुख के पक्ष में हैं

रूस के खिलाफ जबकि अमेरिका
यह एक अधिक हस्तक्षेप रहित दृष्टिकोण है।
यह परिदृश्य रूस को प्रोत्साहित कर सकता है,
जो अमेरिकी नेतृत्व में बदलाव को अधिक प्रयास करने के अवसर के रूप में देख सकते हैं
यूक्रेन में आक्रामक रणनीति या
यहां तक कि दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास भी
पूर्व सोवियत क्षेत्र।
इसलिए, यूक्रेन युद्ध का भाग्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा
ट्रम्प का दृष्टिकोण - चाहे वह
अमेरिका का समर्थन बनाए रखने का विकल्प चुनता है
कीव के लिए या संभावित रूप से बातचीत को प्रोत्साहित करने की ओर बढ़ना
संघर्ष का रुख बदलना
और अमेरिका-रूस संबंधों के एक नए युग का संकेत दे रहा है। कई मायनों में,
ट्रम्प का राष्ट्रपति बनना इस बात का संकेत होगा कि
अमेरिकी विदेश नीति का पुनर्मूल्यांकन
नीति, अपने ब्रांड की ओर लौट रही है
राष्ट्रवाद और व्यावहारिकता का मिश्रण।

हालाँकि, इस दृष्टिकोण से सहयोगियों के साथ घर्षण उत्पन्न हो सकता है,
वैश्विक अर्थव्यवस्था और चुनौतियां
मौजूदा राजनयिक मानदंडों का उल्लंघन किया गया है।
क्या यह मार्ग किसी को बढ़ावा देगा?
अधिक मजबूत, अधिक आत्मनिर्भर अमेरिका या
पृथक एवं खंडित विश्व
अभी आदेश आना बाकी है।
ट्रम्प दूसरे स्थान पर आने को तैयार हैं
उनकी वापसी से अमेरिकी सीमाएँ पुनः परिभाषित होने का वादा किया गया है
नेतृत्व और प्रभाव
तेजी से बहुध्रुवीय होती जा रही दुनिया।
(लेखक रणनीतिक मामलों के विश्लेषक और राजनीतिक विश्लेषक हैं।
शिमला; विचार निजी हैं)

मैं भारत में बुजुर्गों की आबादी काफी अधिक है,
लगभग 138
60 वर्ष से अधिक आयु के दस लाख लोग
ऊपर, जिसमें अधिक शामिल हैं
10 करोड़ से अधिक व्यक्ति
70 वर्ष की आयु. यह खंड
जनसंख्या का अद्वितीय हिस्सा है
और स्वास्थ्य सेवा पर दबाव
जैसे-जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, उनकी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं।
तेजी से संवेदनशील होते जा रहे हैं
कई पुरानी स्थितियों के लिए जिनके लिए
विशेष उपचार की आवश्यकता होती है
देखभाल और लगातार चिकित्सा
ध्यान दें।
अनुदैर्ध्य उम्र बढ़ने का अध्ययन
भारत का (LASI), हर चौथा
60 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय और
हर पांचवा भारतीय 45 वर्ष से अधिक
वर्षों से खराब स्वास्थ्य की रिपोर्ट है।
इसके अतिरिक्त, 75 प्रतिशत
बुजुर्गों में एक या अधिक
दीर्घकालिक बीमारियाँ, और 40 प्रतिशत
100 प्रतिशत विकलांगता का अनुभव करते हैं।
4 में से 1 बुजुर्ग व्यक्ति को यह बीमारी है

बहु-रुग्णता, मधुमेह और कैंसर की दरें बढ़ रही हैं,
विशेषकर शहरी क्षेत्रों में।
ग्लोबल हेल्थ के अनुसार
2019 के गैर-संचारी रोगों के आंकड़ों का अनुमान

इस्केमिक हृदय रोग के रूप में,
स्ट्रोक और मधुमेह विकलांगता-समायोजित
जीवन वर्ष (डीएएलवाईएस) के प्रमुख कारण हैं
व्यक्तियों के बीच खो गया
60. यह विशेषज्ञता की बढ़ती आवश्यकता को उजागर करता है
उपचार और सुसंगत

उम्र से संबंधित विकारों के लिए चिकित्सा ध्यान।
उच्च रक्तचाप की व्यापकता,
बुजुर्गों में हृदय रोग और श्वसन संबंधी समस्याएं

अस्पताल की आवश्यकता बढ़ जाती है
पिटालाइज़ेशन और विशेष
स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर अत्यधिक दबाव डालना
और बुजुर्गों और उनके परिवारों को परेशान कर रहा है।
इससे जुड़ा वित्तीय बोझ
बार-बार अस्पताल जाना और उपचार करवाना एक बड़ी चुनौती है।

इसके अलावा, भारत की वर्तमान चिकित्सा
मुद्रास्फीति दर, पर खड़ी
लगभग 14 प्रतिशत
जिससे स्वास्थ्य देखभाल की कठिनाइयां और भी बदतर हो जाती हैं
बुजुर्गों के लिए बढ़ती चिकित्सा लागत, जिसमें

अस्पताल में भर्ती होना, डॉक्टर से परामर्श और दवाइयाँ,
इसे और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाएं

इस कमजोर के लिए langing
जनसंख्या को आवश्यक देखभाल तक पहुंच बनाने में मदद करना। मुद्रास्फीति, युग्मित
जीवनयापन की उच्च लागत के साथ,
कई बुजुर्ग व्यक्तियों को खर्च वहन करने में संघर्ष करना पड़ता है
यहां तक कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं भी।

इसके अतिरिक्त, चिकित्सा के रूप में
मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है,
बीमा कम्पनियाँ
अधिक कवर करने के लिए मजबूर
चिकित्सा प्रक्रियाओं और उपचारों के लिए खर्च। यह,
बदले में, परिणाम में वृद्धि हुई
पॉलिसीधारकों के लिए प्रीमियम.
कई बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए, ये उच्च बीमा योजनाएं
लागत वित्तीय बोझ को बढ़ाती है, जिससे
आर्थिक संकट गहराता है।
समग्र स्वास्थ्य देखभाल सामर्थ्य संकट।

जबकि इसका विस्तार
आयुष्मान भारत योजना
मंत्री जन आरोग्य योजना

(एबी पीएम-जेएवाई) एक महत्वपूर्ण है
सुधार की ओर कदम
स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, कवरिंग
4.5 करोड़ परिवारों से अतिरिक्त 6 करोड़
व्यक्ति, तथा वरिष्ठ नागरिकों पर ध्यान केन्द्रित करना
70 वर्ष या उससे अधिक आयु के कई लोग
चुनौतियां बनी हुई हैं
बीमा बाज़ार. वर्तमान
बीमा उत्पाद सीमित हैं, विशेष रूप से 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए। पहले से
मौजूद बीमारियाँ (पीईडी) जैसे

जैसे मधुमेह, हृदय रोग
स्थितियाँ, और कैंसर अक्सर
प्रतीक्षा अवधि का परिणाम या
कवरेज से साफ इनकार।
इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा
प्रीमियम भी बढ़ाए गए हैं।
काफी अधिक होने के कारण
इससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिम,
बीमा कई लोगों के लिए वहनीय नहीं रह गया है।
पीईडी पर आधारित बीमा,
अत्यधिक के साथ संयुक्त
प्रीमियम, अक्सर बल
बुजुर्ग व्यक्तियों पर भरोसा करें
व्यक्तिगत बचत या सरकारी योजनाओं को छोड़कर,
पर्याप्त वित्तीय सहायता के बिना
गंभीर बीमारियों से सुरक्षा
बीमारियाँ.
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार
राष्ट्र जनसंख्या कोष
(यूएनएफपीए), भारत के बुजुर्ग
जनसंख्या का अनुमान है
2050 तक यह संख्या लगभग तीन गुनी होकर
320 मिलियन तक पहुंच जाएगी।

ग्राफिक बदलाव की आवश्यकता होगी
देश के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की रक्षा के
लिए अधिक व्यापक समाधान

नागरिकों। जबकि पीएम-जेएवाई का विस्तार
स्वागत योग्य है
विकास, यह नहीं है
व्यापक रूप से पूरी तरह से संबोधित करें
भारत की वृद्धावस्था संबंधी आवश्यकताओं
उम्र बढ़ने की आबादी।
एबी पीएम-जेएवाई मुख्य रूप से इनपेशेंट
देखभाल तक ही सीमित है।
योजना में बाह्य-रोगी सेवाएं शामिल नहीं हैं, जो

काफ़ी हद तक हिस्सा
स्वास्थ्य देखभाल लागत. अनुसंधान में
प्रकाशित
अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ
निवारक चिकित्सा से पता चलता है
बाह्य रोगी देखभाल खाते
40-80 प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए
भारत में व्यय.
परिणामस्वरूप, यहां तक कि
बढ़ी हुई बीमा कवरेज-आयु के कारण, कई व्यक्तियों को

ऐसे उपचारों के लिए जेब से खर्च करना जारी
रखना जिनकी आवश्यकता नहीं है

अस्पताल में भर्ती.
इसकी तत्काल आवश्यकता है
कवरेज को विस्तारित करके इसमें शामिल करें
दीर्घकालिक जैसी सेवाएँ
देखभाल, बाह्य रोगी सेवाएं,
मानसिक स्वास्थ्य सहायता, उपशामक
देखभाल और पुनर्वास, जो आवश्यक हैं

की भलाई सुनिश्चित करना
बुजुर्ग।
इसके अतिरिक्त, सरकार को वित्तीय बाधाओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

स्वास्थ्य सेवा, जैसे उच्च
बीमा प्रीमियम, और
का समावेश सुनिश्चित करना
लंबे समय तक बिना पीईडी कवरेज
प्रतीक्षा अवधि.
(लेखक एनिरा में वरिष्ठ सलाहकार हैं)
परामर्श; विचार हैं
निजी)